



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03092021-229413  
CG-DL-E-03092021-229413

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1  
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 249]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 3, 2021/भाद्र 12, 1943

No. 249]

NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 3, 2021/BHADRA 12, 1943

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार और उपचार महानिदेशालय)

अधिसूचना

अंतिम जांच परिणाम

नई दिल्ली, 3 सितम्बर, 2021

मामला सं. एडीडी-ओआई-27/2020

**विषय:** चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "विटामिन सी" के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच।

**फा. सं. 6/32/2020-डीजीटीआर.**—समय-समय पर यथा संशोधित सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 (जिसे आगे "अधिनियम" भी कहा गया है) और उसकी समय-समय पर यथा संशोधित सीमा प्रशुल्क (पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, मूल्यांकन एवं संग्रहण तथा क्षति के निर्धारण के लिए) नियमावली, 1995 (जिसे आगे "नियमावली" अथवा "पाटनरोधी नियमावली" भी कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए;

**क. मामले की पृष्ठभूमि**

1. मैसर्स बजाज हेल्थकेयर लिमिटेड (जिसे आगे "आवेदक" अथवा "घरेलू उद्योग" अथवा "याचिकाकर्ता" भी कहा गया है) ने चीन जनवादी गणराज्य (जिसे आगे यहां "संबद्ध देश" भी कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित विटामिन सी (जिसे आगे पीयूसी अथवा संबद्ध सामान अथवा विचाराधीन उत्पाद भी कहा गया है) के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच शुरू किए जाने और उन पर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के लिए समय-समय पर यथासंशोधित सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 (जिसे आगे "अधिनियम" भी कहा गया है) और समय-समय पर यथासंशोधित सीमा प्रशुल्क (पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, मूल्यांकन एवं संग्रहण

तथा क्षति के निर्धारण के लिए) नियमावली, 1995 (जिसे यहां आगे "पाटनरोधी नियमावली" अथवा "नियमावली" भी कहा गया है) के अनुसार, निर्दिष्ट प्राधिकारी के समक्ष एक आवेदन पत्र दायर किया। मैसर्स अमोली ऑर्गेनिक प्रा. लि., मैसर्स रेकोन डायग्नोस्टिक्स प्रा. लि. और मैसर्स एसआर बायोकेम संबद्ध सामानों के अन्य घरेलू उत्पादक हैं जिन्होंने आवेदक द्वारा दायर आवेदन पत्र का समर्थन किया है।

2. प्राधिकारी ने आवेदक द्वारा प्रस्तुत पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर, संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध सामानों के तथाकथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव निर्धारित करने के लिए और पाटनरोधी शुल्क (एडीडी) की राशि, जो यदि लगाई जाए, और घरेलू उद्योग को तथाकथित क्षति समाप्ति करने के लिए पर्याप्त होगी, की सिफारिश करने के लिए नियमावली के नियम 5 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क के अनुसार संबद्ध जांच शुरू करते हुए भारत के राजपत्र में प्रकाशित दिनांक 4 सितंबर, 2020 को एक सार्वजनिक सूचना जारी की।

## ख. प्रक्रिया

3. संबद्ध जांच के संबंध में प्राधिकारी द्वारा नीचे वर्णित प्रक्रिया अपनाई गई है:

- क. प्राधिकारी ने उपर्युक्त नियम 5 के उप नियम 5 के अनुसार, जांच शुरू करने की कार्यवाही से पूर्व वर्तमान आवेदन पत्र प्राप्त होने के संबंध में भारत में संबद्ध देश के दूतावास को अधिसूचित किया।
- ख. प्राधिकारी ने संबद्ध देश से संबद्ध सामानों के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच शुरू करते हुए भारत के राजपत्र असाधारण में प्रकाशित दिनांक 4 सितंबर, 2020 की सार्वजनिक सूचना जारी की।
- ग. भारत में संबद्ध देश के दूतावास को नियमावली के नियम 6(2) के अनुसार जांच की शुरुआत के संबंध में सूचित किया गया था। प्राधिकारी ने संबद्ध देश की सरकार को उसके दूतावास के माध्यम से, संबद्ध देश के ज्ञात उत्पादकों/ निर्यातकों, ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं और घरेलू उद्योग तथा आवेदक द्वारा उपलब्ध कराए गए पतों के अनुसार अन्य घरेलू उत्पादकों को जांच की शुरुआत की अधिसूचना की प्रति भेजी और उनसे अनुरोध किया कि वे निर्धारित समय-सीमा के भीतर लिखित में अपने ज्ञात विचार दें।
- घ. प्राधिकारी ने उपर्युक्त नियमावली के नियम 6(3) के अनुसार ज्ञात उत्पादकों/ निर्यातकों तथा संबद्ध देश की सरकार को भारत में उसके दूतावास के माध्यम से आवेदन पत्र के अगोपनीय रूपांतर की प्रति उपलब्ध करायी। आवेदन पत्र के अगोपनीय रूपांतर की प्रति सार्वजनिक फाइल में भी उपलब्ध कराई गई थी और अनुरोध करने पर अन्य हितबद्ध पक्षकारों को भी उपलब्ध कराई गई थी।
- ङ. प्राधिकारी ने संबद्ध देश के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातक, भारत में ज्ञात आयातकों/ प्रयोक्ताओं, अन्य भारतीय उत्पादकों और आवेदक द्वारा उपलब्ध कराए गए पतों के अनुसार, घरेलू उद्योग को भी सूचना की प्रति भेजी तथा उनसे अनुरोध किया कि वे जांच की शुरुआत की अधिसूचना के 30 दिन के भीतर लिखित में अपने ज्ञात विचार दें। प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार संगत सूचना मंगाने के लिए निम्नलिखित ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को निर्यातक प्रश्नावली भेजी:
  - i. मैसर्स हांगझोऊ थिंक केमिकल कं. लि.
  - ii. मैसर्स सीएसपीसी वेइशेंग फार्मास्युटिकल (शीजियाझुआंग) कं. लि.
  - iii. मैसर्स नॉर्थ ईस्ट फार्मास्युटिकल ग्रुप कं. लि.
  - iv. मैसर्स बैरेंटज (शंघाई) कामर्शियल एंड ट्रेडिंग कं. लि.
  - v. मैसर्स सिनोराइट इंटरनेशनल ट्रेड कं. लि.
  - vi. मैसर्स डीएसएम न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट्स एशिया पसिफिक
- च. भारत में संबद्ध देश के दूतावास से यह भी अनुरोध किया गया था कि वे चीन जन. गण. के निर्यातकों/उत्पादकों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर देने की सलाह दें। उत्पादकों/निर्यातकों को भेजे गए पत्र और प्रश्नावली की प्रति भी संबद्ध देश के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों के नामों और पतों सहित उन्हें भेजी गई थी।

- छ. संबद्ध जांच की शुरुआत के उत्तर में संबद्ध देश के निम्नलिखित निर्यातकों/ उत्पादकों ने निर्यात प्रश्नावली के उत्तर दायर किए:
- मैसर्स सीएसपीसी वीशेंग फार्मास्युटिकल (शीजियाझुआंग) कं. लि.
  - मैसर्स शानडोंग लूवी फार्मास्युटिकल कं. लि.
- ज. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार आवश्यक सूचना मंगाने के लिए भारत में संबद्ध सामानों के निम्नलिखित ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं को प्रश्नावली भेजी:
- मैसर्स सिपला लिमिटेड
  - मैसर्स ग्लोबल एक्जिम
  - मैसर्स वेल्यू ट्री इंडिया प्रा. लि.
  - मैसर्स डीएसएस न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट्स इंडिया प्रा. लि.
  - मैसर्स प्लानेट साइंस
  - मैसर्स कांफियांस लाइफ साइसेंज प्रा. लि.
  - मैसर्स मैक्सहील फार्मास्युटिकल्स लि.
  - मैसर्स पल्स फार्मास्युटिकल्स
- झ. संबद्ध जांच की शुरुआत के उत्तर में निम्नलिखित आयातक/उपभोक्ता ने प्रश्नावली का उत्तर दायर किया:
- मैसर्स सेवेंतिलाल एंड संस
  - मैसर्स अबॉट हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड
- ञ. प्राधिकारी ने जांच की शुरुआत की सूचना निम्नलिखित उत्पादकों को इस अनुरोध के साथ जांच की शुरुआत के संबंध में उन्हें सूचित करते हुए भेजी कि वे निर्धारित स्वरूप और तरीके में प्राधिकारी को संगत सूचना दें।
- मैसर्स अमोली ऑर्गेनिक्स प्रा. लि.
  - मैसर्स रेकोन ऑर्गेनिक्स प्रा. लि.
  - मैसर्स एस. आर. बायो केम
- ट. किसी भी अन्य घरेलू उत्पादक ने वर्तमान जांच में भाग नहीं लिया है।
- ठ. संबद्ध जांच की शुरुआत के उत्तर में निम्नलिखित ने प्राधिकारी को अनुरोध दायर किए:
- बल्क ड्रग्स एंड एलाइड डीलर एसोसिएशन
  - संदीप ऑर्गेनिक्स प्राइवेट लिमिटेड
- ड. प्राधिकारी ने विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य का अगोपनीय रूपांतर हितबद्ध पक्षकारों के लिए ई-मेल के माध्यम से ई-फाइल के रूप में उपलब्ध कराया।
- ढ. वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआईएंडएस) से पिछले तीन वर्षों और जांच की अवधि के लिए संबद्ध सामानों के आयातों के लेन-देन वार ब्यौरे उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था जो प्राधिकारी को प्राप्त हो गए थे। प्राधिकारी ने आयातों की मात्रा के परिकलन और लेन-देनों की उचित जांच के बाद उसके विश्लेषण के लिए डीजीसीआईएंडएस के आंकड़ों पर विश्वास किया है।
- ण. क्षति रहित कीमत (एनआईपी) सामान्यतया स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों (जीएएपी) और नियमावली के अनुबंध-III के आधार पर घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत सूचना के आधार पर भारत में संबद्ध सामानों की इष्टतम उत्पादन लागत और निर्माण एवं बिक्री लागत के आधार पर निकाली गई है ताकि यह सुनिश्चित

किया जा सके कि क्या पाटन मार्जिन से कम पाटनरोधी शुल्क घरेलू उद्योग को क्षति समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगा।

- त. विश्व भर में कोविड-19 फैलने के कारण और परिणामस्वरूप भारत सहित विभिन्न देशों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के कारण सूचना के स्थल सत्यापन के माध्यम से प्राधिकारी द्वारा वास्तविक निरीक्षण नहीं किया गया था। आवेदक/ उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा दी गई सूचना की सुदूर परस्पर जांच/डेस्क सत्यापन आवश्यक समझी गई सीमा तक प्राधिकारी द्वारा किया गया था। आवश्यक समझी गई सीमा तक आवश्यक संशोधन के साथ केवल उस सत्यापित सूचना पर ही इस अंतिम जांच परिणाम के प्रयोजन के लिए विश्वास किया गया है।
- थ. दिनांक 19.08.2021 को गोपनीय रूपांतर के साथ सभी हितबद्ध पक्षकारों को ई-मेल के माध्यम से टिप्पणियां, यदि कोई हैं, दायर करने के लिए दिए गए उपयुक्त समय के साथ प्रकटन विवरण (एनसीवी) दिया गया था। हितबद्ध पक्षकारों से प्राप्त टिप्पणियों को प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड में लिया गया है।
- द. जांच प्रक्रिया के दौरान हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अन्य अनुरोधों पर साक्ष्य के साथ समर्थित सीमा तक और वर्तमान जांच में संगत मानी गई सीमा तक प्राधिकारी द्वारा इस अंतिम जांच परिणाम में उपयुक्त रूप से विचार किया गया है।
- ध. वर्तमान पाटनरोधी जांच के प्रयोजन के लिए जांच की अवधि अप्रैल, 2019 – मार्च, 2020 (12 माह) है। क्षति विश्लेषण के संदर्भ में प्रवृत्तियों की जांच में अप्रैल, 2016 – मार्च, 2017, अप्रैल, 2017 – मार्च, 2018, अप्रैल, 2018 – मार्च, 2019 और जांच की अवधि शामिल है।
- न. विश्व भर में कोविड-19 फैलने और परिणामस्वरूप भारत सहित विभिन्न देशों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के कारण प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(6) तथा दिनांक 10 अप्रैल, 2020 की व्यापार सूचना संख्या 01/2020 के अनुसार हितबद्ध पक्षकारों को निर्दिष्ट प्राधिकारी के समक्ष मौखिक रूप से संगत सूचना प्रस्तुत करने के लिए अवसर प्रदान करने हेतु 2 मार्च, 2021 को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से मौखिक सुनवाई आयोजित की। जिन पक्षकारों ने उपर्युक्त मौखिक सुनवाई में भाग लिया था, उन सभी को यह सलाह दी गई थी कि वे मौखिक रूप से व्यक्त विचारों के लिखित अनुरोध दायर करें और उसके बाद, यदि कोई प्रत्युत्तर हैं, तो उन्हें दायर करें। हितबद्ध पक्षकारों से प्राप्त इन लिखित अनुरोधों और प्रत्युत्तरों में दिए गए तर्कों पर इस अंतिम जांच परिणाम के प्रयोजन के लिए आवश्यक समझी गई सीमा तक विचार किया गया है।
- प. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर दी गई सूचना की जांच गोपनीयता के दावे की पर्याप्तता के संबंध में की गई थी। संतुष्ट होने पर प्राधिकारी ने जहां कहीं भी आवश्यक था, गोपनीयता के ऐसे दावों को स्वीकार किया है और ऐसी सूचना को गोपनीय समझा है और उसे अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट नहीं किया है। जहां कहीं भी संभव हुआ है, वहां गोपनीय आधार पर सूचना प्रदान करने वाले पक्षकारों को निदेश दिया गया था कि वे गोपनीय आधार पर दायर सूचना का पर्याप्त अगोपनीय रूपांतर उपलब्ध कराएं।
- फ. प्राधिकारी ने प्रकटन पश्चात टिप्पणियों सहित सभी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाए गए तर्कों और दी गई सूचना पर उस सीमा तक विचार किया है जहां तक वे साक्ष्यों से समर्थित हैं और वर्तमान जांच के लिए संगत मानी गई हैं।
- ब. जहां कहीं किसी हितबद्ध पक्षकार ने वर्तमान जांच प्रक्रिया के दौरान आवश्यक सूचना देने से इंकार किया है अथवा अन्यथा उपलब्ध नहीं कराई है अथवा जांच में काफी बाधा डाली है, वहां प्राधिकारी ने ऐसे पक्षकारों को असहयोगी माना है और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अंतिम जांच परिणाम में रिकार्ड किया है।
- भ. इस दस्तावेज में \*\*\* गोपनीय आधार पर किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा दी गई और नियमावली के तहत प्राधिकारी द्वारा मानी गई सूचना दर्शाते हैं।
- म. प्राधिकारी द्वारा जांच की अवधि के लिए अपनाई गई विनिमय दर 1 अमेरिकी डॉलर = 71.65 रुपए है।

**ग. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु**

4. जांच की शुरुआत के स्तर पर विचाराधीन उत्पाद निम्नलिखित रूप में परिभाषित किया गया था:

3. विचाराधीन उत्पाद "विटामिन सी के सभी रूपों में विटामिन सी" है जिसे एस्कॉर्बिक एसिड, एल-जिलोएस्कॉर्बिक एसिड, 3-ऑक्सो एल-गुलोफुरानोलेक्टोन (इनोल फॉर्म), एल-3-केटोथ्रोक्सोरोमिक एसिड लेक्टोन इत्यादि है, जैसा कि प्रविष्टि संख्या "मर्क इंडेक्स की 867" के तहत वर्णित है।

4. विटामिन सी का प्रयोग प्राथमिक रूप से विभिन्न औषधियों के उत्पादन के लिए फार्मास्युटिकल कंपनियों द्वारा किया जाता है। इस उत्पाद का प्रयोग गैर-फार्मास्युटिकल उद्योग में भी होता है। विटामिन सी टिशू की मरम्मत और विभिन्न खाद्यों में पाए गए कुछ न्यूरोट्रांसमीटर के एंजाइमेटिक उत्पादन में शामिल अनिवार्य पोषक है। इसकी कई एंजाइम के कार्यकरण के लिए आवश्यकता होती है और प्रतिरोधक क्षमता के कार्य के लिए महत्वपूर्ण है। यह एंटी ऑक्सीडेंट के रूप में भी कार्य करता है।

5. विचाराधीन उत्पाद सीमा शुल्क उप शीर्ष संख्या 29362700 के तहत सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 (1975 का 51) के अध्याय 29 के अंतर्गत वर्गीकृत है। सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है और विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र पर बाध्यकारी नहीं है।

**ग.1 घरेलू उद्योग के विचार**

5. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध निम्नलिखित हैं:

क. वर्तमान जांच के लिए विचाराधीन उत्पाद चीन जन. गण. के मूल का अथवा वहां से निर्यातित "विटामिन सी" है। विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड, एल-जिलोएस्कॉर्बिक एसिड, 3-ऑक्सो एल-गुलोफुरानोलेक्टोन (इनोल फॉर्म), एल-3-केटोथ्रोक्सोरोमिक एसिड लेक्टोन इत्यादि जैसे विभिन्न पर्यायवाची नामों से भी जाना जाता है, जैसा कि प्रविष्टि संख्या "मर्क इंडेक्स की 867" के तहत वर्णित है।

ख. विचाराधीन उत्पाद को "विटामिन सी/एस्कॉर्बिक एसिड" के रूप में माना जाना चाहिए। विटामिन सी के व्युत्पन्न वर्तमान जांच के क्षेत्र के अंतर्गत नहीं हैं।

ग. विटामिन सी का प्रयोग प्राथमिक रूप से विभिन्न औषधियों के उत्पादन के लिए फार्मास्युटिकल कंपनियों द्वारा किया जाता है। तथापि, इस उत्पाद का प्रयोग गैर-फार्मास्युटिकल उद्योग में भी होता है। विटामिन सी टिशू की मरम्मत और विभिन्न खाद्यों में पाए गए कुछ न्यूरोट्रांसमीटर के एंजाइमेटिक उत्पादन में शामिल अनिवार्य पोषक है। इसकी कई एंजाइम के कार्यकरण के लिए आवश्यकता होती है और प्रतिरोधक क्षमता के कार्य के लिए महत्वपूर्ण है। यह एंटी ऑक्सीडेंट के रूप में भी कार्य करता है।

घ. ऐसे भी साक्ष्य हैं कि विटामिन सी का नियमित रूप से प्रयोग करने पर सामान्य जुकाम की अवधि कम हो सकती है। शरीर कई विभिन्न तरीकों में विटामिन सी का प्रयोग करता है और कोलाजेन बनाने के लिए शरीर को इसकी आवश्यकता होती है। विटामिन सी की आवश्यकता स्किन, टेंडन, लिगामेंट्स और ब्लड वेसेल बनाने और कार्टिलेज, हड्डियों और दातों की मरम्मत और रख-रखाव के लिए, घावों को भरने के लिए और स्कार टिशू बनाने के लिए होती है। इसका सामान्यतः किलोग्राम अथवा मीट्रिक टन के रूप में व्यक्त निवल भार के संदर्भ में उत्पादन तथा बिक्री की जाती है।

ड. विटामिन सी सीमा प्रशुल्क अधिनियम के अध्याय 29 के अंतर्गत "विटामिन सी और उसके व्युत्पन्न" के रूप में वर्गीकृत है। विटामिन सी के लिए समर्पित कोड 29362700 है। तथापि, सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है और वर्तमान जांच के क्षेत्र पर बाध्यकारी नहीं है।

च. आवेदक द्वारा उत्पादित सामान आयातित सामानों की समान वस्तु हैं क्योंकि वे रासायनिक एवं तकनीकी विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, प्रकार्य एवं प्रयोग, उत्पाद विशिष्टियों, कीमत, वितरण एवं विपणन तथा सामानों के प्रशुल्क वर्गीकरण के संदर्भ में तुलनीय हैं और तकनीकी तथा वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं।

छ. घरेलू उद्योग तथा संबद्ध देश में उत्पादकों द्वारा लगाई गई प्रौद्योगिकी में कोई महत्वपूर्ण ज्ञात अंतर नहीं है।

- ज. विचाराधीन उत्पाद केवल एक थोक औषधि है न कि निर्माण। औषध (कीमत नियंत्रण) आदेश, 2013 ("डीपीसीओ") के तहत लगाई गई कीमत सीमा निर्माण के लिए है न कि एपीआई अथवा थोक औषध के लिए।
- झ. उत्पादकों के लिए अपनी वेबसाइट पर अपने उत्पादों के विश्लेषण का प्रमाण-पत्र अपलोड करने की अपेक्षित नहीं है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद सभी लागू मानदंडों का पालन करता है। आयातों के संबंध में भी यही मानक लागू हैं। घरेलू उद्योग आयातित उत्पाद की समान वस्तु का उत्पादन और बिक्री करता है।
- ञ. भारत में विटामिन सी के किसी भी आयात को भारतीय फार्माकॉपिया (आईपी) के अनुसार पालन करना होता है और घरेलू उत्पादकों द्वारा उसी गुणवत्ता का विनिर्माण किया जाता है।
- ट. आवेदक द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया चीनी उत्पादकों द्वारा लगाई गई प्रक्रिया के समान है।

## ग.2 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

6. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध निम्नलिखित हैं:
  - क. विचाराधीन उत्पाद के विश्लेषण और प्रमाण-पत्र उनकी सरकारी वेबसाइट पर नहीं हैं। घरेलू उद्योग की वेबसाइट खाली है। हितबद्ध पक्षकार आयातित और घरेलू उत्पाद की तुलना नहीं कर सकते।
  - ख. उत्पाद मुख्य रूप से चार रूपों में है, यथा – टेबलेट, पाउडर, कोटेड तथा अनकोटेड। प्रयोग, कीमत आदि में अंतर की जांच किए जाने की आवश्यकता है। टेबलेट महंगी है। चीन मुख्य रूप से भारत को पाउडर रूप में निर्यात करता है।
  - ग. आयात एडीसी (असिस्टेंट ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया) से अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एनओसी) के अधीन है। वे विशिष्ट मार्किंग के साथ आयातों की गुणवत्ता का नियंत्रण करते हैं।
  - घ. आवेदक द्वारा अपनाई उत्पादन प्रक्रिया चीनी उत्पादकों से भिन्न है और लागत प्रभावी नहीं है जिससे स्व-प्रभावित क्षति हुई है।
  - ङ. विचाराधीन उत्पाद के बीपी, यूएसपी, एफओओडी, एफईईडी ग्रेड आदि जैसे कई ग्रेड हैं। कीमत और प्रयोग में ग्रेड के अनुसार अंतर है।

## ग.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

7. जांच की शुरुआत की अधिसूचना में परिभाषित किए गए अनुसार, विचाराधीन उत्पाद "विटामिन सी के सभी रूपों में विटामिन सी" है जिसे एस्कॉर्बिक एसिड, एल-जिलोएस्कॉर्बिक एसिड, 3-ऑक्सो एल-गुलोफुरानोलेक्टोन (इनोल फॉर्म), एल-3-केटोथ्रोक्सोरोमिक एसिड लेक्टोन इत्यादि है, जैसा कि प्रविष्टि संख्या "मर्क इंडेक्स की 867" के तहत वर्णित है। विटामिन सी का प्रयोग प्राथमिक रूप से विभिन्न औषधियों के उत्पादन के लिए फार्मास्युटिकल कंपनियों द्वारा किया जाता है। विचाराधीन उत्पाद का क्षेत्र थोक औषध के रूप में केवल विटामिन सी है, न कि निर्माण के रूप में।
8. विटामिन सी टिशू की मरम्मत और विभिन्न खाद्यों में पाए गए कुछ न्यूट्रांसमीटर के एंजाइमेटिक उत्पादन में शामिल अनिवार्य पोषक है। इसकी कई एंजाइम के कार्यकरण के लिए आवश्यकता होती है और प्रतिरोधक क्षमता के कार्य के लिए महत्वपूर्ण है। यह एंटी ऑक्सीडेंट के रूप में भी कार्य करता है।
9. एक पक्षकार द्वारा प्रस्तुत की गई प्रकटन पश्चात टिप्पणियां जो स्पष्ट रूप से इस बात का उल्लेख करती हैं कि क्या विटामिन-सी का डेरिवेटिव्स विचाराधीन उत्पाद का हिस्सा नहीं है, के संबंध में, प्राधिकारी यह स्पष्ट करते हैं कि विटामिन सी का डेरिवेटिव्स वर्तमान जांच के क्षेत्र में नहीं है।
10. विचाराधीन उत्पाद सीमा शुल्क उप शीर्ष संख्या 29362700 के तहत सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 (1975 का 51) के अध्याय 29 के अंतर्गत वर्गीकृत है। सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है और जांच के क्षेत्र पर बाध्यकारी नहीं है।
11. जहां तक घरेलू उत्पादों की वेबसाइट पर विश्लेषण प्रमाण-पत्र न होने का संबंध है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि वेबसाइट पर विश्लेषण का प्रमाण-पत्र अपलोड करने की कोई सांविधिक अपेक्षा नहीं है। इसके अतिरिक्त, घरेलू

उत्पादक भारत में कई उपभोक्ताओं को बिक्री कर रहे हैं और घरेलू उत्पादकों के उत्पाद के विश्लेषण का प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के लिए उनके लिए इसे बाधा नहीं होना चाहिए।

12. जहां तक विभिन्न ग्रेडों और उत्पाद के रूपों की मौजूदगी का संबंध है, यह स्पष्ट किया जाता है कि विचाराधीन उत्पाद का क्षेत्र केवल ठोस औषध है, न कि उसका निर्माण। हितबद्ध पक्षकारों द्वारा विनिर्दिष्ट उत्पाद के रूप उत्पाद के निर्माण के लिए संगत प्रतीत होते हैं।
13. जहां तक आवेदक तथा चीनी उत्पादकों द्वारा अपनाई गई उत्पादन प्रक्रिया में अंतर का संबंध है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि उत्पादन प्रक्रिया में अंतर अथवा आरंभिक कच्ची सामग्री में अंतर दोनों उत्पादों को तब तक भिन्न नहीं बनाता, जब तक खुद उत्पाद के गुणधर्म भिन्न न हों। तथापि, हितबद्ध पक्षकारों ने उत्पाद के गुणधर्मों में कोई अंतर सिद्ध नहीं किया है।
14. भारतीय बाजार में घरेलू विनिर्माताओं के माध्यम से अथवा आयातों के माध्यम से उत्पाद की बिक्री भारतीय फार्माकॉपिया (आईपी) के अनुसार होनी चाहिए और इसीलिए पक्षकारों द्वारा बेचा गया उत्पाद तुलनीय गुणवत्ता का होना चाहिए। जहां तक निर्माण का संबंध है, उसकी कीमत भारत सरकार द्वारा नियंत्रित की जाती है।
15. आवेदक ने दावा किया कि उसके द्वारा उत्पादित विटामिन सी और संबद्ध देश से आयातित विटामिन सी व्यापक रूप से समान विनिर्माण प्रक्रिया एवं प्रौद्योगिकी, प्रकार्य एवं प्रयोग, उत्पाद विशिष्टियों, कीमत, वितरण एवं विपणन तथा प्रशुल्क वर्गीकरण वाली समान आधारभूत कच्ची सामग्री का प्रयोग करके उत्पादित किया जाता है। आवेदक के तर्क पर अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा विवाद नहीं किया गया है। यह उत्पाद विगत में पाटनरोधी शुल्क के अध्याधीन था और घरेलू तथा आयातित उत्पाद के बीच कोई सिद्ध अंतर नहीं था। प्राधिकारी निर्धारित करते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध सामान नियमावली के नियम 2(घ) के अनुसार संबद्ध देश से आयातित उत्पाद की समान वस्तु है।

## **घ. घरेलू उद्योग का क्षेत्र एवं आधार**

### **घ.1 घरेलू उद्योग के विचार**

16. घरेलू उद्योग के क्षेत्र एवं आधार के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:
  - क. आवेदन पत्र मैसर्स बजाज हेल्थकेयर लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है।
  - ख. देश में विचाराधीन उत्पाद के तीन अन्य उत्पादक हैं, अर्थात:
    - (i) मैसर्स अमोली ऑर्गेनिक्स प्रा. लि.
    - (ii) मैसर्स रेकोन डायग्नोस्टिक्स प्रा. लि. और
    - (iii) मैसर्स एस. आर. बायोकेम
  - ग. विचाराधीन उत्पाद के सभी तीन अन्य उत्पादकों ने आवेदन पत्र और वर्तमान जांच का समर्थन किया है।
  - घ. आवेदक न तो भारत में किसी आयातक से संबद्ध हैं और न ही संबद्ध देश के किसी निर्यातक से तथा उन्होंने संबद्ध देश से विचाराधीन उत्पाद का आयात नहीं किया है।
  - ड. आवेदक का भारत में संबद्ध सामानों के कुल घरेलू उत्पादन में प्रमुख अनुपात है और इस प्रकार वह घरेलू उद्योग है।

### **घ.2 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार**

17. घरेलू उद्योग के क्षेत्र एवं आधार के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:
  - क. आवेदक को आवेदन पत्र का समर्थन करने वाले घरेलू उत्पादकों के लिए क्षति संबंधी आंकड़े देने चाहिए, जिसे वे अपने साथ घरेलू उद्योग होने का दावा करते हैं।

### **घ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच**

18. नियमावली के नियम 2(ख) में घरेलू उद्योग निम्नलिखितानुसार परिभाषित है:

“घरेलू उद्योग” का तात्पर्य ऐसे समग्र घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु के विनिर्माण और उससे जुड़े किसी कार्यकलाप में संलग्न हैं अथवा ऐसे उत्पादकों से है जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उक्त वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा भाग बनता है सिवाए उस स्थिति के जब ऐसे उत्पादक आरोपित पाटित वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित होते हैं अथवा वे स्वयं उसके आयातक होते हैं, तो ऐसे मामले में “घरेलू उद्योग” पद का अर्थ शेष उत्पादकों के संदर्भ में लगाया जा सकता है।

19. यह आवेदन पत्र मैसर्स बजाज हेल्थकेयर लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है। आवेदक न तो संबद्ध देश में संबद्ध सामानों के किसी आयातक अथवा निर्यातक से संबद्ध है और न ही उन्होंने संबद्ध देश से संबद्ध सामानों का आयात किया है। आवेदक देश में संबद्ध सामानों का सबसे बड़ा उत्पादक है।
20. आवेदक द्वारा दायर आवेदन पत्र का विचाराधीन उत्पाद के अन्य उत्पादकों मैसर्स अमोली ऑर्गेनिक्स प्रा. लि., मैसर्स रेकोन डायग्नोस्टिक्स प्रा. लि. और मैसर्स एस. आर. बायोकेम ने समर्थन किया है।
21. प्राधिकारी ने अन्य घरेलू उत्पादकों को यह सलाह देते हुए पत्र भेजा कि वे क्षति निर्धारण के संबंध में निर्धारित स्वरूप एवं तरीके में संगत सूचना दायर करें। तथापि, किसी भी अन्य घरेलू उत्पादक ने निर्धारित प्रपत्र में पूरी क्षति संबंधी सूचना दायर नहीं की है।
22. प्राधिकारी नोट करते हैं कि प्राधिकारी ने समर्थकों के लिए एक प्रपत्र निर्धारित किया है ताकि वे समर्थक उन्हें हुई संभावित क्षति के संबंध में अपना दावा दर्ज कर सकें। अतः प्राधिकारी ने वर्तमान मामले में उन समर्थकों को संभावित क्षति की जांच नहीं की है क्योंकि उन समर्थकों ने संगत सूचना उपलब्ध नहीं कराई है। तथापि, ऐसी स्थिति में जहां समर्थक घरेलू उत्पादक ने निर्धारित प्रपत्र में संगत सूचना उपलब्ध नहीं कराई है बल्कि फिर भी आवेदन पत्र का समर्थन व्यक्त किया है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि यह समर्थन नियम 5 के अभिप्राय से स्वीकार किए जाने की आवश्यकता है।
23. रिकार्ड में उपलब्ध साक्ष्य यह दर्शाता है कि आवेदक का भारत में कुल उत्पादन में प्रमुख अनुपात (46 प्रतिशत)/(40 प्रतिशत – 50 प्रतिशत) है। इसके अतिरिक्त, आवेदक का समर्थक सहित भारत में संबद्ध सामानों के कुल उत्पादन में 100 प्रतिशत हिस्सा है। तदनुसार, प्राधिकारी मानते हैं कि आवेदक नियमावली के नियम 2(ख) के अभिप्राय से घरेलू उद्योग है और यह मानते हैं कि आवेदन पत्र नियमावली के नियम 5(3) के अनुसार आधार के मानदंड पूरा करता है।

## ड. गोपनीयता

### ड.1 घरेलू उद्योग के विचार

24. गोपनीयता के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:
  - क. मैसर्स सिनोब्राइट फार्मास्युटिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा दिनांक 1 मार्च, 2021 के मेल द्वारा परिचालित उत्तर बहुत देर से है और उसे प्राधिकारी द्वारा स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। उत्तर प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख 27 नवंबर, 2020 थी।
  - ख. हितबद्ध पक्षकारों ने पर्याप्त एवं पूर्ण सूचना दायर करने के लिए बढ़ाकर समय दिए जाने के बाद भी अगोपनीय रूपांतर में भारी कमी वाला उत्तर दायर किया है। यह पूरी तरह घरेलू उद्योग को अपने वैध हितों की रक्षा करने से रोकने के इरादे से है। प्रश्नावली के उत्तर रद्द किए जाने अपेक्षित है।
  - ग. विदेशी उत्पादकों ने शेयरधारण संरचना, उत्पादन प्रक्रिया, मूल्य श्रृंखला, उत्पादन सुविधाओं, संबद्ध पक्षकारों, कच्ची सामग्री की खरीद, उत्पादित और/अथवा बेचे गए उत्पादों की सूची, धारक कंपनी के नाम, शेयरधारण के ब्यौरों, गृह बाजार में विपणन के चैनल के संबंध में अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया है और भारत को निर्यात के लिए सूचना गोपनीय होने का दावा किया है।
  - घ. गोपनीय होने का दावा की गई सूचना के लिए कोई सूचीबद्ध रूपांतर नहीं दिया है।
  - ड. निर्यातक संबद्ध सामानों के विनिर्माण के लिए प्रयुक्त कच्ची सामग्री विनिर्दिष्ट करने में भी विफल रहे।



च. आवेदक को प्राधिकारी द्वारा प्रस्तुत उत्तर के सार को उपयुक्त रूप से समझने की अनुमति देने के लिए पर्याप्त ब्यौरे नहीं दिए गए हैं। आवेदक यह भी निर्धारित नहीं कर सकते कि कौन सी सूचना दी गई है और क्या उस पर कोई विश्वास किया जा सकता है। परिणामस्वरूप आवेदक गंभीर रूप से असमर्थ है और निर्यातक द्वारा दायर उत्तर पर टिप्पणी करने में असमर्थ है।

## ड.2 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

25. गोपनीयता के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

क. विगत 22 वर्षों से पाटनरोधी शुल्कों के बावजूद घरेलू उद्योग तथ्यों को प्रकट करने में अत्यधिक गोपनीयता का दावा कर संरक्षण की मांग कर रहा है।

## ड.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

26. गोपनीयता के संबंध में जांच प्रक्रिया के दौरान आवेदक तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए विभिन्न अनुरोधों की प्राधिकारी द्वारा संगत मानी गई सीमा तक जांच की गई है और निम्नलिखित रूप में उन्हें हल किया गया है।

27. प्राधिकारी ने नियम 6(7) के अनुसार निरीक्षण के लिए विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के अगोपनीय रूपांतर से युक्त सार्वजनिक फाइल के माध्यम से सभी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दी गई सूचना का अगोपनीय रूपांतर उपलब्ध कराया।

28. सूचना की गोपनीयता के संबंध में, नियमावली के नियम 7 में निम्नलिखित प्रावधान है:

“ गोपनीय सूचना : (1) नियम 6 के उप नियमों (2), (3) और (7), नियम 12 के उप नियम (2), नियम 15 के उपनियम (4) और नियम 17 के उपनियम (4) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जांच की प्रक्रिया में नियम 5 के उपनियम (1) के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों के प्रतियां या किसी पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर निर्दिष्ट प्राधिकारी को प्रस्तुत किसी अन्य सूचना के संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकारी उसकी गोपनीयता से संतुष्ट होने पर उस सूचना को गोपनीय मानेंगे और ऐसी सूचना देने वाले पक्षकार से स्पष्ट प्राधिकार के बिना किसी अन्य पक्षकार को ऐसी किसी सूचना का प्रकटन नहीं करेंगे।

(2) निर्दिष्ट प्राधिकारी गोपनीय अधिकारी पर सूचना प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों से उसका अगोपनीय सारांश प्रस्तुत करने के लिए कह सकते हैं और यदि ऐसी सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार की राय में उस सूचना का सारांश नहीं हो सकता है तो वह पक्षकार निर्दिष्ट प्राधिकारी को इस बात के कारण संबंधी विवरण प्रस्तुत करेगा कि सारांश करना संभव क्यों नहीं है।

(3) उप नियम (2) में निहित किसी बात के होते हुए भी यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हो कि गोपनीयता के लिए अनुरोध न्यायसंगत नहीं अथवा सूचना प्रदाता सूचना को सार्वजनिक करने अथवा इसको सामान्य तौर पर अथवा संक्षिप्त रूप में उसे प्रकट करने के लिए अनिच्छुक हो, तो ऐसी सूचना की उपेक्षा की जा सकती है।

29. जहां तक सूचना की गोपनीयता के संबंध में शर्तों का संबंध है, हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर दी गई सूचना की गोपनीयता के दावों की उनकी पर्याप्तता के संदर्भ में जांच की गई थी। प्राधिकारी ने संतुष्ट होने पर जहां कहीं भी आवश्यक था, गोपनीयता के ऐसे दावों को स्वीकार किया है और ऐसी सूचना को गोपनीय समझा है और उसे अन्य हितबद्ध पक्षकारों के समक्ष प्रकट नहीं किया है। जहां कहीं भी संभव हुआ है, वहां गोपनीय आधार पर सूचना प्रदान करने वाले पक्षकारों को निदेश दिया गया था कि वे गोपनीय आधार पर दायर सूचना का पर्याप्त अगोपनीय रूपांतर उपलब्ध कराएं। प्राधिकारी ने सार्वजनिक फाइल के रूप में विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य का अगोपनीय रूपांतर उपलब्ध कराया। घरेलू उद्योग के आयातों, निष्पादन मानदंडों और क्षति मानदंडों से संबंधित सूचना सार्वजनिक फाइल में उपलब्ध कराई गई है। व्यापार संवेदी सूचना परिपाटी के अनुसार गोपनीय रखी गई है।

**च. विविध अनुरोध****च.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार**

30. विविध मुद्दों के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित विविध अनुरोध किए गए हैं:

- क. अमेरिकी डॉलर 3.74 प्रति कि.ग्रा. की दर पर अबाधित रूपसे 22 वर्ष के लम्बे पाटनरोधी शुल्क का लाभ लेने के बाद घरेलू विनिर्माताओं ने नई जांच के लिए फिर से एक आवेदन पत्र दायर किया है।
- ख. उपर्युक्त संरक्षण संबंधित उद्योग को क्षति से संरक्षण प्रदान करने के उल्लिखित उद्देश्य से युक्त है तथा साथ ही, उद्योग विचाराधीन उत्पाद में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आवश्यक कौशल, प्रौद्योगिकी और संसाधन विकसित करने का प्रयास करेगा, परंतु घरेलू उद्योग चीन पर 100 प्रतिशत निर्भर बना हुआ है क्योंकि वे निरंतर चीन से अंतिम उत्तर पर तत्काल (2 केजीए) की खरीद करते आ रहे हैं।
- ग. घरेलू उद्योग ने पाटनरोधी शुल्कों के अनारक्षित समर्थन के बाद भी 2 केजीए पर आत्मनिर्भरता के प्रति बिल्कुल भी कोई प्रगति नहीं की है। पाटनरोधी शुल्क उन्हें अप्रत्याशित लाभ प्रदान करता आ रहा है और पिछड़े एकीकरण के लिए कोई अनुरोध नहीं है।
- घ. 1998 से प्राधिकारी ने पाटनरोधी शुल्क लगाया है जिसके परिणामस्वरूप भारतीय घरेलू बाजार में आवेदक के पक्ष में एकाधिकार बना है।
- ङ. भारत चीन से निर्यातों के लिए प्रमुख बाजार भी है क्योंकि भारत को कुल निर्यातों का एक छोटा सा भाग भी निर्यात किया जाता है। चीनी उत्पादकों का निर्यात अभिमुखीकरण संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ की ओर निर्देशित है, न कि भारत की ओर। चीन का विश्व में "विटामिन सी" के उत्पादन में लगभग एकाधिकार है और वह पाटनरोधी कानूनों की परिधि में नहीं आता है। यह पूरी तरह गलत उल्लिखित किया गया है कि चीन के निर्यातक भारत में "विटामिन सी" का पाटन करना चाहते हैं।
- च. प्राधिकारी को यह जांच करनी चाहिए कि भारतीय उद्योग 22 वर्षों से अधिक समय से शुल्क के संरक्षण के बावजूद वैश्विक व्यापारियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम क्यों नहीं है।
- छ. विचाराधीन उत्पाद कोविड के विरुद्ध एक आधारभूत एवं प्राथमिक दवाई है, जैसा कि भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) द्वारा निर्धारित किया गया है और कोविड में इसका व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। इस महामारी में इस उत्पाद पर कोई पाटनरोधी शुल्क नहीं होना चाहिए। पाटनरोधी शुल्क उचित दर पर उत्पाद की उपलब्धता प्रतिबंधित करेंगे और याचिकाकर्ता को किसी संरक्षण की आवश्यकता नहीं है।
- ज. यदि पाटनरोधी शुल्क लगाया जाता है तो घरेलू उद्योग पाटनरोधी शुल्क की राशि तक अपनी कीमत बढ़ा सकते हैं। अतः आयातित तथा भारत में उत्पादित उत्पाद दोनों महंगे हो जाएंगे और उपभोक्ताओं को अधिक कीमत वहन करनी होगी। विगत 5 वर्षों में, "विटामिन सी" पर पाटनरोधी शुल्क के कारण भारत में बिक्री कीमत 6 अमेरिकी डॉलर/कि.ग्रा. से अधिक के स्तर पर रही और यहां तक कि कभी-कभी 10 अमेरिकी डॉलर/कि.ग्रा. तक पहुँची।
- झ. पाटनरोधी शुल्क इस दवाई की कीमत बढ़ाएंगे जिसका अंततः जनता पर और विशेष रूप से गरीब जनता पर (भारत में अधिकतम गरीब लोग हैं) प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इससे मृत्यु दर अधिक बढ़ सकती है। इससे विश्व में भारत का नाम खराब होगा।
- ञ. घरेलू उद्योग द्वारा व्यवहार और वाणिज्यिक शोषण ने प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया है और देश का हित उल्लिखित प्रयोजन और उद्देश्यों की वाणिज्यिक उपयोग की दृष्टि से पूरी तरह अनदेखी की गई है।
- ट. पाटनरोधी शुल्क लागू करने से केवल चुनिंदा भारतीय विनिर्माता अत्यधिक लाभ प्राप्त करते हैं, परंतु उन भारतीय फार्मास्युटिकल उद्यमों, खाद्य उद्यमों और पेय पदार्थों के उद्यमों के लाभ को नुकसान पहुँचाते हैं जो अपने उत्पादों के उत्पादन के लिए "विटामिन सी" का प्रयोग करते हैं। उपभोक्ताओं के संबंध में उल्लेख नहीं किया जाता।

- ठ. विटामिन सी पर पाटनरोधी शुल्क लगाना उपयुक्त नहीं होगा क्योंकि 22 वर्षों के संरक्षण के बाद भी घरेलू उद्योग ने केवल उद्देश्य देखा है और भारतीय उपभोक्ता पर उस उत्पाद के लिए और अधिक भुगतान करने का भार पड़ा है जो कि काफी सस्ती दर पर उपलब्ध है। यह खुद ही सिद्ध करता है कि कोई पाटन नहीं है।
- ड. यदि सरकार यह महसूस करती है कि घरेलू उद्योग को संरक्षित किया जाना है तो अतिरिक्त इनपुट शुल्क के रूप में 13 प्रतिशत सीआईएफ मूल्य लगाया जा सकता है अथवा समतुल्य पाटनरोधी शुल्क लगाया जाना चाहिए जो मोटे तौर पर 0.58 अमेरिकी डॉलर/कि.ग्रा. आता है। यदि 3.74 अमेरिकी डॉलर/कि.ग्रा. का शुल्क लगाया जाता है तो उसका कोई औचित्य नहीं होगा और प्रावधान का दुरुपयोग होगा।
- ढ. आवेदक द्वारा किए गए अनुरोध के विपरीत, विचाराधीन उत्पाद के स्थानापन्न है (यथा साइट्रिक एसिड, पोटेशियम ब्रोमेट, एजोडिकारबोनामाइड)।
- ण. चूंकि यह उत्पाद एक एपीआई है, अतः इसकी उपलब्धता और कीमत बहुत महत्वपूर्ण है।
- त. घरेलू उत्पादकों ने अपने विवेक पर ही अपनी सहमत आपूर्ति संविदाओं को रद्द किया है और वस्त्र एवं व्यावसायी समूहन में लगा हुआ है।
- थ. आयात और घरेलू उद्योग दोनों उच्च मांग की स्थितियों से लाभान्वित होते रहे हैं। विचाराधीन उत्पाद की कोई निर्धारित मांग नहीं है क्योंकि यह बाजार स्थिति पर निर्भर करती है जिसमें उतार-चढ़ाव आता है।
- द. आवेदक द्वारा दिए गए विपरीत/गलत आंकड़ों के दो सेट हैं। अतः हितबद्ध पक्षकार कोई सार्थक टिप्पणियां देने में सक्षम नहीं हैं और जांच में पूरी तरह से भाग लेने में सक्षम नहीं रहे हैं।
- ध. घरेलू उद्योग ने निर्णायक समीक्षा की शुरुआत के लिए आवेदन दायर नहीं किया और इसके बजाए जानबूझकर नई जांच के लिए आवेदन दायर किया क्योंकि आगे क्षति की कोई संभावना नहीं थी।
- न. अपीलीय निकाय ने यूएस-कोरोसिन रेसिस्टेंट स्टील निर्णायक समीक्षा में यह नोट किया था कि संभावना का निर्धारण उसी तारीख से निर्धारण है और यह कि जांचकर्ता प्राधिकारियों को मुद्दे का हल निकालने की मांग करने के लिए आगे का विश्लेषण करना चाहिए कि यदि शुल्क समाप्त किए गए तो क्या होने की संभावना है।
- प. घरेलू उद्योग ने अप्रैल, 2020 से अगस्त, 2020 तक 60 प्रतिशत से अधिक तक कीमतें बढ़ाई हैं जो उत्पादन लागत में वृद्धि के बिना हैं जिससे लाभ का सहारा लिया गया है। केवल तीन माह की छोटी अवधि के अंतर्गत घरेलू उद्योग 31 मार्च, 2020 को समाप्त 12 माह के दौरान अर्जित लाभ का 78 प्रतिशत (30 सितंबर, 2020 को समाप्त तिमाही में) और 56 प्रतिशत (30 जून, 2020 को समाप्त तिमाही में) कमाने में सक्षम था।
- फ. इस मामले की पृष्ठभूमि के कारण जांच की अवधि के बाद के आंकड़ों का घरेलू उद्योग के कार्यों की स्थिति समझने के लिए विश्लेषण किया जाना चाहिए।
- ब. मांग में अचानक वृद्धि के बाद, उत्तरदाताओं ने अपने उत्पादन में काफी वृद्धि की है ताकि महामारी के दौरान कोई कमी न रहे और यह इस तथ्य के बावजूद है कि डीपीसीओ ने अंतिम उत्पाद के लिए 23.02 रुपये प्रति स्ट्रिप की कीमत सीमा निर्धारित की है।
- भ. विचाराधीन उत्पाद एक अनिवार्य औषधि है। एकाधिकारिक लाभ लेने के लिए घरेलू उद्योग ने देश में संबद्ध सामानों की महत्ता और आवश्यकता को कम आंका है।
- म. विटामिन सी, जो समाज को अन्य लाभ भी देती है, जैसी अनिवार्य औषधि पर पाटनरोधी शुल्क लगाकर उद्योग के दावे से अत्यधिक महत्ता, विशेष रूप से वर्तमान समय में, के उत्पाद की कीमतें बढ़ाकर देश को सेवाहीन करने जैसा होगा।
- य. याचिकाकर्ता सहित समर्थक उत्पादकों ने समूह बनाया और मिलकर कीमतें बढ़ाई और इस प्रकार घरेलू उद्योग वैश्विक महामारी के बीच में आम जनता के स्वास्थ्य की कीमत पर कीमतें बढ़ाने में लगा रहा।
- कक. विचाराधीन उत्पाद जो विटामिन सी औषधि, जो कोविड-19 महामारी में देश के लोगों के जीवन को बचा सकता है, के आयातों पर शुल्क लगाना जनहित में नहीं होगा।

- खख. प्राधिकारी को विटामिन सी परिष्कृत उत्पाद के विनियामक कार्यवाही के और रोगी/ अंतिम उपभोक्ता पर उसके प्रभाव पर भी विचार करना चाहिए।
- गग. कुल मिलाकर अंतिम उपभोक्ता एफएसएसआई श्रेणी के विटामिन सी के विकल्प पर भी रह सकते हैं, जो कीमत प्रतिबंधों के अध्यधीन नहीं है और रोगी की 500 एमजी की थेराप्यूटिक डोज की आवश्यकता को पूरा नहीं कर सकती हैं।
- घघ. विटामिन सी टेबलेट प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए, विशेषकर चल रही कोविड-19 महामारी के दौरान, सामान्यतः ली जाती है। इस प्रकार, पाटनरोधी शुल्क लगाने से टेबलेट के विनिर्माण और उसकी सतत आपूर्ति बनाए रखने की क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और इससे अंततः जनहित प्रभावित हो सकता है।
- ङङ. विचाराधीन उत्पाद के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क पुनः लगाने से घरेलू उद्योग का एकाधिकार बनेगा और विटामिन सी के परिष्कृत निर्माणों के विनिर्माताओं तथा कुल मिलाकर जनता और उपभोक्ताओं की हानि के लिए वे कीमतें बढ़ाने में सक्षम होंगे, वह भी उस नाजुक अवधि में जब देश महामारी से लड़ रहा है। इससे चुनिंदा भारतीय "विटामिन सी" विनिर्माता अत्यधिक लाभ प्राप्त करेंगे, परंतु भारतीय फार्मास्यूटिकल उद्यमों, खाद्य उद्यमों और पेय पदार्थ उद्यमों के लाभ को हानि पहुँचाएंगे और उपभोक्ताओं के संबंध में कोई उल्लेख ही नहीं है।
- चच. भारत में इस उत्पाद की सही मांग-आपूर्ति स्थिति की जांच इस मामले में आगे कार्रवाई करने से पूर्व की जाए, ताकि भारत में आम जनता विटामिन सी टेबलेट से वंचित न हो।
- छछ. यदि पाटनरोधी शुल्क लगाया जाता है तो घरेलू उद्योग के पाटनरोधी शुल्क की राशि तक अपनी कीमत बढ़ाने की संभावना है। अतः आयातित तथा भारत में उत्पादित उत्पाद दोनों महंगे हो जाएंगे और उपभोक्ताओं को अधिक कीमत की लागत वहन करनी पड़ेगी।

## च.2 घरेलू उद्योग के विचार

31. विविध अनुरोधों के संबंध में आवेदक द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- क. संबद्ध देशों के निर्यातकों ने दो बार उत्तर दायर करने के लिए समय बढ़वाया। फिर भी निर्यातक ने प्रश्नावली का उत्तर दायर करने के लिए 84 दिन लगाए।
- ख. जांच की अवधि लॉकडाउन की शुरुआत में समाप्त हो गई, अतः कोविड-19 से लगे लॉकडाउन के दौरान मांग में उछाल का याचिका में कोई संदर्भ नहीं दिया गया।
- ग. जनहित कारकों से निर्यातकों को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि भारत का हित उनकी कोई चिंता नहीं है।
- घ. प्राधिकारी की किसी नई जांच में जांच की अवधि के बाद की क्षति का विश्लेषण करने की परिपाटी नहीं है।
- ङ. मैसर्स अबॉट इंडिया लि. ने कभी भी अपने संविदागत दायित्वों को पूरा नहीं किया और अपनी सुविधा के अनुसार वे आदतन अपने संविदागत दायित्वों से हटते रहे। बिक्री खरीद संविदागत बातचीतों के आधार पर होती है जो वर्ष में बेची जाने वाली पूरी सहमत मात्रा के लिए आवेदक द्वारा अपनाई जाती है।
- च. पाटनरोधी शुल्क लगाने से अंतिम उत्पाद पर कोई महत्वपूर्ण प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा और शुल्क लगाना व्यापक जनहित में होगा। पाटनरोधी शुल्क अन्य देशों में उत्पादकों द्वारा अनुचित कीमत भेदभाव का समाधान है जो भारत में उद्योग के लिए हानिकारक है।
- छ. डीपीसीओ के तहत लगाई गई कीमत सीमा निर्माण के लिए है, न कि एपीआई अथवा थोक औषधियों पर।
- ज. घरेलू उद्योग बाजार दरों और बाजार में विद्यमान उचित प्रतिस्पर्धा के कारण अपनी कीमतें अनुचित रूप से नहीं बढ़ाएंगे। वस्तुतः घरेलू उद्योग कोविड संकट के समय अग्रणी स्थान पर रहा है और देश के नागरिकों द्वारा प्रयोग के लिए उसने उस उत्पाद की आपूर्ति की है।

- झ. उत्तरदाता निर्यातकों ने मौखिक सुनवाई के समय पहली बार विभिन्न स्थानों पर भिन्न-भिन्न आंकड़ों के संबंध में चिंता उठाई है। आवेदक ने दिनांक 9 मार्च, 2021 के मेल द्वारा इन विसंगतियों को दूर किया।
- ञ. उत्पादकों/निर्यातकों का अपना यह तर्क है कि पाटनरोधी शुल्क इतनी लम्बी अवधि के लिए लागू था। यद्यपि वर्तमान जांच एक नई जांच है, तथापि उत्पाद पर कुछ समय से पाटनरोधी शुल्क लग रहा था। पाटनरोधी शुल्क का प्रतिकूल प्रभाव किसी भी पक्षकार द्वारा सिद्ध नहीं किया जा सका।
- ट. यहां तक कि शुल्क लागू रहा है, उत्पाद की न तो कमी थी, न ही वहन करने योग्य कीमत थी और न ही उपभोक्ताओं पर काफी प्रतिकूल प्रभाव था। यह सिद्ध है कि हितबद्ध पक्षकार गलत विवरणों और असिद्ध दावों का सहारा ले रहे हैं।
- ठ. घरेलू उत्पादक बाजार दलों और उच्च प्रतिस्पर्धा के कारण अपनी कीमतों में अनुचित वृद्धि नहीं करेंगे और भारत के लोगों को दवाईयों की अबाधित आपूर्ति करने के लिए संकट के इस समय में आगे खड़े रहे हैं। इसके अतिरिक्त, इससे उपयुक्त कीमतों पर प्रयोक्ताओं के लिए बहु-विध घरेलू स्रोतों की निरंतर उपलब्धता होगी।
- ड. शुल्क लगाए जाने के बाद भी, मुक्त, उचित और उपयुक्त प्रतिस्पर्धा बाजार में विद्यमान रहेगी जिससे यह सुनिश्चित होगा कि शुल्क लगाना व्यापक जनहित में होगा।
- ढ. निर्यातकों/उत्पादकों को इससे अलग रहना चाहिए कि क्या पाटन हो रहा है। इन जनता के हित के कारकों से विदेशी उत्पादकों को परेशान नहीं होना चाहिए। घरेलू उद्योग जिम्मेदार और उत्तरदायी हैं।
- ण. चीन से आयात सबसे हाल की अवधि में बढ़े हैं, न कि उस समय जब कोविड-19 अपने पीक पर था। इसके विपरीत, जब कोविड-19 अपने पीक पर था, आयात मात्रा कम थी और कीमत अधिक थी।
- त. जब आयात कीमत में गिरावट आई, तो आयात मात्राओं में वृद्धि हुई है। यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि चीनी उत्पादकों का कोविड-19 की अवधि के दौरान भारत की मांग से बहुत कम संबंध था।
- थ. एक बार जब उनकी अपनी आंतरिक आवश्यकताएं पूरी हो गई हैं और कोविड-19 चल रहा था, तो चीनी उत्पादक भारत में कोविड-19 की स्थिति के प्रति जाग गए, कीमतें घटा दीं और भारी मात्रा में पाटन किया। यह भी दर्शाता है कि चीनी उत्पादकों की कार्यवाहियां विवरणों से भिन्न हैं।

### च.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

32. प्राधिकारी ने कानूनी प्रावधानों और हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दिए गए साक्ष्य को ध्यान में रखते हुए विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों की जांच की है और उन पर विचार किया है।
33. इस तर्क के संबंध कि समीक्षा याचिका दायर करने के बजाए नया आवेदन पत्र दायर किया गया है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि आवेदक ने निर्णायक समीक्षा (एसएसआर) के लिए आवेदन पत्र दायर किया। तथापि, प्राधिकारी द्वारा उसे तकनीकी आधार पर स्वीकार नहीं किया गया था क्योंकि वह निर्णायक समीक्षा आवेदन पत्र दायर करने के लिए निर्धारित समय सीमा से बाहर था।
34. चूंकि वर्तमान जांच एक नई जांच है, अतः प्राधिकारी जांच की अवधि के बाद के आंकड़ों पर विचार नहीं करते। इसके अतिरिक्त, बाद की अवधि में हुई घटनाओं को हल करने के लिए नियमावली के तहत समीक्षा के प्रावधान हैं।
35. घरेलू उत्पादकों की 2 केजीए के लिए चीन पर निर्भरता के संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि 2-केटोग्लुकोनिक एसिड से विटामिन सी में उत्पादन होता है और इसमें काफी मूल्यवर्धन शामिल होता है। इसके अतिरिक्त, कच्ची सामग्री की कीमतों में अस्थिरता अथवा विनिमय दरों में अस्थिरता से कच्ची सामग्री और परिष्कृत उत्पाद, दोनों की कीमत प्रभावित होने की उम्मीद होती है। यह सिद्ध नहीं है कि इन परिवर्तनों से चुनिंदा रूप से अकेले उत्पाद की लाभप्रदता कैसे प्रभावित हो सकती है।
36. घरेलू उत्पादकों की 2 केजीए का उत्पादन करने की असमर्थता के संबंध में प्राधिकारी मानते हैं कि यह वर्तमान जांचों के क्षेत्र से बाहर है।

37. घरेलू उद्योग के संभावित एकाधिकार संबंधी तर्क के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि भारत में विटामिन सी के चार विनिर्माता हैं जो इस प्रकार काफी घरेलू प्रतिस्पर्धा दर्शा रहे हैं। इसके अतिरिक्त, बाद की अवधियों में घटनाओं को हल करने के लिए नियमावली के तहत समीक्षा प्रावधान हैं।
38. प्राधिकारी ने नोट किया है कि भारत और चीन की विटामिन सी थोक औषधि के विनिर्माता हैं। विश्व में अन्य देश, विटामिन सी थोक औषधि की खरीद भारत और चीन से करते हैं और निर्माण की बिक्री करते हैं।
39. इस तर्क के संबंध में कि पाटनरोधी शुल्क से उचित दर पर उत्पाद की उपलब्धता प्रतिबंधित होगी, प्राधिकारी नोट करते हैं कि किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने यह नहीं दर्शाया है कि विगत में पाटनरोधी शुल्क से कैसे अंतिम उत्पाद की कीमत और अंततः जनता प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुई है। इसके अतिरिक्त, विटामिन सी डीपीसीओ के तहत आता है और इसीलिए अंतिम उत्पाद की कीमतें विनियमित की जाती हैं।
40. आवेदक द्वारा दिए गए क्षति आंकड़ों के विरोधी सेट के संबंध में, यह नोट किया जाता है कि उसे घरेलू उद्योग ने ठीक कर दिया था। यह भी नोट किया जाता है कि अंतर काफी नहीं हैं। किसी भी दशा में प्राधिकारी ने उस सूचना का स्वीकार किया है जिसकी सुदूर परस्पर जांच की गई है।
41. जहां तक जनहित के तर्क का संबंध है, यह नोट किया जाता है कि पाटनरोधी शुल्क का प्रयोजन पाटन की अनुचित परिपाटी को हल करना ही है।

**छ. बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार (एमईटी), सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन का निर्धारण**

42. अधिनियम की धारा 9क(1)(ग) के अधीन, किसी वस्तु के संबंध में सामान्य मूल्य का तात्पर्य है:
  - (i) व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की तुलनीय कीमत जब वह उप नियम (6) के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित निर्यातक देश या क्षेत्र में खपत के लिए नियत हो, अथवा
  - (ii) जब निर्यातक देश या क्षेत्र के घरेलू बाजार में व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की कोई बिक्री न हुई हो अथवा जब निर्यातक देश या क्षेत्र की बाजार विशेष की स्थिति अथवा उसके घरेलू बाजार में कम बिक्री मात्रा के कारण ऐसी बिक्री की उचित तुलना न हो सकती हो तो सामान्य मूल्य निम्नलिखित में से कोई एक होगा:-
    - (क) समान वस्तु की तुलनीय प्रतिनिधिक कीमत जब उसका निर्यात उप-धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार निर्यातक देश या क्षेत्र से या किसी उचित तीसरे देश से किया गया हो; अथवा उपधारा- (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित प्रशासनिक, बिक्री और सामान्य लागत एवं लाभ हेतु उचित वृद्धि के साथ उद्गम वाले देश में उक्त वस्तु की उत्पादन लागत;
    - (ख) परंतु यदि उक्त वस्तु का आयात उद्गम वाले देश से भिन्न किसी देश से किया गया है और जहां उक्त वस्तु को निर्यात के देश से होकर केवल यानांतरण किया गया है अथवा ऐसी वस्तु का उत्पादन निर्यात के देश में नहीं होता है, अथवा निर्यात के देश में कोई तुलनीय कीमत नहीं है, वहां सामान्य मूल्य का निर्धारण उद्गम वाले देश में उसकी कीमत के संदर्भ में किया जाएगा।

**छ.1 घरेलू उद्योग के विचार**

43. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के निर्धारण के संबंध में आवेदक द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:
  - क. चीन को पूर्व मामलों में प्राधिकारी द्वारा ली गई स्थिति के अनुसार और अन्य देशों में जांचकर्ता प्राधिकारियों द्वारा ली गई स्थिति के अनुरूप गैर-बाजार अर्थव्यवस्था माना जाना चाहिए।
  - ख. चीनी उत्पादकों की लागत और कीमत पर सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए विश्वास नहीं किया जा सकता और तदनुसार सामान्य मूल्य नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित किया जाना चाहिए।

- ग. आवेदक ने सार्वजनिक पटल पर उपलब्ध कच्ची सामग्री की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के आधार पर और बिक्री, सामान्य एवं प्रशासनिक व्यय और लाभ की उपयुक्त राशि के साथ विधिवत समायोजित घरेलू उद्योग की परिवर्तन लागत पर विचार करके संबद्ध सामानों का सामान्य मूल्य निर्धारित किया है।
- घ. निर्यात कीमत डीजीसीआईएंडएस, कोलकाता द्वारा दिए गए लेन-देन वार आयात आंकड़ों के आधार पर है। निर्यात कीमत सीआईएफ मूल्य होने के नाते और सामान्य मूल्य कारखानागत स्तर पर होने के नाते निर्यात कीमतें, समुद्री भाड़ा, समुद्री बीमा, कमीशन, अंतर्देशीय भाड़ा व्यय, पत्तन व्यय, बैंक प्रभारों और वैट के लिए समायोजित की गई हैं।
- ङ. किए गए दावे का तब तक कोई आधार नहीं है जब तक निर्यात कीमत के लिए उत्तरदाता निर्यातकों द्वारा दिए गए आंकड़े हर तरह से पूरे न हों। इसके अतिरिक्त, प्राधिकारी को पहले यह निर्धारित करना चाहिए कि क्या इतनी देरी से दिए गए उत्तर को स्वीकार किया जाना चाहिए।
- च. संबद्ध देश से आयातों का पाटन मार्जिन केवल न्यूनतम स्तरों से अधिक नहीं है बल्कि काफी है।

## छ.2 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

44. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के निर्धारण के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:
  - क. निर्यात कीमत, पहुँच कीमत और पाटन मार्जिन निर्यातक प्रभावली के उत्तरों में प्रस्तुत आंकड़ों के आधार पर निर्धारित की जानी चाहिए।
  - ख. एक प्रमुख उत्पादक/निर्यातक सीएसपीसी उस स्तर/दर तक भारत को निर्यात के प्रयोजन के लिए बिक्री कीमत में संशोधन करता है जिससे प्राधिकारी के अनुसार "विटामिन सी" का पाटन नहीं होता और घरेलू उद्योग को क्षति का समाधान करता है। दूसरे शब्दों में, सीएसपीसी "विटामिन सी" की बिक्री कीमत निर्धारित रखता है।
  - ग. चीन जन. गण. के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण पूरी तरह से त्रुटिपूर्ण और आधारहीन है क्योंकि यह आवेदक द्वारा दी गई सूचना के आधार पर है, जो भारतीय घरेलू उद्योग में एकाधिकार बना रहा है और शुल्क का प्रमुख लाभग्राही है।
  - घ. चीन से बिक्री कीमत लागत से अधिक है। सन् 2018 से 2020 तक, प्रत्येक चीनी कारखाना जो सामान्य प्रचालन में है, इस उत्पाद से धन अर्जित करता है जिसे वितीय रिपोर्टों के माध्यम से सिद्ध किया जा सकता है। साथ ही, चीन से अन्य देशों को औसत निर्यात कीमत भारत को निर्यातित विटामिन सी की औसत कीमत की तरह समान है। केवल भारत पाटनरोधी शुल्क लगाता है जो डब्ल्यूटीओ के मानदंडों के विरुद्ध है।
  - ङ. रिकॉर्ड में उपलब्ध सामग्री, यह सिद्ध नहीं करती कि "विटामिन सी" का निर्यात उसके सामान्य मूल्य से कम कीमत पर है।
  - च. चीन जन. गण. को गैर-बाजार अर्थव्यवस्था मानने के बात त्रुटिपूर्ण है।
  - छ. संबद्ध सामानों के उत्पादन में प्रयुक्त मुख्य कच्ची सामग्री 2 केजीए सामान्य मूल्य के परिकलन का आधार नहीं बननी चाहिए। 2 केजीए में संबद्ध सामानों के उत्पादन की लागत का लगभग 50 प्रतिशत होता है, 2 केजीए की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों का प्रयोग सामान्य मूल्य को ऊपर की ओर तिरछा करेंगे। प्राधिकारी को चाहिए कि वे चीन के लिए सामान्य मूल्य निर्मित करते समय 2 केजीए के आयात से संबंधित उपर्युक्त इनपुट खरीद लागत और सहायक लागत को समायोजित करें।
  - ज. यह प्रथम दृष्टया विचार बनाने का कोई आधार/साक्ष्य नहीं है कि चीन जन. गण. से विचाराधीन उत्पाद भारतीय बाजार में पाटित किया जा रहा है। "पाटन मार्जिन" जो कि सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत के बीच का अंतर है, निकालने के लिए आधार पूर्णतः असंगत है और उस पर कार्रवाई नहीं की जा सकती।
  - झ. भारत में उत्पाद लागत के आधार पर निर्मित सामान्य मूल्य अनुमत्य नहीं है।

- ज. चीनी विनिर्माता जब विटामिन सी का निर्यात करते हैं, तो वे चीनी सरकार से 13 प्रतिशत कर वापस प्राप्त करते हैं। अतः यह तर्क कि निर्यात कीमत सामान्य कीमत पर नहीं है, केवल 13 प्रतिशत की सीमा तक है।
- ट. प्राधिकारी इस अनुरोध में उस उत्पादक/निर्यातक के लिए अलग-अलग पाटन एवं क्षति मार्जिन निर्धारित करें, जिसने इस मामले में निर्यातक प्रश्नावली के उत्तर दायर किए हैं।

### छ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

#### छ.3.1 सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत का निर्धारण

##### चीनी उत्पादकों का बाजार अर्थव्यवस्था स्तर

45. चाइनीज एसेसन प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 15 में निम्नलिखित प्रावधान है: "जीएटीटी का अनुच्छेद-VI, टैरिफ और व्यापार पर सामान्य समझौता, 1994 ("पाटनरोधी समझौता") के अनुच्छेद-VI के कार्यान्वयन पर समझौता तथा एससीएम समझौता निम्नलिखित के अनुरूप डब्ल्यूटीओ सदस्यों में चीन मूल के आयातों वाली कार्यवाहियों पर लागू होंगे:

- (क) जीएटीटी के अनुच्छेद-VI और पाटनरोधी समझौते के तहत मूल्य की तुलना का निर्धारण करने में आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य या तो जांचाधीन उद्योग के लिए चीन के मूल्यों अथवा लागतों का उपयोग करेंगे या उस पद्धति को उपयोग करेंगे जो निम्नलिखित के आधार पर चीन में घरेलू मूल्यों अथवा लागतों के साथ सख्ती से तुलना करने में आधारित नहीं है:
- (i) यदि जांचाधीन उत्पादक साफ-साफ यह दिखा सकते हैं कि समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग में उस उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां रहती हैं तो निर्यात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य मूल्य की तुलनीयता का निर्धारण करने में जांचाधीन उद्योग के लिए चीन के मूल्यों अथवा लागतों का उपयोग करेगा।
- (ii) आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य उस पद्धति का उपयोग कर सकता है जो चीन में घरेलू कीमतों अथवा लागतों के साथ सख्त अनुपालन पर आधारित नहीं है, यदि जांचाधीन उत्पादक साफ-साफ यह नहीं दिखा सकते हैं कि उस उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग हैं।
- (ख) एससीएम समझौते के पैरा II, III और V के अंतर्गत कार्यवाहियों में अनुच्छेद 14(क), 14(ख), 14(ग) और 14(घ) में निर्धारित राजसहायता को बताते समय एससीएम समझौते के प्रासंगिक प्रावधान लागू होंगे, तथापि, उसके प्रयोग करने में यदि विशेष कठिनाईयां हों, तो आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य राजसहायता लाभ की पहचान करने और उसको मापने के लिए तब पद्धति का उपयोग कर सकते हैं जिसमें उस संभावना को ध्यान में रखती है और चीन में प्रचलित निबंधन और शर्तें उपयुक्त बेंचमार्क के रूप में सदैव उपलब्ध नहीं हो सकती हैं। ऐसी पद्धतियों को लागू करने में, जहां व्यवहार्य हो, आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य के द्वारा चीन से बाहर प्रचलित निबंधन और शर्तों का उपयोग के बारे में विचार करने से पूर्व ऐसी विद्यमान निबंधन और शर्तों को ठीक करना चाहिए।
- (ग) आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य उप-पैरा (क) के अनुसार प्रयुक्त पद्धतियों को पाटनरोधी कार्य समिति के लिए अधिसूचित करेगा तथा उप पैराग्राफ (ख) के अनुसार प्रयुक्त पद्धतियों को कमिटी ऑन सब्सिडीज और काउंटर वेलिंग मैसर्स के लिए अधिसूचित करेगा।
- (घ) आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य को राष्ट्रीय कानून के तहत चीन ने एक बार यह सुनिश्चित कर लिया है कि यह एक बाजार अर्थव्यवस्था है, तो उप पैराग्राफ के प्रावधान (क) समाप्त कर दिए जाएंगे, बशर्ते आयात करने वाले सदस्य के राष्ट्रीय कानून में प्राप्ति की तारीख के अनुरूप बाजार अर्थव्यवस्था संबंधी मानदंड हो। किसी भी स्थिति में उप पैराग्राफ (क)(ii) के प्रावधान प्राप्ति की तारीख के बाद 15 वर्षों में समाप्त होंगे। इसके अलावा, आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य के राष्ट्रीय कानून के अनुसरण में चीन के द्वारा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां एक विशेष उद्योग अथवा क्षेत्र में प्रचलित हैं, उप पैराग्राफ (क) के गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के प्रावधान उस उद्योग अथवा क्षेत्र के लिए आगे लागू नहीं होंगे।"



46. यह नोट किया जाता है कि यद्यपि अनुच्छेद 15(क)(ii) में निहित प्रावधान 11 दिसंबर, 2016 को समाप्त हो गए हैं, तथापि अभिगम नयाचार के 15(क)(i) के अंतर्गत दायित्व के साथ पठित डब्ल्यूटीओ के अनुच्छेद 2.2.1.1 के अंतर्गत प्रावधान में नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 8 में निर्धारित मापदंड को बाजार अर्थव्यवस्था के स्तर का दावा करने के संबंध में पूरक प्रश्नावली में दी जाने वाली सूचना/आंकड़ों के माध्यम से पूरा किया जाना अपेक्षित है। यह नोट किया जाता है कि चूंकि चीन जन. गण. से किसी भी उत्तरदाता उत्पादक/निर्यातक ने संगत प्रश्नावली के उत्तर प्रस्तुत नहीं किए हैं, अतः सामान्य मूल्य का परिकलन नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित किए जाने की आवश्यकता है। तदनुसार, संबद्ध देश के इन उत्पादकों/निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत निम्नलिखित रूप में निर्धारित की गई है।

### छ.3.2 चीन जन. गण. के सभी उत्पादकों के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण

47. निम्नलिखित चीनी उत्पादकों/निर्यातकों ने बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार (एमईटी) प्रश्नावली का उत्तर दायर किया है और बाजार अर्थव्यवस्था स्तर का दावा किया है:
- क. मैसर्स सीएसपीसी वीशेंग फार्मास्युटिकल (शीजियाझुआंग) कं. लि.
48. नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 में निर्धारित किए गए अनुसार, अन्य पद्धतियों के संबंध में रिकॉर्ड में पर्याप्त सूचना के अभाव में प्राधिकारी ने *"उपयुक्त लाभ मार्जिन शामिल करने के लिए आवश्यक होने पर विधिवत समायोजित समान उत्पाद के लिए भारत में वास्तव में प्रदत्त अथवा देय कीमत सहित किसी अन्य उपयुक्त आधार"* पर पद्धति पर विचार करते हुए सामान्य मूल्य निर्धारित किया है।
49. सिंगापुर से भी संबद्ध सामानों के आयात हैं, तथापि रिकॉर्ड में उपलब्ध सूचना के अनुसार सिंगापुर में संबद्ध सामान के विनिर्माण के लिए कोई उत्पादन सुविधा नहीं है। अतः प्राधिकारी ने नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 के दूसरे परंतुक के अनुसार उपलब्ध तथ्यों के आधार पर और बिक्री, सामान्य एवं प्रशासनिक व्यय और उपयुक्त लाभ में अभिवृद्धि के साथ विधिवत समायोजित घरेलू उद्योग की परिवर्तन लागत पर विचार करते हुए चीन जन. गण. के लिए सामान्य मूल्य निर्मित किया है। तदनुसार, चीनी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए इस प्रकार निर्धारित निर्मित सामान्य मूल्य निम्नलिखित पाटन मार्जिन तालिका में उल्लिखित है।

### छ.3.3 निर्यात कीमत का निर्धारण

#### क. मैसर्स शानडोंग लूवी फार्मास्युटिकल कं. लि.

50. मै. शानडोंग लुवेई फार्मास्युटिकल कं. लि. चीन जन.गण. में संबद्ध वस्तुओं का एक उत्पादक है और इसने भारत को इस उत्पाद का निर्यात किया है। यह नोट किया जाता है कि जांच की अवधि के दौरान मै. शानडोंग लुवेई फार्मास्युटिकल कं. लि. ने यह दावा किया है कि इसने भारत में असंबंधित ग्राहकों को प्रत्यक्ष तौर पर संबद्ध वस्तुओं का \*\*\*एमटी का निर्यात किया है। प्रकटन विवरण में, सीआईएफ निर्यात कीमत का निर्धारण प्रस्तुत की गई प्रश्नावली के उत्तर के आधार पर किया गया था और अंतरदेशीय भाड़ा, समुद्री भाड़ा, बीमा, पोत और अन्य संबंधित खर्च तथा बैंक शुल्क के प्रति समायोजन किया गया था, जिसके ब्यौरे की जांच संभव सीमा तक रिमोट क्लास चेक/डेस्क सत्यापन के माध्यम से किया गया था। तदनुसार मै. शानडोंग लुवेई फार्मास्युटिकल कं. लि. के लिए एक्स-फैक्टरी स्तर पर विचाराधीन उत्पाद के लिए निवल निर्यात कीमत का निर्धारण किए जाने का प्रस्ताव किया जाता है।
51. हितबद्ध पक्षकारों को प्रकटन विवरण जारी किए जाने के बाद, चीन के अन्य उत्पादक अर्थात् मै. सीएसपीसी ने चीन की सीमा शुल्क के अनुसार निर्यात ब्यौरे का हवाला देकर यह आरोप लगाया कि मै. शानडोंग लुवेई फार्मास्युटिकल कं. लि. ने भारत को अपने निर्यात के संबंध में पूर्ण/तथ्यात्मक आंकड़े की सूचना नहीं दी है और इस कारण से इसके फलस्वरूप संदिग्ध तरीके से कमतर मार्जिन रहा है। इसके अलावा, घरेलू उद्योग ने मै. साइनोराइट इंटरनेशनल ट्रेड कंपनी लि. द्वारा किए गए निर्यातों का प्रविष्टि-वार बिल का ब्यौरा प्रस्तुत कर यह आरोप लगाते हुए समान टिप्पणियां प्रस्तुत की हैं कि शानडोंग लुवेई फार्मास्युटिकल ने भी चीन के एक असंबंधित कंपनी/व्यापारी अर्थात् मै साइनोराइट इंटरनेशनल ट्रेड कंपनी लि. के माध्यम से जांच की अवधि के दौरान भारत को संबद्ध वस्तुओं की बिक्री की है। इसके अलावा, घरेलू उद्योग ने यह उल्लेख करते हुए दस्तावेज प्रस्तुत किए कि शानडोंग लुवेई फार्मास्युटिकल ने अपने एजेंट के रूप में साइनोराइट इंटरनेशनल ट्रेड की नियुक्ति की है और इस

दस्तावेज में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि “शानडोंग लुवेई फार्मास्युटिकल कं. लि. एतद्वारा एसकोरबि एसिड के लिए वाणिज्यिक क्रियाकलाप, विपणन और बिक्री के वास्ते भारत में अनन्य एजेंट के रूप में मै. साइनोराइट इंटरनेशनल ट्रेड कं. लि. को अधिकृत करता है”। इसमें निहित महत्वपूर्ण तथ्यों पर विचार करते हुए, प्राधिकारी ने मै. शानडोंग लुवेई फार्मास्युटिकल कं. लि. को उपर्युक्त के संबंध में अपनी टिप्पणियां देने के लिए अवसर दिया जिसका उत्तर कंपनी ने यह दिया कि शानडोंग लुवेई फार्मास्युटिकल द्वारा अपने एजेंट के रूप में साइनोराइट इंटरनेशनल ट्रेड की नियुक्ति करने संबंधी करार को बाद में कंपनी द्वारा रद्द कर दिया गया था। इसके अलावा, प्राधिकारी ने जवाहरलाल नेहरू कस्टम हाउस (राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय) के कार्यालय और केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय) के कार्यालय से वाणिज्यिक बीजकों, पैकिंग सूची, मूलता प्रमाण-पत्र आदि तथा फार्म 9 और 10 सहित प्रविष्टि बिल के ब्यौरे की मांग की। उसकी जांच करने के बाद, यह निष्कर्ष निकाला गया है कि शानडोंग लुवेई फार्मास्युटिकल कं. लि. ने भारत को किए गए सभी निर्यातों की सूचना नहीं दी है और भारत को किए गए सभी निर्यातों को ईमानदारी से नहीं बताया है। इस कारण से, प्राधिकारी ने कंपनी द्वारा प्रस्तुत किए गए उत्तर को अस्वीकार किया है तथा कंपनी के लिए अलग-अलग पाटन मार्जिन का निर्धारण नहीं किया है।

**ख. मैसर्स सीएसपीसी वीशेंग फार्मास्युटिकल (शीजियाझुआंग) कं. लि. और मैसर्स सिनोब्राइट फार्मास्युटिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड**

52. मैसर्स सीएसपीसी वीशेंग फार्मास्युटिकल (शीजियाझुआंग) कं. लि. चीन जन. गण. में संबद्ध सामानों का एक उत्पादक है और उसने भारत को सीधे ही तथा मैसर्स सिनोब्राइट फार्मास्युटिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड (असंबद्ध निर्यातक) के माध्यम से भी इस उत्पाद का निर्यात किया है। उत्तर प्राप्त होने के बाद, एक कमी वाला तथ्य उत्पादक को भेजा गया था जिसमें उनसे कहा गया था कि वे उन कमियों को ठीक करें। उत्पादक ने इन कमियों को ठीक कर दिया है। यह नोट किया जाता है कि जांच की अवधि के दौरान मैसर्स सीएसपीसी वीशेंग फार्मास्युटिकल (शीजियाझुआंग) कं. लि. ने भारत को सीधे ही \*\*\* मी. टन संबद्ध सामानों का निर्यात किया है और असंबद्ध निर्यातक के माध्यम से अन्य \*\*\* मी. टन का निर्यात किया है। सीआईएफ निर्यात कीमत दायर प्रश्नावली के उत्तर के आधार पर निर्धारित की गई है। सीआईएफ निर्यात कीमत समुद्री भाड़ा, अंतर्देशीय परिवहन, पत्तन एवं अन्य संबंधित व्यय, बैंक प्रभारों के निमित्त समायोजित की गई है जिसके ब्यौरों की जांच व्यवहार्य सीमा तक सुदूर परस्पर जांच/डेस्क सत्यापन के माध्यम से की गई थी। तदनुसार, मैसर्स सीएसपीसी वीशेंग फार्मास्युटिकल (शीजियाझुआंग) कं. लि. के लिए कारखानागत स्तर पर विचाराधीन उत्पाद के लिए निवल निर्यात कीमत निर्धारित की गई है और पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाई गई है।

**चीन जन. गण. के सभी अन्य उत्पादकों/निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत**

53. चीन जन. गण. के अन्य सहयोगी निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत चीन के सहयोगी निर्यातकों के आंकड़ों और डीजीसीआईएंडएस के आयात आंकड़ों को ध्यान में रखते हुए उपलब्ध तथ्यों के अनुसार निर्धारित की गई है।

**i. पाटन मार्जिन**

54. उपर्युक्त निर्धारित सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत के आधार पर, चीन जन. गण. के उत्पादकों/निर्यातकों के लिए पाटन मार्जिन निर्धारित किया गया है और वह निम्नलिखित तालिका में दिया गया है।

उत्पादक	सामान्य मूल्य (अमे. डॉ./ कि. ग्रा.)	निर्यात कीमत (अमे. डॉ./ कि. ग्रा.)	पाटन मार्जिन (अमे. डॉ./ कि. ग्रा.)	पाटन मार्जिन %	पाटन मार्जिन रेंज
मैसर्स सीएसपीसी वीशेंग फार्मास्युटिकल (शीजियाझुआंग) कं. लि.	***	***	***	***	110-120
अन्य	***	***	***	***	120-130

**ज. क्षति और कारणात्मक संपर्क****ज.1 घरेलू उद्योग के विचार**

55. क्षति और कारणात्मक संपर्क के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोधों का सार निम्नलिखित है:

- क. संबद्ध देश से आयातों में जांच की अवधि के दौरान आयातों में थोड़ी सी गिरावट के साथ क्षति की अवधि में वृद्धि हुई थी।
- ख. उत्पादन की तुलना में आयातों में जांच की अवधि में थोड़ी सी गिरावट के साथ क्षति की अवधि में वृद्धि हुई थी और खपत के संबंध में आयातों में 2017-18 तक वृद्धि हुई और उसके बाद जांच की अवधि तक गिरावट आई।
- ग. संबद्ध सामानों के लिए मांग में जांच की अवधि के दौरान आयातों में थोड़ी सी गिरावट के साथ पूरी क्षति अवधि में निरंतर वृद्धि हुई थी।
- घ. संबद्ध देश से आयातों के बाजार हिस्से में गिरावट आई है, जबकि अन्य देशों के बाजार में हिस्से में क्षति की अवधि में वृद्धि हुई है।
- ङ. आयातों की पहुँच कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से काफी कम है। आयात घरेलू उद्योग की कीमतों की कटौती कर रहे हैं।
- च. आयात बाजार में उत्पाद की कीमतों का काफी ह्रास कर रहे हैं।
- छ. घरेलू उद्योग के उत्पादन में 2017-18 में क्षमताओं की अभिवृद्धि के साथ 2018-19 तक वृद्धि हुई, परंतु जांच की अवधि में उत्पादन में गिरावट आई।
- ज. घरेलू बिक्री में 2018-19 तक वृद्धि हुई, परंतु जांच की अवधि में उसमें गिरावट आई।
- झ. क्षमता उपयोग में 2018-19 तक वृद्धि हुई, परंतु जांच की अवधि में उसमें गिरावट आई।
- ञ. घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा क्षति की अवधि में कम हुआ था; तथापि संबद्ध देश से संबद्ध आयातों के बाजार हिस्से में 2018-19 में वृद्धि हुई है जिसमें जांच की अवधि में थोड़ी सी गिरावट आई और अन्य देशों से आयातों में क्षति की अवधि में वृद्धि हुई है।
- ट. घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में 2018-19 तक वृद्धि हुई और उसके बाद जांच की अवधि में तेजी से गिरावट आई। निवेश पर आय और नकद लाभ ने लाभप्रदता की तरह ही वही प्रवृत्ति अपनाई है। आयात कीमतों में तेजी से गिरावट के कारण अब लाभप्रदता में गिरावट आई है।
- ठ. घरेलू उद्योग ने मालसूची 2017-18 तक कम हो रही थी, परंतु उसके बाद उसमें वृद्धि हुई।
- ड. घरेलू उद्योग की प्रतिदिन उत्पादकता में पूरी क्षति की अवधि में वृद्धि हुई है।
- ढ. रोजगार और मजदूरी ने प्रस्तावित क्षति अवधि में समग्र सुधार दर्शाया है।
- ण. घरेलू उद्योग ने मात्रात्मक एवं कीमत मानदंडों दोनों के संदर्भ में जांच की अवधि में गिरावट के साथ समग्र वृद्धि दर्ज की है। विभिन्न मानदंडों, यथा – बिक्री मात्रा, बिक्री मूल्य, कीमतों, उत्पादन मात्रा, क्षमता उपयोग, लाभ, नकद लाभ, निवेश पर आय ने 2018-19 तक सकारात्मक वृद्धि दर्शाई और जांच की अवधि में गिरावट दर्शाई। लाभ, नकद लाभ और निवेश पर आय में वृद्धि जांच की अवधि में काफी नकारात्मक थी।
- त. घरेलू उद्योग के निष्पादन में वर्तमान जांच की अवधि में उस समय भी ह्रास हुआ, जब पाटनरोधी शुल्क लागू है।
- थ. यहां तक कि यदि एनआईपी एनएसआर से अधिक नहीं है, तो उसका अर्थ घरेलू उद्योग को क्षति का अभाव नहीं है।

## ज.2 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

56. क्षति और कारणात्मक संपर्क के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों का सार निम्नलिखित है:
- क. मानी गई जांच की अवधि में पाटनरोधी शुल्क पहले ही मौजूद था और इसीलिए क्षति होने का कोई अवसर नहीं था। पूरा कार्य प्रकृति में यांत्रिक प्रतीत होता है और घरेलू उद्योग को संरक्षित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया प्रतीत होता है तथा आवेदक को उनके पक्ष में एकाधिकार बनाने के लिए संरक्षण प्रदान करने के लिए प्रतीत होता है। इस प्रकार, वर्तमान जांच की शुरुआत के लिए कोई आधार नहीं है।
  - ख. पूरी जांच की शुरुआत क्षति की संभावना के आधार पर है। वास्तविक आंकड़े, जो यदि प्राधिकारी को प्रस्तुत किए जाएं, तो वे पूरी तरह से विपरीत तस्वीर दर्शाएंगे।
  - ग. चीनी उत्पादकों की भारी अधिशेष उत्पादन क्षमताओं के संबंध में दिया गया साक्ष्य यह उल्लेख किए बिना है कि क्या आपूर्ति क्षमता निर्यात के लिए अथवा घरेलू खपत के लिए अथवा भारत को लक्ष्य बनाकर है। सकारात्मक साक्ष्य के अभाव में आवेदक का दावा स्वीकार करने योग्य नहीं है।
  - घ. आवेदक की निर्यात कीमत के संबंध में कोई सूचना नहीं दी गई है। सभी घरेलू उत्पादकों द्वारा निर्यातों की जांच किए जाने की आवश्यकता है।
  - ङ. अन्य देशों से आयातों की जांच किए जाने की आवश्यकता है।
  - च. इस उत्पाद की बहुत अधिक मांग है। इसका औचित्य बताने की कोई आवश्यकता नहीं है।
  - छ. सभी घरेलू उत्पादकों की वार्षिक रिपोर्टों, लेखापरीक्षा रिपोर्टों और आयकर विवरणियों की जांच किए जाने की आवश्यकता है।
  - ज. सभी घरेलू उत्पादकों के कार्यवृत्तों की जांच किए जाने की आवश्यकता है।
  - झ. सभी घरेलू उत्पादकों द्वारा बीएसई और एनएसई में लाभप्रदता की जांच किए जाने की आवश्यकता है। आवेदक भारी लाभ कमा रहा है, जैसा कि आंकड़ों से भी दर्शाया गया है और आगे वह किसी कीमत न्यूनीकरण का सामना नहीं कर रहा है। निवेश पर आय और निवल लाभ में कोई गिरावट तथाकथित पाटित आयात के बजाए असाधारण खर्चों में वृद्धि के कारण है।
  - ञ. 2 केजीए में विटामिन सी की उत्पादन लागत का 50 प्रतिशत है। यह एक कारण है जिससे चीन से आयातों की पहुँच कीमत गिरावट दर्शा रही है।
  - ट. काफी मांग-आपूर्ति अंतराल मौजूद है।
  - ठ. चीनी विनिर्माता अधिक प्रतिस्पर्धी हैं। यह तथ्य घरेलू विनिर्माताओं द्वारा स्वीकार भी किया गया है। यदि चीनी निर्यातक भारतीय बाजार को लेना चाहते तो वे कच्ची सामग्री 2 केजीए की कीमतें बढ़ा सकते थे जिसके परिणामस्वरूप भारतीय थोक औषधि विनिर्माताओं को और भी अधिक क्षति हुई होती। इन परिस्थितियों में चूंकि 2 केजीए के लिए कोई घरेलू विनिर्माता नहीं है, अतः पाटनरोधी जांच की शुरुआत का विकल्प भी उपलब्ध नहीं होगा।
  - ड. प्राधिकारी और घरेलू उद्योग के पास ऐसा कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है कि कोई पाटन हो रहा है, पाटन से क्षति हो रही है और इसीलिए जांच शुरू करने का कोई अवसर नहीं था।
  - ढ. भारत में उत्पादन प्रौद्योगिकी के अनुसार "विटामिन सी" का उत्पादन करने की लागत 2 केजीए का उत्पादन करने की लागत की अपेक्षा दोगुना अधिक है। कच्ची सामग्री (2 केजीए) की कीमतों में अस्थिरता के कारण, घरेलू विनिर्माताओं को हानियाँ हुई हैं।
  - ण. चीनी निर्यातक भारतीय घरेलू विनिर्माताओं की अपेक्षा अधिक लागत प्रतिस्पर्धी हैं।
  - त. दिए गए आंकड़े न तो यह सिद्ध करते हैं कि उन्हें वास्तविक क्षति हुई है और न यही कि शुल्क हटाने पर वास्तविक क्षति बार-बार होने की स्थिति है।
  - थ. चीन जन. गण. से आयातों की मात्रा में कोई पूर्ण वृद्धि नहीं है।

- द. क्षमता और उत्पादन में वृद्धि हुई है। क्षमता उपयोग में कोई गिरावट नहीं है। घरेलू बिक्री मात्रा और मूल्य में भी वृद्धि हुई है। बाजार हिस्से में भी वृद्धि हुई है। घरेलू उद्योग सकारात्मक वृद्धि दर्शा रहा है।
- ध. कोई क्षति नहीं है क्योंकि बाजार हिस्से, लाभ, नियोजित पूंजी पर आय (आरओसीई) और नकद लाभ में कोई गिरावट नहीं थी।
- न. आयातों और वास्तविक क्षति के दावे के बीच कोई कारणात्मक संपर्क नहीं है। क्षति संबंधी आंकड़े केवल आवेदक के लिए दिए गए हैं और उन पर विश्वास नहीं किया जा सकता। आवेदक को अन्य घरेलू उत्पादकों के लिए क्षति संबंधी आंकड़े देने चाहिए थे।
- प. नए व्यापारी उस बाजार में प्रवेश नहीं करेंगे जिसको क्षति हो रही है अथवा लाभप्रद न माना जाता हो। आवेदक के खर्चों में काफी वृद्धि से हुई क्षति की मात्रा आयातों से हुए किसी क्षतिकारक प्रभाव से अलग की जानी चाहिए।
- फ. कोई कीमत कटौती नहीं है। आयातों से कोई कीमत न्यूनीकरण अथवा ह्रास नहीं हुआ है क्योंकि 2 केजीए की कीमत में कमी के कारण बिक्री कीमत तथा उत्पादन लागत में गिरावट आई है। अतः आयातों से काफी मात्रा तक कीमतों का ह्रास नहीं हुआ है अथवा कीमत वृद्धि नहीं रुकी है जो अन्यथा हुई होती।
- ब. "विटामिन सी" की बिक्री कीमत राष्ट्रीय फार्मास्युटिकल कीमत प्राधिकरण (एनपीपीए) द्वारा विनियमित की गई है और कीमतों में किसी वृद्धि की प्रवृत्ति सीमा के अध्यधीन रही है। आवेदक की बिक्री कीमत उसकी उत्पादन लागत से अधिक रही है और आवेदक को कोई हानियां नहीं होनी चाहिए।
- भ. अन्य घरेलू उत्पादकों ने हाल की अवधि में अपनी बिक्री कीमतें बढ़ाई हैं।
- म. मूल्यह्रास, मजदूरी और ब्याज जैसे कुछ व्यय आयातों की अपेक्षा किन्हीं हानियों के लिए उत्तरदायी थे। लाभ और निवेश पर आय में गिरावट आवेदक के उपर्युक्त खर्चों में वृद्धि से जुड़े हैं।
- य. ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदक भारी लाभ में रहा है, परन्तु निवेश में वृद्धि के कारण उसके नकद लाभ में गिरावट रही है।
- कक. प्रमुख कच्ची सामग्री अर्थात् मैथेनॉल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में जांच की अवधि के दौरान 30 प्रतिशत तक तेजी से गिरावट आई। अतः विचाराधीन उत्पाद के लिए घरेलू उद्योग की आयात कीमतों और बिक्री कीमतों में गिरावट आई है।
- खख. पूर्व वर्ष की तुलना में जांच की अवधि के दौरान पूर्ण दृष्टि से और सापेक्ष संदर्भ में तथाकथित आयातों में भारी गिरावट आई है।
- गग. आयातित मात्रा और घरेलू बिक्री में उतार-चढ़ाव रहा है जो बाजार हिस्से में गिरावट के कारण हो सकता है।
- घघ. प्राधिकारी को इसकी पुष्टि करनी चाहिए कि एनआईपी, एनएसआर से अधिक है। चूंकि क्षति मार्जिन और कीमत कटौती की रेंज समान है, अतः दो अतिवार्य संघटक हैं। जांच समान हो सकती है अथवा एनएसआर, एनआईपी से अधिक हो सकती है। प्राधिकारी की सतत परिपाटी के अनुसार यदि एनआईपी, एनएसआर से अधिक है तो प्राधिकारी को जांच रद्द करनी चाहिए।

### ज.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

57. अनुबंध-11 के साथ पठित पाटनरोधी नियमावली के नियम 11 में यह प्रावधान है कि क्षति के निर्धारण में "... पाटित आयातों की मात्रा, समान वस्तुओं के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर उनके प्रभाव और ऐसी वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों पर इस प्रकार के आयातों का परिणामी प्रभाव सहित सभी संगत तथ्यों पर विचार करते हुए ..." घरेलू उद्योग की क्षति को दर्शाने वाले कारकों की जांच शामिल होगी। कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव पर विचार करते हुए, इस बात की जांच करना आवश्यक माना गया है कि क्या भारत में समान वस्तु की कीमत की तुलना में पाटित आयातों द्वारा कीमत में बहुत अधिक कटौती हुई है अथवा क्या इस प्रकार के आयातों का प्रभाव अन्यथा कीमतों का बहुत अधिक मात्रा में ह्रास करना अथवा कीमत में वृद्धि रोकना है जो अन्यथा बहुत अधिक मात्रा में हुई होती। भारत में घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच करने के लिए, उत्पादन, क्षमता

उपयोग, बिक्री मात्रा, मालसूची, लाभप्रदता, निवल बिक्री वसूली, पाटन की मात्रा और मार्जिन आदि जैसे उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले तत्वों पर नियमावली के अनुबंध-II के अनुसार विचार किया गया है।

58. प्राधिकारी ने क्षति और कारणात्मक संपर्क के संबंध में घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों को ध्यान में रखा है और रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों तथा लागू कानूनों को ध्यान में रखते हुए विश्लेषण किया है। यथातथ्यतः किया गया क्षति विश्लेषण घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों को हल करता है।
59. जहां तक घरेलू उद्योग के उनकी वार्षिक रिपोर्ट, लेखापरीक्षा रिपोर्टों, आयकर विवरणों और बीएसई तथा एनएसई में उनकी लाभप्रदता में निष्पादन का संबंध है, यह नोट किया जाता है कि आवेदक कई उत्पादों वाली एक बहु-उत्पाद कंपनी है। उपर्युक्त दस्तावेजों में सूचित लाभ विचाराधीन उत्पाद के लिए घरेलू उद्योग का निष्पादन नहीं दर्शाता। किसी भी दशा में प्राधिकारी ने सत्यापित सूचना के आधार पर वर्तमान निर्धारण किया है।
60. विरोधी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए इस अनुरोध के संबंध में कि निवल बिक्री कीमत (एनएसआर), क्षति रहित कीमत (एनआईपी) से अधिक है, अतः घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि इसका कोई कानूनी प्रावधान नहीं है कि प्राधिकारी को कीमत प्रभाव निर्धारित करने के लिए क्षति रहित कीमत की तुलना निवल बिक्री वसूली से करनी चाहिए।
61. प्राधिकारी नोट करते हैं कि विचाराधीन उत्पाद पर दिनांक 06 अगस्त, 2015 की सीमा शुल्क अधिसूचना संख्या 38/2015-सीमा शुल्क (एडीडी) द्वारा 3.74 अमेरिकी डॉलर/कि.ग्रा. की दर से पाटनरोधी शुल्क लग रहा था जो 05 अगस्त, 2020 तक लागू था। इस प्रकार, पाटनरोधी शुल्क क्षति की लगभग पूरी अवधि के दौरान लागू था। प्राधिकारी का मानना है कि क्षति निर्धारण के प्रयोजन के लिए प्रासंगिक अवधि के दौरान मौजूदा पाटनरोधी शुल्क के तथ्य पर विचार किया जाना अपेक्षित है।

### ज.3.1 पाटित आयातों का मात्रात्मक प्रभाव

#### क. मांग/स्पष्ट खपत का मूल्यांकन

62. वर्तमान जांच के प्रयोजन के लिए, प्राधिकारी ने भारतीय उत्पादकों की घरेलू बिक्री की राशि तथा सभी स्रोतों से आयातों के रूप में भारत में उत्पाद की मांग अथवा स्पष्ट खपत को ध्यान में रखा है।

विवरण	यूओएम	2016-17	2017-18	2018-19	जांच की अवधि
घरेलू उद्योग की बिक्रियां	मी. टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	112	113	100
अन्य उत्पादकों की बिक्रियां	मी. टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	107	102	105
संबद्ध देश से कुल आयात	मी. टन	783	1288	1171	868
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	165	150	111
अन्य देशों से आयात	मी. टन	65	84	253	217
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	130	390	335
कुल मांग/खपत	मी. टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	123	124	109

63. यह देखा जाता है कि जबकि विचाराधीन उत्पाद की मांग 2018-19 तक बढ़ी, जांच की अवधि में इसमें गिरावट आई। तथापि, आधार वर्ष से तुलना करने पर संबद्ध सामानों के लिए मांग में जांच की अवधि में वृद्धि हुई।

**ख. संबद्ध देश से आयात मात्राएं**

64. पाटित आयातों की मात्रा के संबंध में, प्राधिकारी को इस बात पर विचार करना अपेक्षित होता है कि क्या पूर्ण दृष्टि से या भारत में उत्पादन अथवा खपत के संबंध में संबद्ध देश से पाटित आयातों में काफी वृद्धि हुई है। क्षति विश्लेषण के प्रयोजन के लिए, प्राधिकारी ने डीजीसीआईएंडएस से प्राप्त लेन-देन वार आयात आंकड़ों पर विश्वास किया है। संबद्ध देश से संबद्ध सामानों के आयातों की मात्रा का विश्लेषण निम्नलिखित रूप में किया गया है:

विवरण	यूओएम	2016-17	2017-18	2018-19	जांच की अवधि
संबद्ध देश से कुल आयात	मी. टन	783	1288	1171	868
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	165	150	111
अन्य देशों से आयात	मी. टन	65	84	253	217
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	130	390	335
<b>के संबंध में चीन से संबद्ध आयात</b>					
मांग	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	132	120	100
भारतीय उत्पादन	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	150	133	100

65. यह नोट किया जाता है कि:

क. पाटित आयातों की मात्रा 2017-18 तक बढ़ी, फिर उसके बाद जांच की अवधि तक उसमें गिरावट आई। तथापि, आधार वर्ष से तुलना करने पर, जांच की अवधि में आयातों में वृद्धि हुई।

ख. घरेलू उत्पादन और खपत के संबंध में, आयातों ने समान प्रवृत्तियां दर्शाई हैं, जबकि भारत में उत्पादन और खपत के संबंध में 2017-18 तक आयातों में वृद्धि हुई, उसके बाद जांच की अवधि तक उसमें गिरावट आई।

**पाटित आयातों का कीमत प्रभाव**

66. नियमावली के अनुबंध-II(ii) के अनुसार, कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव के संबंध में प्राधिकारी के लिए यह अपेक्षित है कि वे यह विचार करें कि क्या भारत में समान उत्पाद की कीमत की तुलना में पाटित आयातों से काफी कीमत कटौती हुई है अथवा क्या इन आयातों का प्रभाव अन्यथा कीमतों में काफी मात्रा तक कमी करना है या कीमत वृद्धि रोकना है जो अन्यथा काफी मात्रा तक हुई होती।

**क. कीमत कटौती**

67. कीमत कटौती के विश्लेषण के प्रयोजन के लिए, घरेलू उद्योग की निवल बिक्री कीमत की तुलना संबद्ध देश से आयातों के पहुँच मूल्य से की गई है। घरेलू उद्योग की निवल बिक्री कीमत का परिकलन करते समय सभी कर, छूटें, रियायत और कमीशन घटा दिया गया है और कार्यगत स्तर पर बिक्री वसूली पर पाटित आयातों के पहुँच मूल्य के साथ तुलना करने के लिए विचार किया गया है। तदनुसार, संबद्ध देश से पाटित आयातों के कटौती प्रभाव निम्नलिखित निकलते हैं:

विवरण	यूनिट	चीन जन. गण.			
		2016-17	2017-18	2018-19	जांच की अवधि
आयातों की पहुँच कीमत	रु./कि.ग्रा.	318	586	433	256
निवल बिक्री कीमत	रु./कि.ग्रा.	***	***	***	***
कीमत कटौती	रु./कि.ग्रा.	100	151	132	94
	%	***	***	***	***
	रेंज	70-80%	40-50%	65-75%	100-110%

68. यह देखा जाता है कि संबद्ध सामानों की पहुँच कीमतें घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से वास्तविक रूप से कम थीं। इसके अतिरिक्त, आयातों की पहुँच कीमत में वृद्धि के साथ बिक्री कीमत 2017-18 में बढ़ी। तथापि, बिक्री कीमत में आयातों की पहुँच कीमत में गिरावट के साथ उसके बाद गिरावट आई। कीमत कटौती पूरी क्षति अवधि में सकारात्मक और काफी है।

#### ख. कीमत न्यूनीकरण एवं ह्रास

69. यह निर्धारित करने के लिए कि क्या पाटित आयात घरेलू उद्योग की कीमतों का ह्रास कर रहे हैं और क्या इन आयातों का प्रभाव काफी मात्रा तक कीमतों का न्यूनीकरण करने के लिए अथवा कीमत वृद्धि रोकने के लिए है जो अन्यथा सामान्य प्रक्रिया में हुई होती, क्षति की अवधि में लागतों तथा कीमतों में परिवर्तनों की तुलना निम्नलिखित रूप में की गई है:

विवरण	यूनिट	2016-17	2017-18	2018-19	जांच की अवधि
बिक्रियों की लागत	रु./कि.ग्रा.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	154	125	94
बिक्री कीमत	रु./कि.ग्रा.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	151	132	94
पहुँच कीमत - चीन	रु./कि.ग्रा.	318	586	433	256
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	184	136	81

70. यह देखा जाता है कि संबद्ध देश से आयातों की पहुँच कीमत पूरी क्षति अवधि में घरेलू उद्योग की बिक्री लागत तथा बिक्री कीमत से कम थी। यह भी नोट किया जाता है कि जबकि घरेलू उद्योग 2017-18 में लागत वृद्धि से अधिक अपनी कीमत बढ़ाने में सक्षम था और जांच की अवधि के दौरान 2018-19 में लागत गिरावट से कम पर कीमत घटाई तो घरेलू उद्योग लागत गिरावट से अधिक कीमत कम करने के लिए मजबूर था।

71. यह भी नोट किया जाता है कि आयातों की पहुँच कीमत बिक्री लागत से काफी कम है। इसके अतिरिक्त, आयातों की पहुँच कीमत और बिक्री लागत के बीच अंतर क्षति की अवधि में बढ़ा और जांच की अवधि में अपने उच्चतम स्तर पर था। इस प्रकार, घरेलू उद्योग को क्षति की अवधि के दौरान कीमत न्यूनीकरण हुआ है।

72. इस प्रकार यह नोट किया जाता है कि आयात घरेलू उद्योग की कीमतों का ह्रास कर रहे हैं।



**ज.3.2 घरेलू उद्योग के आर्थिक मानदंड**

73. नियमावली के अनुबंध-II में यह अपेक्षित है कि क्षति के निर्धारण में उन उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर पाटित आयातों के परिणामी प्रभाव की तथ्यपरक जांच शामिल होगी। इन उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर पाटित आयातों के परिणामी प्रभाव के संबंध में, नियमावली में यह भी उपबंध है कि घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच में समस्त संगत आर्थिक कारकों और बिक्री, लाभ, उत्पादन, बाजार हिस्से, उत्पादकता, निवेश पर आय अथवा क्षमता उपयोग में वास्तविक एवं संभावित गिरावट सहित घरेलू उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले संकेतकों; घरेलू कीमतों, पाटन मार्जिन की मात्रा, नकद प्रवाह, मालसूची, रोजगार, मजदूरी, वृद्धि, पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता पर वास्तविक और संभावित नकारात्मक प्रभावों का तथ्यपरक एवं निष्पक्ष मूल्यांकन शामिल होगा। घरेलू उद्योग से संबंधित विभिन्न क्षति मानदंडों पर यहां नीचे चर्चा की गई है।

**क. उत्पादन, क्षमता, बिक्री और क्षमता उपयोग**

74. क्षति की अवधि में घरेलू उद्योग की क्षमता, उत्पादन, बिक्री और क्षमता उपयोग निम्नलिखित है:

विवरण	यूओएम	2016-17	2017-18	2018-19	जांच की अवधि
क्षमता	मी. टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	109	109	109
कुल उत्पादन	मी. टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	109	113	113
क्षमता उपयोग	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	100	103	103
घरेलू बिक्रियां	मी. टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	112	113	100
निर्यात बिक्रियां	मी. टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	100	36	27
कुल बिक्रियां	मी. टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	112	112	99

75. यह देखा जाता है कि:

क. घरेलू उद्योग ने वर्ष 2017-18 में अपने क्षमताओं में वृद्धि की।

ख. घरेलू उद्योग का उत्पादन और क्षमता उपयोग बढ़ा।

ग. घरेलू बिक्री 2018-19 तक बढ़ी और उसके बाद जांच की अवधि में उसमें गिरावट आई।

**ख. मांग में बाजार हिस्सा**

76. घरेलू उद्योग और आयातों का बाजार हिस्सा निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है:

विवरण	यूओएम	2016-17	2017-18	2018-19	जांच की अवधि
घरेलू उद्योग की बिक्रियां	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	91	91	91
अन्य उत्पादकों की बिक्रियां	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	87	82	95

संबद्ध देश से आयात	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	132	120	100
अन्य देश	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	100	300	300
कुल	%	100	100	100	100

77. यह देखा जाता है कि यद्यपि संबद्ध आयातों के बाजार हिस्से में 2017-18 में वृद्धि हुई है और जांच की अवधि में उसमें गिरावट आई है, तथापि उस उत्पाद को पूरी क्षति अवधि में पाटनरोधी शुल्क के अध्याधीन रखा गया था, फिर भी संबद्ध सामानों का बाजार हिस्सा काफी है। जांच अवधि में घरेलू बिक्री के बाजार हिस्से में आधार वर्ष की तुलना में गिरावट आई है।

#### ग. मालसूची

78. क्षति की अवधि में घरेलू उद्योग के पास मालसूची की स्थिति निम्नलिखित तालिका में दी गई है:

मानदंड	यूनिट	2016-17	2017-18	2018-19	जांच की अवधि
आरंभिक स्टॉक	मी. टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	35	4	22
अंतिम स्टॉक	मी. टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	13	63	975
औसत मालसूची	मी. टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	27	20	273

79. यह देखा जाता है कि घरेलू उद्योग के पास मालसूची में 2018-19 तक गिरावट आई और जांच की अवधि में उसमें वृद्धि हुई।

#### घ. लाभ, निवेश पर आय और नकद लाभ

80. क्षति की अवधि में घरेलू उद्योग की लाभप्रदता, निवेश पर आय और नकद लाभ निम्नलिखित तालिका में दिया गया है:

मानदंड	यूनिट	2016-17	2017-18	2018-19	जांच की अवधि
बिक्री कीमत	र./कि.ग्रा.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	151	132	94
लागत	र./कि.ग्रा.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	154	125	94
लाभ/हानि	र./कि.ग्रा.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	123	189	90
लाभ/हानि	लाख र.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	137	213	91
ब्याज और कर पूर्व लाभ/हानि	लाख र.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	126	178	77
नकद लाभ	लाख र.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	122	179	92
आरओसीई	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	71	127	42

81. यह देखा जाता है कि:

- क. घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में 2018-19 तक वृद्धि हुई और जांच की अवधि के दौरान उसमें गिरावट आई। लाभप्रदता आधार वर्ष की तुलना में जांच की अवधि के दौरान गिरावट दर्शाती है।
- ख. निवेश पर आय और नकद लाभ ने लाभप्रदता की तरह समान प्रवृत्ति अपनाई है।
- ग. घरेलू उद्योग ने यह अनुरोध किया है कि घरेलू उद्योग की विनिर्माण सुविधाओं का काफी हद तक ह्रास हुआ है और इसलिए आरओआई प्रतिबिंबित और प्रतिनिधि नहीं है।

#### ड. रोजगार, उत्पादकता और मजदूरी

82. क्षति की अवधि में रोजगार, उत्पादकता और मजदूरी के संबंध में घरेलू उद्योग का निष्पादन निम्नलिखित था:

विवरण	यूओएम	2016-17	2017-18	2018-19	जांच की अवधि
रोजगार	सं.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	106	121	126
प्रति कर्मचारी उत्पादकता	मी. टन/सं.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	107	93	86
मजदूरी	लाख ₹	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	106	140	123

83. यह देखा जाता है कि:

- क. कर्मचारियों की संख्या में क्षति की अवधि में सुधार हुआ है।
- ख. उत्पादकता में क्षति की अवधि में गिरावट आई है।
- ग. प्रदत्त मजदूरी 2018-19 तक बढ़ी है और फिर जांच की अवधि में उसमें गिरावट आई है।

#### घ. वृद्धि

84. उत्पादन, घरेलू बिक्री, बिक्री लागत, बिक्री कीमत, लाभ और नकद लाभ के संबंध में घरेलू उद्योग की वृद्धि में क्षति की अवधि में गिरावट आई है। तथापि, निवेश पर आय ने विशेषकर जांच की अवधि के दौरान, नकारात्मक वृद्धि दर्शाई।

मानदंड	यूनिट	2016-17	2017-18	2018-19	जांच की अवधि
उत्पादन (मी. टन)	%		9%	3%	0%
घरेलू बिक्री मात्रा (मी. टन)	%		12%	1%	-11%
बिक्रियों की लागत (रु./कि.ग्रा.)	%		54%	-19%	-25%
बिक्री कीमत (रु./कि.ग्रा.)	%		51%	-12%	-29%
लाभ/हानि (रु./कि.ग्रा.)	%		22%	55%	-52%
नकद लाभ	%		22%	47%	-49%
निवेश पर आय	%		-29%	79%	-67%

**ड. पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता**

85. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग के पास उपयुक्त रूप से अच्छा क्षमता उपयोग है। तथापि, घरेलू उद्योग के निष्पादन में जांच की अवधि में गिरावट आई है।

**च. पाटन की मात्रा**

86. यह नोट किया जाता है कि संबद्ध सामानों का भारत में पाटन किया जा रहा है और पाटन मार्जिन सकारात्मक और काफी है।

**छ. घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक**

87. संबद्ध देश से आयात कीमतों की जांच लागत ढांचे में परिवर्तन, घरेलू उद्योग में प्रतिस्पर्धा, पाटित आयातों को छोड़कर अन्य कारक, जो घरेलू बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतों को प्रभावित कर सकते हैं, यह दर्शाते हैं कि संबद्ध देश से आयातित सामग्री का पहुँच मूल्य घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत के लिए निर्धारण है। वस्तुतः घरेलू उद्योग आयात की कीमतों से मेल कर रहा है और उसने लागत में वृद्धि के अनुपात में अपनी कीमतें नहीं बढ़ाई हैं, यह दर्शाता है कि संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों की पहुँच कीमत घरेलू उद्योग की कीमतों को प्रभावित कर रहे हैं।

**ज. क्षति संबंधी विश्लेषण**

88. प्राधिकारी ने क्षति और कारणात्मक संपर्क के संबंध में घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए विभिन्न अनुरोधों को नोट किया है और रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों तथा लागू कानूनों पर विचार करते हुए उनका विश्लेषण किया है। पूर्व के पैराओं में किया गया क्षति विश्लेषण यथातथ्यतः घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों को हल करता है।
89. संबद्ध उत्पाद के आयातों की जांच और घरेलू उद्योग का निष्पादन यह दर्शाता है कि आयातों की मात्रा क्षति की अवधि में पूर्ण दृष्टि से और भारत में उत्पादन तथा मांग की तुलना में बढ़ी है। यहां तक कि यद्यपि उसने पूर्व वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में गिरावट दर्शाई है। आयात घरेलू उद्योग की कीमतों की कटौती कर रहे हैं और कीमत कटौती का मार्जिन काफी है। यह भी नोट किया जाता है कि संबद्ध देश से संबद्ध सामानों के आयातों से बाजार में कीमत ह्रास हुआ है और घरेलू उद्योग को संबद्ध देश से संबद्ध सामानों के पाटित आयातों के कारण कीमत न्यूनीकरण भी हुआ है।
90. यद्यपि घरेलू उद्योग की क्षमता में इस अवधि में वृद्धि हुई है, तथापि घरेलू उद्योग की बिक्री में पूर्व वर्ष से तुलना करने पर जांच की अवधि में गिरावट आई है। संबद्ध आयातों के बाजार हिस्से में वृद्धि हुई है, जबकि घरेलू उद्योग के हिस्से में आधार वर्ष से गिरावट आई है। घरेलू उद्योग में जांच की अवधि में उसके लाभ और नकद लाभ में गिरावट आई है। घरेलू उद्योग की नियोजित पूंजी पर आय में जांच की अवधि में काफी गिरावट आई है।

**क्षति मार्जिन/कम कीमत पर बिक्री**

91. प्राधिकारी ने यथा संशोधित अनुबंध-III के साथ पठित नियमावली में निर्धारित सिद्धांतों के आधार पर घरेलू उद्योग के लिए क्षति रहित कीमत (एनआईपी) निर्धारित की है। विचाराधीन उत्पाद की क्षति रहित कीमत जांच की अवधि के लिए घरेलू उद्योग द्वारा दी गई और प्रैक्टिसिंग लागत लेखाकार द्वारा विधिवत प्रमाणित उत्पादन लागत से संबंधित सूचना/आंकड़ों को अपनाकर निर्धारित की गई है। क्षति मार्जिन का परिकलन करने के लिए संबद्ध देश से पहुँच कीमत की तुलना करने के लिए क्षति रहित कीमत पर विचार किया गया है। क्षति रहित कीमत निर्धारित करने के लिए क्षति की अवधि में घरेलू उद्योग द्वारा कच्ची सामग्री के सर्वोत्तम उपयोग पर विचार किया गया है। यही व्यवहार यूटिलिटियों के साथ किया गया है। क्षति की अवधि में उत्पादन क्षमता के सर्वोत्तम उपयोग पर विचार किया गया है। यह सुनिश्चित किया जाता है कि उत्पादन लागत में कोई असाधारण अथवा अनावर्ती व्यय न लगाया जाए। विचाराधीन उत्पाद के लिए औसत नियोजित पूंजी (अर्थात् औसत निवल निर्धारित परिसंपत्तियां तथा औसत कार्यशील पूंजी) पर उपयुक्त आय (कर पूर्व 22 प्रतिशत की दर से) की नियमावली के अनुबंध-III में निर्धारित किए गए अनुसार और प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई सतत परिपाटी के अनुसार क्षति रहित कीमत निकालने के लिए कर पूर्व लाभ के रूप में अनुमति दी गई थी।

92. संबद्ध देशों से सभी असहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए प्राधिकारी ने उपलब्ध तथ्यों के आधार पर पहुँच कीमत निर्धारित की है।
93. उपर्युक्त निर्धारित पहुँच कीमत और क्षति रहित कीमत के आधार पर, उत्पादकों/निर्यातकों के लिए क्षति मार्जिन प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किया गया है और वह निम्नलिखित तालिका में दिया गया है:

उत्पादक	क्षति रहित कीमत (अमे. डॉ./मी. टन)	पहुँच मूल्य (अमे. डॉ./मी. टन)	क्षति मार्जिन अमे. डॉ./ मी. टन	क्षति मार्जिन (%)	क्षति मार्जिन % (रेंज)
मैसर्स सीएसपीसी वीशेंग फार्मास्युटिकल (शीजियाझुआंग) कं. लि.	***	***	***	***	90-100
अन्य	***	***	***	***	120-130

#### झ. कारणात्मक संपर्क और गैर-आरोप्य विश्लेषण

94. नियमावली के अनुसार, प्राधिकारी के लिए अन्य बातों के साथ-साथ पाटित आयातों को छोड़कर किन्हीं अन्य ज्ञात कारकों की जांच करना अपेक्षित है जो साथ-साथ घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचा रहे हैं ताकि इन अन्य कारकों के कारण हुई क्षति पाटित आयातों के कारण न हो। इस संबंध में, जो कारक संगत हैं, उनमें अन्य बातों के साथ-साथ पाटित कीमतों पर न बेचे गए आयातों की मात्रा तथा कीमतें, मांग में संकुचन अथवा खपत के पैटर्न में परिवर्तन, व्यापार प्रतिबंधात्मक परिपाटियां, विदेशी और घरेलू उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा, प्रौद्योगिकी में विकास तथा निर्यात निष्पादन और घरेलू उद्योग की उत्पादकता शामिल हैं। प्राधिकारी ने जांच की कि क्या पाटित आयातों को छोड़कर किन्हीं अन्य ज्ञात कारकों का घरेलू उद्योग को क्षति में योगदान हो सकता है।
95. प्राधिकारी नोट करते हैं कि नियमावली यह मानती है कि पाटन घरेलू उद्योग का क्षति का पूरा कारण होना आवश्यक नहीं है। ऐसे भी अन्य कारक हो सकते हैं जिनसे घरेलू उद्योग को क्षति हुई हो। तथापि, ऐसी स्थिति में जहां अन्य कारकों से घरेलू उद्योग को क्षति हुई है, वहां प्राधिकारी के लिए यह अपेक्षित है कि वे यह सुनिश्चित करें कि क्या अन्य कारकों से हुई क्षति इतनी अधिक है कि वह पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को हुई क्षति से अधिक हो।

#### क. अन्य स्रोतों से आयात

96. अन्य देशों से आयात या तो न्यूनतम स्तरों पर हैं अथवा आयात कीमतें अधिक हैं। अतः यह देखा जाता है कि अन्य देशों से आयातों से घरेलू उद्योग को क्षति नहीं हुई है।

#### ख. मांग में संकुचन

97. विचाराधीन उत्पाद की मांग में जांच की अवधि में गिरावट के साथ क्षति की अवधि में वृद्धि हुई है। यहां तक कि जब मांग में जांच की अवधि में गिरावट आई तो वह आधार वर्ष से अधिक थी। इसके अतिरिक्त, चूंकि उत्पादन के लिए मांग में गिरावट आई, अतः आयात कीमत में लागत में गिरावट से कहीं अधिक तेज गिरावट थी।

#### ग. खपत के पैटर्न में परिवर्तन

98. विचाराधीन उत्पाद के संबंध में खपत के पैटर्न में किसी परिवर्तन का कोई साक्ष्य नहीं है। अतः खपत के पैटर्न में परिवर्तनों को घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचाना नहीं माना जा सकता।

#### घ. व्यापार प्रतिबंधात्मक परिपाटियां और घरेलू एवं विदेशी उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा

99. ऐसी कोई व्यापार प्रतिबंधात्मक परिपाटी नहीं है जो घरेलू उद्योग को क्षति में योगदान कर सकती हो।

#### ङ. प्रौद्योगिकी में विकास

100. किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने प्रौद्योगिकी में काफी परिवर्तन दर्शाने के लिए कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है जिससे घरेलू उद्योग को क्षति हो सकती हो।

**च. निर्यात निष्पादन**

101. यहां ऊपर जांच की गई कि क्षति संबंधी सूचना घरेलू बाजार के संदर्भ में घरेलू उद्योग के निष्पादन से ही संबंधित है। इस प्रकार, हुई क्षति घरेलू उद्योग के निर्यात निष्पादन के कारण नहीं हो सकती।

**छ. घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित किए जा रहे और बेचे जा रहे अन्य उत्पादों का निष्पादन**

102. प्राधिकारी ने केवल संबद्ध सामानों के निष्पादन से संबंधित आंकड़ों पर ही विचार किया है। अतः उत्पादित और बेचे गए अन्य उत्पादों का निष्पादन घरेलू उद्योग को क्षति का संभावित कारण नहीं है।

**ज. क्षति और कारणात्मक संपर्क की जांच**

103. इस प्रकार यह नोट किया जाता है कि नियमावली के तहत सूचीबद्ध अन्य ज्ञात कारक यह नहीं दर्शाते कि घरेलू उद्योग को इन अन्य कारकों के कारण क्षति हुई है। प्राधिकारी ने यह भी जांच की है कि क्या इस उत्पाद के पाटन से घरेलू उद्योग को क्षति हुई है। निम्नलिखित मानदंड यह दर्शाते हैं कि घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति पाटित आयातों के कारण हुई है:

- क. संबद्ध देश से संबद्ध सामानों के आयात में पूर्ण दृष्टि से तथा उत्पादन एवं खपत के संबंध में वृद्धि हुई है।
- ख. संबद्ध आयातों का बाजार हिस्सा क्षति की अवधि के दौरान स्थिर और काफी रहा है, जबकि घरेलू उद्योग के हिस्से में उसी अवधि में गिरावट आई है।
- ग. पाटित आयात घरेलू उद्योग की कीमतों की कटौती कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त, कीमत कटौती से बाजार में उत्पाद की कीमतों पर न्यूनीकरण एवं ह्रासमान प्रभाव पड़ा है।
- घ. पाटित आयातों के कारण हुए न्यूनीकरण एवं प्रभावीकारी प्रभावों से घरेलू उद्योग के लाभ, नकद लाभ और नियोजित पूंजी पर आय प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुए हैं।

**ट. प्रकटन पश्चात टिप्पणियां****ट.1 घरेलू उद्योग के विचार**

104. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए प्रकटन पश्चात अनुरोध निम्नलिखित हैं:

- क. जबकि सभी पक्षकारों के लिए पाटन मार्जिन इतना तुलनीय है, पाटन मार्जिन उतना तुलनीय नहीं है।
- ख. अलग-अलग आयात लेन-देन की कम मात्रा और तथ्य पर विचार करते हुए कि वायु मार्ग द्वारा माल भेजा गया है, यह स्पष्ट है कि पूर्व लेन-देन के बारे में निर्यातकों द्वारा प्राधिकारी को नहीं बताया गया है। ये लेन-देन सामान्य व्यापार के लेन-देन नहीं हैं। प्राधिकारी से यह अनुरोध किया जाता है कि वे जेएनपीटी पोर्ट से संगत दस्तावेजों की मांग करें। चूंकि यह उत्पाद दवा नहीं है, अतः किसी भी उत्पादक से यह अपेक्षित है कि वह ड्रग कंट्रोलर से लाइसेंस प्राप्त करे और व्यापारी से खरीदी गई वस्तुओं के लिए भी उत्पादक का नाम दर्शाते हुए, दस्तावेज प्रस्तुत करे।
- ग. मै. शानडोंग युवेई फार्मास्युटिकल अकेले इतनी कम कीमत पर निर्यात करता रहा है, ऐसा प्रतीत होता है कि उसने जांच की अवधि के दौरान और इतनी अधिक कीमत पर केवल तीन वायु मार्ग से लेन-देन की सूचना दी है। समुद्री मार्ग और वायु मार्ग के माध्यम से भाड़ा शुल्क में बहुत अधिक अंतर है।
- घ. हम प्राधिकारी से अनुरोध करते हैं कि वे वायु मार्ग के भाड़े को हटाने के बाद और केवल भुगतान योग्य समुद्री भाड़े पर विचार करने के बाद क्षति मार्जिन पर फिर से विचार करें।
- ड. मै. शानडोंग लुवेई फार्मास्युटिकल ने मै. शाइनोराइट इंटरनेशनल ट्रेड कं. के माध्यम से की गई बिक्री की सूचना नहीं दी है। उत्पादक के उत्तर के साथ कोई उत्तर संलग्न नहीं किया गया है। केवल उत्पादक ने उत्तर प्रस्तुत किया है। इसके अलावा, यह तथ्यों को छुपाने को दर्शाता है।
- च. मै. शानडोंग लुवेई फार्मास्युटिकल ने बहुत अधिक हद तक तथ्यों को छुपाया है और प्राधिकारी के समक्ष गलत सूचना प्रस्तुत की है।

- छ. विचाराधीन उत्पाद के लिए कोई अर्थक्षम प्रतिस्थापन नहीं है। घरेलू उद्योग द्वारा बेचे गए उत्पाद के उपयोग की अवधि 4 वर्ष है जबकि विदेशी उत्पादक 3 वर्षों की उपयोग की अवधि देते हैं। घरेलू उद्योग द्वारा निर्मित विचाराधीन उत्पाद की पैकिंग निर्यातकों की पैकिंग के समान है।
- ज. पाटनरोधी शुल्क लगाना घरेलू निर्माताओं के हित में होगा, उद्योग के कार्य-निष्पादन में गिरावट को रोकेगा और हुई क्षति को दूर करेगा। यह उद्योग प्रत्यक्ष रूप से 5,000 से अधिक लोगों और अप्रत्यक्ष रूप से 50,000 से अधिक लोगों को रोजगार प्रदान करता है, इस प्रकार के लोगों की जीविका प्रभावित होगी। शुल्क लगाया जाना भारत में मध्यवर्ती के उत्पादन को भी प्रोत्साहित करेगा।
- झ. शुल्क लगाने के फलस्वरूप, अंतिम उत्पाद पर कोई बहुत अधिक प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा और यह व्यापक जनहित में होगा। वर्ष 2010 से इन शुल्कों के लागू रहने के बावजूद प्रयोक्ताओं पर प्रतिकूल प्रभाव का कोई साक्ष्य नहीं है। दवाओं में उपयोग किए जाने वाले विटामिन-सी सूत्रीकरण की कीमत में वृद्धि नहीं होगी क्योंकि इसकी कीमत भारत सरकार द्वारा नियंत्रित और विनियमित होती है। विटामिन-सी डीपीसीओ के अंतर्गत आता है।
- ञ. चीन के उत्पादकों को अधिकतम कोविड-19 अवधि के दौरान भारत की मांग की बहुत कम चिंता थी।
- ट. भारतीय उद्योग के पास भारत में 100 प्रतिशत मांग पूरा करने के लिए पहले से ही पर्याप्त क्षमताएं हैं।
- ठ. इस शुल्क को निर्धारित राशि के रूप में लगाया जाना चाहिए और उसे यूएस डॉ. में व्यक्त किया जाना चाहिए।

## ट.2 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

105. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रकटन पश्चात, निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:-

- क. किसी शुल्क की सिफारिश नहीं की जानी चाहिए क्योंकि निवल बिक्री प्राप्ति प्रकटन विवरण के पैरा 57 में यथा-उल्लिखित आवेदक उद्योग की क्षति रहित कीमत से अधिक है।
- ख. प्राधिकारी को आवेदक उद्योग की लागत/कीमत से समुद्री भाड़ा, बीमा, पोर्ट शुल्क जैसे एफओबी पश्चात खर्च और बीसीडी, सेस आदि जैसे किसी लागू शुल्कों को कम करने की आवश्यकता है क्योंकि चीन के उत्पादक इन खर्चों का वहन नहीं करेंगे क्योंकि वे कच्चे माल का आयात नहीं करते हैं।
- ग. “कमतर शुल्क नियम” का अनिवार्य रूप से अनुसरण प्राधिकारी द्वारा सभी मामलों में किया जाना अपेक्षित है।
- घ. प्राधिकारी का क्षति आकलन न केवल गलत है बल्कि इस नियमावली की आवश्यकता के विपरीत भी है क्योंकि प्राधिकारी के पास इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए पर्याप्त आंकड़े नहीं हैं कि संबद्ध वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों को क्षति हुई है।
- ङ. चूंकि अन्य उत्पादकों ने व्यापार सूचना सं. 13/2018 के अनुसार आंकड़े प्रस्तुत नहीं किए हैं अतः उनके आंकड़ों का उपयोग समर्थकों के रूप में भी नहीं किया जा सका, जैसाकि 6पीपीडी [एफ.नं. 6/34/2019-डीजीटीआर दिनांक 9.1.2020] के मामले में किया गया था। किसी भी भारतीय उत्पादक ने निर्णायक समीक्षा जांच के लिए आवेदन नहीं किया है, यह साबित करता है कि घरेलू उत्पादकों को न तो कोई क्षति हुई थी और न ही उन्हें क्षति होने की संभावना थी।
- च. कोविड-19 के कारण, इन उत्पादों की मांग में 6 से 8 बार तक वृद्धि हुई है। उदाहरण के लिए, एबोट के लिए इन उत्पादों की मांग में 400 प्रतिशत से अधिक वृद्धि हुई है। घरेलू उद्योग भारत में संबद्ध वस्तुओं की मांग को पूरा नहीं कर सकते हैं। चूंकि चीन और सिंगापुर भारत में विटामिन-सी के मुख्य निर्यातक हैं, अतः विटामिन-सी के आयातों पर कोई भी पाटनरोधी शुल्क संबद्ध वस्तुओं के प्रयोक्ताओं को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करेगा।
- छ. बजाज हेल्थकेयर लिमिटेड ने भी एक कार्टल बनाते हुए प्रभावी रूप से अन्य आपूर्तिकर्ताओं के पास पहुंचा है ताकि वे एसकोर्बिक एसिड और सोडियम एसकोरबेट की बढ़ी हुई कीमतें बनाए रख सकें।
- ज. मांग में अचानक वृद्धि के साथ-साथ आपूर्ति की कमी के फलस्वरूप विटामिन-सी की बहुत अधिक कमी हुई है जिसकी बिक्री सामान्य कीमत से पांच से आठ गुना अधिक कीमतों पर की जा रही है।

- झ. यदि कोई अतिरिक्त संरक्षण दिया जाता है जो उन्हें 22 वर्षों से अधिक से मिलता आ रहा है, तब यह व्यापक रूप से आम जनता के लिए अत्यधिक अनुचित होगा।
- ञ. वर्तमान जांच स्पष्ट रूप से गलत अनुमानों, गलत सूचना पर आधारित हैं और वे स्थापित कानूनी प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं। इस प्रकार, हम प्राधिकारी से यह अनुरोध करते हैं कि वे जांच को कृपया तुरंत समाप्त कर दें।
- ट. प्राधिकारी अपनी निरंतर कार्य-पद्धति के अनुसार, जांच के इस चरण में कोई नया साक्ष्य स्वीकार नहीं कर सकते हैं। हालांकि, प्राधिकारी द्वारा किसी अप्रत्याशित संलिप्तता दर्शाते हुए असंभावित घटना में, ऐसी सभी दस्तावेजों/सूचना को कृपया हमें उपलब्ध कराया जाए ताकि हम उन पर टिप्पणी कर सकें। प्राधिकारी से यह अनुरोध किया जाता है कि वे उस सूचना जिसे गोपनीय के रूप में नहीं रखा जा सकता है अथवा जिसके लिए पाटनरोधी नियमावली के नियम 8 के संदर्भ में एक सार्थक सारांश अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना अपेक्षित है, के बाद एक नई सुनवाई की अनुमति दी जाए।
- ठ. विचाराधीन उत्पाद की परिभाषा में तथा अंतिम जांच परिणामों में शुल्क तालिका के नीचे इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए कि विटामिन-सी का डेरिवेटिव्स उत्पाद क्षेत्र के भीतर नहीं है।
- ड. चूंकि इस उत्पाद पर शुल्क चीन जन.गण. से पिछले 22 वर्षों से लागू रहा है अतः प्राधिकारी को यह सुनिश्चित करने के लिए इस मामले में जांच की अवधि के बाद का विश्लेषण अवश्य करना चाहिए कि क्या इस स्थिति में इस उत्पाद पर आगे पाटनरोधी शुल्क लगाने की आवश्यकता है।
- ढ. विचाराधीन उत्पाद की अपेक्षाकृत अधिक खरीद लागत अंतिम दवा सूत्रीकरण जिनकी कीमत पर डीपीसीओ के अंतर्गत एनपीपीए द्वारा नियंत्रण किया गया है क्योंकि विचाराधीन उत्पाद इस प्रकार के अंतिम दवा सूत्रीकरण के लिए मूल कच्चे मालों में से एक है, का उत्पादन करने और उसकी बिक्री करने के क्रियाकलापों को जारी रखने में गंभीर रूप से बाधा पहुंचाती है।
- ण. विटामिन-सी के खाद्य संपूरक रूप का निर्माण करने के लिए प्रयोक्ता उद्योग की कंपनियों की एक प्रवृत्ति रही है जो ड्रग रूप जैसे कीमत प्रतिबंधों के अधीन नहीं है। इसने कुल मिलाकर आम जनता को उचित कीमत पर विटामिन-सी की उपलब्धता को गंभीर रूप से प्रभावित किया है और अभी भी प्रभावित कर रहा है।
- त. प्रयोक्ता की प्रश्नावली के उत्तर में सभी अपेक्षित सूचना दिए जाने के बाद प्राधिकारी के लिए यह कहना सही नहीं है कि किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने पाटनरोधी शुल्कों के प्रभावों को दर्शाने के लिए सूचना उपलब्ध कराई।
- थ. विचाराधीन उत्पाद की निहित प्रकृति और कीमत निर्धारण के लिए मौजूद विनियामक तंत्र पर विचार करते हुए, पाटनरोधी शुल्क लगाने का प्रयोक्ता उद्योग पर और उचित कीमतों पर कुल मिलाकर आम जनता को विटामिन-सी की उपलब्धता पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा।
- द. संबद्ध आयातों में तत्काल पूर्व वर्ष 2018-19 की तुलना में जांच की अवधि में 303 एमटी तक बहुत अधिक हद तक कमी आई है। आधार वर्ष से तुलना किए जाने पर आयात की मात्रा में 85 एमटी की मामूली वृद्धि हुई है। हालांकि, इस प्रकार की मामूली वृद्धि को पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-II के उद्देश्य से “बहुत अधिक” वृद्धि के रूप में नहीं माना जा सकता है।
- ध. सीआईएफ की कीमतों से संबंधित आंकड़ों जैसाकि घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत किया गया है, में अनेक बार परिवर्तन हुआ है और प्राधिकारी से यह अनुरोध किया जाता है कि वे आयातों की सीआईएफ कीमतों का शुरु से अंत तक सत्यापन करें।
- न. सीएसपीसी और शांगडोंग लुवेई फार्मास्युटिकल कं. लि. के लिए निर्धारित पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन में स्पष्ट असंगतता है। जबकि सीएसपीसी की निर्यात कीमत (एफओबी) जांच की अवधि के दौरान 3.10 यूएस. डॉ. प्रति किग्रा. रही है, अन्य सहयोगी निर्यातक की निर्यात कीमत (एफओबी) उसी अवधि में 2.64 यूएसडॉ. प्रति किग्रा. के रूप में देखी जाती है। उसको देखते हुए, प्राधिकारी गणना संबंधी किसी त्रुटियों से बचने के लिए सीएसपीसी के लिए निर्धारित क्षति मार्जिन की क्रास जांच कर सकते हैं।



- प. घरेलू उद्योग की आयातों की पहुंच कीमत और बिक्री कीमत दोनों समग्र क्षति की अवधि के दौरान अस्थिर रही है और कीमतों में इस प्रकार की बहुत अधिक परिवर्तन कभी कभी इस उत्पाद के लिए मांग में अचानक वृद्धि अथवा कमी के कारण हुई है।
- फ. जांच की अवधि के दौरान आयात में तीव्र गिरावट हुई है। हालांकि, घरेलू उद्योग ने पिछले दो वर्षों जब आयात अधिकतम था, में अधिकतम लाभ दर्ज किया और जांच की अवधि में जब आयातों में जांच की अवधि के दौरान तेजी से गिरावट आई, लाभ में गिरावट आई। इस प्रकार, केवल पहुंच कीमत लाभ में गिरावट का कारण नहीं था, जैसा कि आरोप लगाया गया है।

### ट.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

106. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अधिकांश अनुरोध पुनरावृत्तिक प्रकृति के हैं। इन अनुरोधों की जांच पहले ही इस जांच परिणाम में उपयुक्त स्थानों पर की जा चुकी है। इसके अलावा, प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों के अतिरिक्त संगत अनुरोधों की जांच नीचे दिए गए अनुसार की है।
107. हितबद्ध पक्षकारों को प्रकटन विवरण जारी किए जाने के बाद, चीन के अन्य उत्पादक अर्थात् मै. सीएसपीसी ने चीन की सीमा शुल्क के अनुसार निर्यात ब्यौरे का हवाला देकर यह आरोप लगाया कि मै. शानडोंग लुवेई फार्मास्युटिकल कं. लि. ने भारत को अपने निर्यात के संबंध में पूर्ण/तथ्यात्मक आंकड़े की सूचना नहीं दी है और इस कारण से इसके फलस्वरूप संदिग्ध तरीके से कमतर मार्जिन रहा है। इसके अलावा, घरेलू उद्योग ने मै. साइनोराइट इंटरनेशनल ट्रेड कंपनी लि. द्वारा किए गए निर्यातों का प्रविष्टि-वार बिल का ब्यौरा प्रस्तुत कर यह आरोप लगाते हुए समान टिप्पणियां प्रस्तुत की है कि शानडोंग लुवेई फार्मास्युटिकल ने भी चीन के एक असंबंधित कंपनी/व्यापारी अर्थात् मै. साइनोराइट इंटरनेशनल ट्रेड कंपनी लि. के माध्यम से जांच की अवधि के दौरान भारत को संबद्ध वस्तुओं की बिक्री की है। इसके अलावा, घरेलू उद्योग ने यह उल्लेख करते हुए दस्तावेज प्रस्तुत किए कि शानडोंग लुवेई फार्मास्युटिकल ने अपने एजेंट के रूप में साइनोराइट इंटरनेशनल ट्रेड की नियुक्ति की है और इस दस्तावेज में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि “शानडोंग लुवेई फार्मास्युटिकल कं. लि. एतद्वारा एसकोरबि एसिड के लिए वाणिज्यिक क्रियाकलाप, विपणन और बिक्री के वास्ते भारत में अनन्य एजेंट के रूप में मै. साइनोराइट इंटरनेशनल ट्रेड कं. लि. को अधिकृत करता है”। इसमें निहित महत्वपूर्ण तथ्यों पर विचार करते हुए, प्राधिकारी ने मै. शानडोंग लुवेई फार्मास्युटिकल कं. लि. को उपर्युक्त के संबंध में अपनी टिप्पणियां देने के लिए अवसर दिया जिसका उत्तर कंपनी ने यह दिया कि शानडोंग लुवेई फार्मास्युटिकल द्वारा अपने एजेंट के रूप में साइनोराइट इंटरनेशनल ट्रेड की नियुक्ति करने संबंधी करार को बाद में कंपनी द्वारा रद्द कर दिया गया था। इसके अलावा, प्राधिकारी ने जेएनसीएच के कार्यालय और सीडीएससीओ के कार्यालय से वाणिज्यिक बीजकों, पैकिंग सूची, मूलता प्रमाण-पत्र आदि तथा फार्म 9 और 10 सहित प्रविष्टि बिल के ब्यौरे की मांग की। पीयूसी बल्क ड्रग होने के कारण, फॉर्म -9 (आयात लाइसेंस के लिए एक आवेदन के साथ वचनबद्धता का फॉर्म) फॉर्म -10 (आयात लाइसेंस) जारी करने के लिए जमा करना आवश्यक है। शेडोंग लुवेई फार्मास्युटिकल कंपनी लिमिटेड के अधिकृत एजेंट द्वारा प्रस्तुत फॉर्म -9 के आधार पर, सीडीएससीओ द्वारा फॉर्म -10 जारी किया गया था जिसने पीयूसी के आयात की अनुमति दी थी। उसकी जांच करने के बाद, यह निष्कर्ष निकाला गया है कि शानडोंग लुवेई फार्मास्युटिकल कं. लि. ने भारत को किए गए सभी निर्यातों की सूचना नहीं दी है और भारत को किए गए सभी निर्यातों को ईमानदारी से नहीं बताया है। इस कारण से, प्राधिकारी ने कंपनी द्वारा प्रस्तुत किए गए उत्तर को अस्वीकार किया है तथा कंपनी के लिए अलग-अलग पाटन मार्जिन का निर्धारण नहीं किया है।
108. प्राधिकारी यह मानते हैं कि किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने यह सिद्ध नहीं किया है कि विचाराधीन उत्पाद के लिए तकनीकी रूप से और वाणिज्यिक रूप से अर्थक्षम प्रतिस्थानापन हैं।
109. हितबद्ध पक्षकारों ने घरेलू उद्योग को क्षति होने का प्रतिवाद किया है। हितबद्ध पक्षकारों ने क्षति संबंधी कुछ मानदंडों के मामले में घरेलू उद्योग के कार्य-निष्पादन के मामले में सुधार का उल्लेख किया है। यह नोट किया जाता है कि केवल यह तथ्य कि घरेलू उद्योग के कार्य-निष्पादन में कुछ मानदंडों के संबंध में सुधार हुआ है, का आशय यह नहीं है कि घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति नहीं हुई है। यह एक अच्छे तरीके से स्थापित कानूनी स्थिति है कि यह आवश्यक नहीं है कि घरेलू उद्योग का कार्य-निष्पादन प्रत्येक क्षति संबंधी मानदंड के मामले में गिरावट दर्शाना चाहिए और कुछ मापदंडों में सुधार का आशय क्षति का नहीं होना नहीं है। जब तक घरेलू उद्योग का कार्य-निष्पादन कुछ मापदंडों के मामले में गिरावट को दर्शाता है और इस प्रकार की गिरावट अन्य मापदंडों में सकारात्मक विकास से अधिक महत्वपूर्ण होता है, तब यह निष्कर्ष निकाला जाना चाहिए कि घरेलू उद्योग को क्षति हुई है। इस संबंध में यह नोट किया जाता है कि इस उत्पाद पर क्षति की अवधि के दौरान पाटनरोधी शुल्क

लग रहा था, घरेलू उद्योग के लाभ, निवेश पर प्रतिफल और नकद लाभ बहुत अधिक गिरावट को दर्शाते हैं। यह भी नोट किया जाता है कि आयातों की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग के उत्पादन की लागत, बिक्री कीमत और क्षति रहित कीमत से बहुत कम है। इसके अलावा, पाटनरोधी शुल्क को जोड़ने के बाद आयातों की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से पूर्ण रूप से तुलनीय था। जबकि आयातों में पूर्व वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में गिरावट आई, वह आधार वर्ष की तुलना में अधिक थे और उसमें पाटनरोधी शुल्क के समाप्त होने के बाद बहुत अधिक हद तक वृद्धि हुई। विभिन्न मापदंड सामूहिक रूप से और संचयी रूप से यह दर्शाते हैं कि घरेलू उद्योग को क्षति हुई है।

110. इस तर्क के संबंध में कि संबद्ध वस्तुओं के अन्य उत्पादकों ने भाग नहीं लिया है और उन्हें कोई क्षति नहीं हो रही है अथवा वे बेहतर कर रहे हैं, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि इन हितबद्ध पक्षकारों ने यह दर्शाते हुए कोई सूचना उपलब्ध नहीं कराई है कि इन अन्य घरेलू उत्पादकों को क्षति नहीं हो रही है अथवा उनके कार्य-निष्पादन में सुधार हुआ। प्राधिकारी अन्य घरेलू उत्पादकों के कार्य-निष्पादन के संबंध में केवल अनुमान पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा, आवेदक इस नियमावली के अभिप्राय से घरेलू उद्योग है और उससे केवल इस कारण से कि अन्य घरेलू उत्पादकों ने अपने क्षति संबंधी आंकड़े उपलब्ध नहीं कराए हैं, जांच और उसकी स्थिति में गिरावट से वंचित नहीं किए जा सकते हैं।
111. विरोधी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए इस अनुरोध के संबंध में कि निवल बिक्री कीमत (एनएसआर) क्षति रहित कीमत (एनआईपी) से अधिक है, इस कारण से घरेलू उद्योग को क्षति नहीं हुई है, प्राधिकारी यह दोहराते हैं कि वर्तमान जांच में एनआईपी का निर्धारण क्षति मार्जिन के निर्धारण के उद्देश्य से पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-III के संबंध में किया गया है। इसके अलावा, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि ऐसा कोई कानूनी प्रावधान नहीं है कि प्राधिकारी को कीमत के प्रभाव का निर्धारण करने के उद्देश्य से क्षति रहित कीमत की तुलना निवल बिक्री प्राप्ति से करनी चाहिए। यह भी नोट किया जाता है कि आयातों की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री लागत, बिक्री कीमत और क्षति रहित कीमत से लगातार और वास्तविक रूप से कम रही है।
112. महामारी के समय के दौरान मांग-आपूर्ति में अंतर के मुद्दे के संबंध में, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि (क) घरेलू उत्पादकों ने अपनी मौजूदा क्षमताओं का विस्तार किया है (ख) रिकॉर्ड पर उपलब्ध सूचना के अनुसार, घरेलू उत्पादकों के पास न केवल देश में मौजूदा मांग से बहुत अधिक क्षमताएं हैं बल्कि वे मांग में किसी संभावित वृद्धि को भी पूरा करने में सक्षम होंगे (ग) घरेलू उद्योग ने यह अनुरोध किया है कि इसने कोविड के दौरान बढ़ी हुई मांग को पूरा किया है (घ) हितबद्ध पक्षकारों ने उनके द्वारा दावा किए गए कोविड के कारण मांग में वृद्धि के संबंध में आंकड़ों के साथ इसे सिद्ध नहीं किया है। घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि मांग में वृद्धि बहुत कम थी।
113. हितबद्ध पक्षकारों के इस तर्क के संबंध में कि पाटनरोधी शुल्क लगाने से खाद्य संपूरकों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क लगाने का उद्देश्य पाटन की अनुचित व्यापार कार्य-पद्धति की तुलना में घरेलू उद्योग के लिए समान अवसर सृजित करना है। इसके अलावा, घरेलू उद्योग ने यह दर्शाते हुए गणना उपलब्ध कराई कि खाद्य संपूरकों में उत्पाद के कारण लागत बहुत कम है। इसके अलावा, इस उत्पाद पर न केवल वर्तमान जांच की अवधि के दौरान बल्कि पिछले कुछ वर्षों के दौरान भी पाटनरोधी शुल्क लग रहा था और लागू पाटनरोधी शुल्क के संभावित प्रतिकूल प्रभाव के संबंध में किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया है। हितबद्ध पक्षकारों ने यह नहीं दर्शाया है कि इन उत्पादों की लागत में इस उत्पाद पर पूर्व पाटनरोधी शुल्क के समाप्त होने के बाद बहुत अधिक हद तक गिरावट आई थी।
114. प्राधिकारी सामान्य तौर पर यह नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क लगाने से अंतिम उत्पादों की कीमतों पर लागत वृद्धि प्रभाव पड़ सकता है। फिर भी, भारतीय बाजार में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा में पाटनरोधी शुल्कों के द्वारा कमी नहीं आएगी विशेषकर जब पाटनरोधी शुल्क की लेवी घरेलू उद्योग को हुई क्षति का निवारण करने के लिए आवश्यक राशि तक सीमित हो। इसके विपरीत, पाटनरोधी शुल्क लगाने से पाटन की कार्य-पद्धतियों द्वारा प्राप्त अनुचित लाभ समाप्त होंगे, घरेलू उद्योग की गिरावट रुक जाएगी और संबद्ध वस्तुओं के प्रयोक्ताओं/उपभोक्ताओं को अपेक्षाकृत अधिक विकल्प की उपलब्धता बनाए रखने में मदद मिलेगी। इस कारण से ये तर्क कि पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से अंतिम प्रयोक्ताओं/उपभोक्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, का कोई आधार नहीं है।
115. हितबद्ध पक्षकारों के इस तर्क के संबंध में कि घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत किए गए सीआईएफ कीमतों से संबंधित आंकड़ों में परिवर्तन हुआ है, प्राधिकारी ने प्रस्तुत की गई सूचना का सत्यापन किया है और उसे अपनाया है।

## ठ. भारतीय उद्योग के हित एवं अन्य मुद्दे

### ठ.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अनुरोध

116. भारतीय उद्योग के हित के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों का सार निम्नलिखित है:

- क. विचाराधीन उत्पाद एक अनिवार्य औषधि है। घरेलू उद्योग ने एकाधिकार की स्थिति लेने के लिए देश में संबद्ध सामानों की महत्ता और आवश्यकता को कम आंका है।
- ख. विटामिन सी, जो समाज को अन्य लाभ भी देता है, जैसी अनिवार्य औषधि पर पाटनरोधी शुल्क लगाकर उद्योग का दावा उस उत्पाद, जो कि विशेष रूपसे वर्तमान समय में अत्यधिक महत्ता का है, की कीमतों को बढ़ाकर देश को सेवाहीन करना है।
- ग. याचिकाकर्ता सहित समर्थक उत्पादकों ने समूह बनाया और मिलकर कीमतें बढ़ाईं। इस प्रकार, घरेलू उद्योग वैश्विक महामारी के बीच में आम जनता के स्वास्थ्य की कीमत पर कीमतें बढ़ाने में लगा हुआ है।
- घ. विचाराधीन उत्पाद जो विटामिन सी औषधि, जो कोविड-19 महामारी में देश के लोगों के जीवन को बचा सकता है, के आयातों पर शुल्क लगाना जनहित में नहीं होगा।
- ङ. प्राधिकारी को विटामिन सी परिष्कृत उत्पाद के विनियामक कार्यवाहों और रोगी/ अंतिम उपभोक्ता पर उसके प्रभाव पर भी विचार करना चाहिए।
- च. कुल मिलाकर अंतिम उपभोक्ता एफएसएसआई श्रेणी के विटामिन सी के विकल्प पर भी रह सकते हैं, जो कीमत प्रतिबंधों के अध्यधीन नहीं है और रोगी की 500 एमजी की थेराप्यूटिक डोज की आवश्यकता को पूरा नहीं कर सकती हैं।
- छ. घरेलू उद्योग ने अप्रैल, 2020 से अगस्त, 2020 तक 60 प्रतिशत से अधिक तक विचाराधीन उत्पाद की कीमतें बढ़ाई हैं जो उनकी उत्पादन लागत में किसी अनुरूप वृद्धि के बिना हैं जिससे इस तथ्य को देखते हुए कोविड-19 महामारी की स्थिति में जनता को नुकसान पहुँचाने की लागत पर लाभ लेने का सहारा लिया गया है कि विटामिन सी परिष्कृत उत्पाद महत्वपूर्ण प्रतिरोधक शक्ति वर्धक के रूप में अत्यधिक मांग में है।
- ज. विटामिन सी टेबलेट प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए, विशेषकर चल रही कोविड-19 महामारी के दौरान, सामान्यतः ली जाती है। इस प्रकार, पाटनरोधी शुल्क लगाने से टेबलेट के विनिर्माण और उसकी सतत आपूर्ति बनाए रखने की क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और इससे अंततः जनहित प्रभावित हो सकता है।
- झ. विचाराधीन उत्पाद के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क पुनः लगाने से घरेलू उद्योग का एकाधिकार बनेगा और विटामिन सी के परिष्कृत निर्माणों के विनिर्माताओं तथा कुल मिलाकर जनता और उपभोक्ताओं की हानि के लिए वे कीमतें बढ़ाने में सक्षम होंगे, वह भी उस नाजुक अवधि में जब देश महामारी से लड़ रहा है। इससे चुनिंदा भारतीय "विटामिन सी" विनिर्माता अत्यधिक लाभ प्राप्त करेंगे, परंतु भारतीय फार्मास्युटिकल उद्यमों, खाद्य उद्यमों और पेय पदार्थ उद्यमों के लाभ को हानि पहुँचाएंगे और उपभोक्ताओं के संबंध में कोई उल्लेख ही नहीं है।
- ञ. भारत में इस उत्पाद की सही मांग-आपूर्ति स्थिति की जांच इस मामले में आगे कार्रवाई करने से पूर्व की जाए, ताकि भारत में आम जनता विटामिन सी टेबलेट से वंचित न हो।
- ट. पाटनरोधी शुल्क से इस दवाई की कीमत बढ़ेगी जिससे अधिक मृत्यु दर हो सकती है। इससे विश्व के समक्ष भारत का नाम खराब होगा।
- ठ. यदि पाटनरोधी शुल्क लगाया जाता है तो घरेलू उद्योग के पाटनरोधी शुल्क की राशि तक अपनी कीमत बढ़ाने की संभावना है। अतः आयातित तथा भारत में उत्पादित उत्पाद दोनों महंगे हो जाएंगे और उपभोक्ताओं को अधिक कीमत की लागत वहन करनी पड़ेगी।

## ठ.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

117. भारतीय उद्योग के हित के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोधों का सार निम्नलिखित है:

- क. उत्पादकों/निर्यातकों का अपना यह तर्क है कि पाटनरोधी शुल्क इतनी लम्बी अवधि के लिए लागू था। यद्यपि वर्तमान जांच एक नई जांच है, तथापि उत्पाद पर लम्बे समय से पाटनरोधी शुल्क लग रहा था। पाटनरोधी शुल्क का प्रतिकूल प्रभाव किसी भी पक्षकार द्वारा सिद्ध नहीं किया जा सका।
- ख. यहां तक कि जब शुल्क लागू रहा है, उत्पाद की न तो कमी थी, न ही वहन करने योग्य कीमत थी और न ही उपभोक्ताओं पर काफी प्रतिकूल प्रभाव था। यह सिद्ध है कि हितबद्ध पक्षकार गलत विवरणों और असिद्ध दावों का सहारा ले रहे हैं।
- ग. घरेलू उत्पादक बाजार दलों और उच्च प्रतिस्पर्धा के कारण अपनी कीमतों में अनुचित वृद्धि नहीं करेंगे और भारत के लोगों को दवाईयों की अबाधित आपूर्ति करने के लिए संकट के इस समय में आगे खड़े रहे हैं। इसके अतिरिक्त, इससे उपयुक्त कीमतों पर प्रयोक्ताओं के लिए बहु-विध घरेलू स्रोतों की निरंतर उपलब्धता होगी।
- घ. शुल्क लगाए जाने के बाद भी, मुक्त, उचित और उपयुक्त प्रतिस्पर्धा बाजार में विद्यमान रहेगी जिससे यह सुनिश्चित होगा कि शुल्क लगाना व्यापक जनहित में होगा।
- ङ. शुल्क लगाने से घरेलू उद्योग संबद्ध देश से पाटन के विरुद्ध संरक्षित होगा, एक उचित व्यापारिक क्षेत्र प्राप्त होगा और घरेलू उद्योग के निष्पादन की गिरावट का समाधान होगा।
- च. पाटनरोधी शुल्क उद्योग के लिए एक संरक्षण नहीं है बल्कि इसके बजाए उचित स्तरों पर कीमतों में सुधार का साधन है। इससे किसी भी तरह संबद्ध देश से आयात प्रतिबंधित नहीं होंगे और उपभोक्ताओं को उत्पाद की उपलब्धता प्रभावित नहीं होगी।
- छ. निर्यातकों/उत्पादकों को इससे अलग रहना चाहिए कि क्या पाटन हो रहा है। इन जनता के हित के कारकों से विदेशी उत्पादकों को परेशान नहीं होना चाहिए। घरेलू उद्योग जिम्मेदार और उत्तरदायी हैं।
- ज. चीन से आयात सबसे हाल की अवधि में बढ़े हैं, न कि उस समय जब कोविड-19 अपने पीक पर था। इसके विपरीत, जब कोविड-19 अपने पीक पर था, आयात मात्रा कम थी और कीमत अधिक थी।
- झ. जब आयात कीमत में गिरावट आई, तो आयात मात्राओं में वृद्धि हुई है। यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि चीनी उत्पादकों का कोविड-19 की अवधि के दौरान भारत की मांग से बहुत कम संबंध था।
- ञ. एक बार जब उनकी अपनी आंतरिक आवश्यकताएं पूरी हो गई हैं और कोविड-19 चल रहा था, तो चीनी उत्पादक भारत में कोविड-19 की स्थिति के प्रति जाग गए, कीमतें घटा दीं और भारी मात्रा में पाटन किया। यह भी दर्शाता है कि चीनी उत्पादकों की कार्यवाहियां विवरणों से भिन्न हैं।

## ठ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

118. प्राधिकारी ने इस बात पर विचार किया कि क्या पाटनरोधी शुल्क लगाने का जनहित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इसके लिए प्राधिकारी ने विभिन्न पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों की जांच की और क्या इस उत्पाद के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाना व्यापक जनहित के विरुद्ध होगा। यह निर्धारण रिकॉर्ड में उपलब्ध सूचना तथा घरेलू उद्योग, आयातकों और उत्पाद के उपभोक्ताओं सहित विभिन्न पक्षकारों के हितों पर विचार करने के आधार पर है।
119. प्राधिकारी ने जांच की शुरुआत के स्तर पर सभी हितबद्ध पक्षकारों से विचार आमंत्रित किए। प्राधिकारी ने उपभोक्ताओं के लिए उनके प्रचालनों पर पाटनरोधी शुल्क के संभावित प्रभाव सहित संगत सूचना प्रदान करने के लिए एक प्रश्नावली निर्धारित की है। केवल एक उपभोक्ता मैसर्स अबॉट हेल्थकेयर प्रा. लि. ने संगत सूचना प्रदान की। इसके अतिरिक्त, घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया कि यद्यपि वह विचाराधीन उत्पाद का एक उत्पादक है, तथापि वह उसका उपभोक्ता भी है और विटामिन सी टेबलेटों के रूप में बाजार में विटामिन सी निर्माण की बिक्री कर रहा है। घरेलू उद्योग ने विचाराधीन उत्पाद और निर्माण दोनों की लागत लेखापरीक्षा रिपोर्ट से संगत उद्धरणों के रूप में, विटामिन सी निर्माण के लिए अपनी लाभप्रदता दी है।

120. कोई भी हितबद्ध पक्षकार रिकॉर्ड में यह दर्शाते हुए कोई साक्ष्य नहीं लाया है कि विटामिन सी पर पाटनरोधी शुल्क लगाने के बाद उपभोक्ताओं पर इस पाटनरोधी शुल्क का काफी प्रतिकूल प्रभाव है।
121. इसके अतिरिक्त, इसका भी कोई साक्ष्य नहीं है कि इस लम्बी अवधि में पाटनरोधी शुल्क लगाने से या तो उत्पाद की कमी हुई है अथवा इस उत्पाद या निचले स्तर के उत्पाद की कीमतों में काफी वृद्धि हुई है।
122. प्राधिकारी नोट करते हैं कि विटामिन सी निर्माण की कीमत सरकार द्वारा विनिर्मित की जाती है और इसीलिए इस उत्पाद को किसी भी निर्माता द्वारा किसी भी कीमत पर नहीं बेचा जा सकता। चूंकि कीमत विनिर्मित की जाती है, अतः प्राधिकारी यह मानते हैं कि पाटनरोधी शुल्क लगाने से अंततः जनता के लिए अंतिम उत्पाद (विटामिन सी टेबलेट) की कीमत में काफी वृद्धि हो सकती है।
123. प्राधिकारी नोट करते हैं कि विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन देश में चार कंपनियों द्वारा किया जा रहा है। रिकॉर्ड में दी गई जानकारी के अनुसार, संयुक्त भारतीय क्षमता जांच की अवधि में 3,600 मी. टन है। इसके विपरीत, उत्पाद की मांग जांच की अवधि में 3,477 मी. टन थी और कोविड-19 महामारी के पीक में लगभग 5,200 मी. टन थी। घरेलू उत्पादकों ने भी महामारी के दौरान मांग में वृद्धि को देखते हुए अपनी क्षमताएं (5,280 मी. टन) बढ़ाईं। इस प्रकार, देश में विचाराधीन उत्पाद के लिए काफी क्षमताएं हैं।
124. प्राधिकारी ने विभिन्न पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों की जांच की और क्या इस उत्पाद के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाना व्यापक जनहित के विरुद्ध होगा। यह निर्धारण रिकॉर्ड पर उपलब्ध सूचना और घरेलू उद्योग, इस उत्पाद के आयातों और उपभोक्ताओं सहित विभिन्न पक्षकारों के हितों पर विचार करने के बाद किया जाता है।
125. प्राधिकारी ने आयातकों, उपभोक्ताओं और अन्य हितबद्ध पक्षकारों सहित सभी हितबद्ध पक्षकारों से विचार आमंत्रित करते हुए राजपत्र अधिसूचना जारी की। प्राधिकारी ने वर्तमान जांचों, उनके क्रियाकलापों पर पाटनरोधी शुल्क के संभावित प्रभाव सहित संगत सूचना उपलब्ध कराने के लिए उपभोक्ताओं के लिए इस संबंध में एक प्रश्नावली भी निर्धारित की। प्राधिकारी ने अन्य बातों के साथ-साथ विभिन्न देशों से विभिन्न आपूर्तिकर्ताओं द्वारा आपूर्ति किए गए उत्पाद की एक-दूसरे के स्थान पर उपयोग करने की क्षमता, स्रोत बदलने के लिए घरेलू उद्योग की क्षमता, उपभोक्ताओं पर पाटनरोधी शुल्क का प्रभाव, पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से उत्पन्न नई स्थिति के समायोजन को संभावित रूप से गति प्रदान करने अथवा उसमें विलंब करने वाले कारकों, वर्तमान शुल्क लगाने के प्रभाव के संबंध में सूचना मांगी। प्राधिकारी नोट करते हैं कि केवल एक उपभोक्ता ने प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत किया। जबकि उपभोक्ता ने यह सूचना दी कि इसे विटामिन सी सूत्रीकरण पर वित्तीय हानि हो रही थी, घरेलू उद्योग ने डाउनस्ट्रीम उत्पाद के उत्पादन और बिक्री से संबंधित अपनी स्वयं की जानकारी दिखाते हुए विस्तृत गणना प्रस्तुत की। जबकि एबोट ने यह दावा किया कि इसे डाउनस्ट्रीम उत्पाद में वित्तीय हानि हो रही थी, घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया कि विटामिन सी कीमत पर भी बहुत अधिक लाभप्रद थी। घरेलू उद्योग ने विटामिन सी सूत्रीकरण की बहुत अधिक मात्राओं की खरीद के लिए अनेक उपभोक्ताओं और राज्य सरकार के प्राधिकारियों द्वारा इसे दिए गए ऑर्डरों का ब्यौरा भी उपलब्ध कराया है। ये ऑर्डर उस कीमत से बहुत कम कीमत पर थे जिस पर घरेलू उद्योग बाजार में विटामिन सी सूत्रीकरण की बिक्री कर रहा है। घरेलू उद्योग ने यह भी दर्शाया है कि बहुत कमतर कीमत जिस पर इन ऑर्डरों को घरेलू उद्योग द्वारा लिया गया है, के बावजूद इन ऑर्डरों में भी लाभ हुआ था।
126. उपभोक्ताओं ने मौखिक सुनवाई में भाग लिया और अनुरोध किया, जिस पर विचार किया गया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि इन हितबद्ध पक्षकारों ने मात्रात्मक सूचना नहीं दर्शाई है कि पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने का या तो इन उपभोक्ताओं पर अथवा व्यापक रूप से आम जनता पर बहुत अधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।
127. प्राधिकारी यह मानते हैं कि पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से भारत में इस उत्पाद की कीमत स्तरों पर प्रभाव पड़ सकता है। हालांकि भारतीय बाजार में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा में पाटनरोधी शुल्कों को लगाए जाने से कमी नहीं आएगी। इसके विपरीत, पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से पाटन की कार्य-पद्धतियों द्वारा प्राप्त अनुचित लाभ समाप्त हो जाएंगे, घरेलू उद्योग की गिरावट रुक जाएगी और संबद्ध वस्तुओं के उपभोक्ताओं को अपेक्षाकृत अधिक व्यापक विकल्प की उपलब्धता बनाए रखने में मदद मिलेगी। पाटनरोधी शुल्कों का उद्देश्य आमतौर पर पाटन की अनुचित व्यापार कार्य-पद्धतियों के द्वारा घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करना है ताकि भारतीय बाजार में खुली और

निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा की स्थिति फिर से स्थापित हो सके, जो देश के सामान्य हित में है। इस कारण से पाटनरोधी शुल्क लगाने से उपभोक्ताओं को इस उत्पाद की उपलब्धता प्रभावित नहीं होगी। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्कों को लगाए जाने से किसी भी रूप में संबद्ध देश से आयातों पर रोक नहीं लगेगी और इस कारण से, उपभोक्ताओं को इस उत्पाद की उपलब्धता प्रभावित नहीं होगी।

128. प्राधिकारी ने विचाराधीन उत्पाद के प्रयोक्ता द्वारा प्रस्तुत की गई प्रश्नावली की जांच की है। प्राधिकारी यह पाते हैं कि विचाराधीन उत्पाद की लागत अंतिम दवा सूत्रीकरण की कुल उत्पादन लागतों का एक छोटा हिस्सा है। इस कारण से, विचाराधीन उत्पाद पर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के फलस्वरूप अंतिम दवा के उत्पादन की समग्र लागत में बहुत अधिक वृद्धि हो सकती है।

#### ड. निष्कर्ष

129. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों और उनमें उठाए गए मुद्दों की जांच करने और रिकॉर्ड पर उपलब्ध तथ्यों पर विचार करने के बाद प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि:

- क. संबद्ध वस्तुओं के लिए सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत पर विचार करते हुए, संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के लिए पाटन मार्जिन का निर्धारण किया गया है और मार्जिन बहुत अधिक है।
- ख. घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है। संबद्ध उत्पाद के आयातों और घरेलू उद्योग का कार्य-निष्पादन की जांच यह दर्शाती है कि संबद्ध देश से पाटित आयातों की मात्रा में 2017-18 तक वृद्धि हुई और जांच की अवधि तक उसमें गिरावट आई, हालांकि वह पूर्ण रूप में और उत्पादन तथा खपत की तुलना में बहुत अधिक रहती है। आयात बिक्री कीमत, क्षति रहित कीमत और बिक्री की लागत के स्तर से कम कीमत पर बाजार में हो रहे हैं। हालांकि उत्पादन और क्षमता के उपयोग में वृद्धि हुई लेकिन घरेलू बिक्री में गिरावट आई है। यह नोट किया जाता है कि जांच की अवधि में मालसूची के स्तर में वृद्धि हुई है। घरेलू उद्योग के कार्य-निष्पादन में जांच की अवधि में लाभ, नकद लाभ और लगाई गई पूंजी पर प्रतिफल के मामले में बहुत अधिक गिरावट आई है।
- ग. घरेलू उद्योग द्वारा उठाई गई वास्तविक क्षति पाटित आयातों के कारण पहुंचाई गई है।
- घ. किसी भी प्रयोक्ता ने संगत सूचना उपलब्ध नहीं कराई है। हितबद्ध पक्षकारों ने सत्यापन योग्य सूचना के साथ प्रयोक्ता उद्योग पर पाटनरोधी शुल्क के प्रभाव को सिद्ध नहीं किया है। पाटनरोधी शुल्क नहीं लगाए जाने से संबंधित उत्पाद के स्वदेशी उत्पादन पर प्रतिकूल रूप से प्रभाव पड़ेगा और यह तथ्य कि पाटनरोधी शुल्क का प्रभाव विचाराधीन उत्पाद के उपभोक्ताओं के लिए बहुत कम है, प्राधिकारी का यह मत है कि पाटनरोधी शुल्क लगाया जाना जनहित में होगा।
- ड. शुल्कों की लंबी अवधि के संबंध, हितबद्ध पक्षकारों के तर्क को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकारी ने लम्बी अवधि में आयातों की मात्रा और कीमत की जांच की। यह देखा गया है कि चीन से आयात शुल्क की संपूर्ण अवधि में महत्वपूर्ण मात्रा में जारी रहे हैं जो यह स्थापित करता है कि एडीडी की मौजूदगी के परिणामस्वरूप बाजार में चीन से आयातों की अनुपस्थिति नहीं हुई या चीनी आयातों से घरेलू उद्योग के लिए प्रतिस्पर्धा समाप्त नहीं हुई है। प्राधिकारी द्वारा आयोजित पिछली जांचें यह भी दर्शाती हैं कि आनुक्रमिक जांचों में प्राधिकारी ने यह पाया कि घरेलू उद्योग ने लगातार क्षति का सामना किया है। आयातों की पहुंच कीमत लगातार और उल्लेखनीय रूप से घरेलू उद्योग की बिक्रियों की लागत, बिक्री कीमत और क्षति रहित कीमत से कम रही है। पाटनरोधी शुल्कों की लंबी अवधि के बावजूद, एक उपभोक्ता को छोड़कर, किसी अन्य उपभोक्ता ने जांच में भाग नहीं लिया है। उपयोगकर्ताओं के असहयोग से पता चलता है कि उन पर नगण्य प्रभाव पड़ता है। जहां प्राधिकारी, आम तौर पर, पीओआई पश्चात् अवधि की जांच नहीं करते, तथापि, शुल्क की लंबी अवधि में हितबद्ध पक्षकारों के तर्क और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि वर्तमान क्षति अवधि शुल्क की अवधि थी, प्राधिकारी ने पाटनरोधी शुल्कों की समाप्ति के पश्चात् आयातों की मात्रा और कीमत की जांच की। यह देखा गया है कि जहां आयात कीमतें लगभग समान दायरे में बनी रही हैं, आयातों की मात्रा में महत्वपूर्ण रूप से वृद्धि हुई है यह दर्शाता है कि यदि शुल्क नहीं लगाया जाता है तो आयात में वृद्धि जारी रहेगी और घरेलू उद्योग को वास्तविक रूप से नुकसान होने की संभावना है।

**ढ. सिफारिशें**

130. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच आरंभ की गई थी और सभी हितबद्ध पक्षकारों को अधिसूचित किया गया था तथा पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंध के पहलुओं पर सूचना उपलब्ध कराने के लिए घरेलू उद्योग, निर्यातकों, आयातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को पर्याप्त अवसर दिया गया था। इस नियमावली के अंतर्गत निर्धारित प्रावधानों के संबंध में पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंध की जांच शुरू और उसे पूरा करने के बाद प्राधिकारी का यह मत है कि पाटनरोधी शुल्क लगाया जाना पाटन और क्षति के प्रभाव को निष्क्रिय करने के लिए अपेक्षित है। इस कारण से, प्राधिकारी संबद्ध देश के संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करते हैं।
131. इस नियमावली के नियम 4(घ) और नियम 17(1)(ख) में निहित प्रावधान के संदर्भ में, प्राधिकारी पाटन के मार्जिन और क्षति के मार्जिन में कमतर के बराबर पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करते हैं ताकि घरेलू उद्योग को क्षति समाप्त की जा सके। तदनुसार, नीचे दी गई शुल्क तालिका के कॉलम 7 में उल्लिखित राशि के बराबर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क चीन जन.गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यात किए गए शुल्क तालिका के कॉलम 3 में वर्णित वस्तुओं के सभी आयातों पर केन्द्र सरकार द्वारा जारी की जाने वाली अधिसूचना की तिथि से पांच (5) वर्षों के लिए लगाए जाने की सिफारिश करते हैं।

**शुल्क तालिका**

क्र.सं.	टैरिफ शीर्ष*	वस्तु का विवरण	मूलता का देश/अथवा निर्यात का देश	निर्यात का देश	उत्पादक	शुल्क राशि	मुद्रा	इकाई
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	29362700	विटामिन-सी*	चीन जन.गण.	चीन जन.गण. सहित कोई भी देश	मै. सीएसपीसी वीशेंग फार्मास्युटिकल (शिजियाजझुआंग) कं. लि.	3.20	यूएसडॉ.	किग्रा
2	29362700	विटामिन-सी*	चीन जन.गण.	चीन जन.गण.	क्र.सं. 1 के अलावा अन्य कोई उत्पादक	3.55	यूएसडॉ.	किग्रा
3	29362700	विटामिन-सी*	चीन जन.गण. के अलावा कोई देश	चीन जन.गण.	कोई	3.55	यूएसडॉ.	किग्रा

\*नोट: पाटनरोधी शुल्क विटामिन सी के सभी रूपों में विटामिन सी जिसे एसकोरबिक एसिड, एल-जाइलोएस्कोर्बिक एसिड, 3-ओक्सो एल-गुलोफुरानोलेक्टोन (इनोल रूप), एल-3 केटोथिरियोहेक्सुरोनिक एसिड लेक्टोन आदि के रूप में भी जाना जाता है, जैसाकि मर्क इंडेक्स की प्रविष्टि सं. "867" के अंतर्गत वर्णित है, पर लागू है। विटामिन सी का डेरिवेटिव्स वर्तमान जांच के क्षेत्र में नहीं है।

**ण. आगे की प्रक्रिया**

132. केन्द्र सरकार द्वारा इन जांच परिणामों को स्वीकार कर लिए जाने के बाद इनके विरुद्ध कोई अपील 1995 में यथा-संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 और सीमा शुल्क टैरिफ नियमावली, 1995 के अनुसार सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष की जाएगी।

अनंत स्वरूप, निर्दिष्ट प्राधिकारी

**MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY****(Department of Commerce)****(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)****NOTIFICATION****FINAL FINDINGS**

New Delhi, the 3rd September, 2021

**Case No. ADD-OI-27/2020****Subject: Anti-dumping investigation concerning imports of “Vitamin C” originating in or exported from China PR.**

**F. No. 6/32/2020-DGTR.**—Having regard to the Customs Tariff Act, 1975, as amended from time to time (hereinafter also referred to as the Act), and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time, (hereinafter also referred to as “the Rules” or “the AD Rules”) thereof.

**A. BACKGROUND OF THE CASE**

1. M/s. Bajaj Healthcare Limited (hereinafter also referred to as “the Applicant” or “the Domestic Industry” or “the petitioner”) filed an application before the Designated Authority in accordance with the Customs Tariff Act 1975 as amended from time to time (hereinafter also referred as the Act) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Antidumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 (hereinafter also referred as the “Anti-Dumping Rules” or “Rules”) for initiation of anti-dumping investigation and imposition of anti-dumping duty on imports of Vitamin C (hereinafter also referred to as “PUC” or “subject goods” or “product under consideration”), originating in or exported from People’s Republic of China (hereinafter also referred to as the “subject country”). M/s Amoli Organics Pvt Ltd, M/s Reckon Diagnostics Pr.t. Ltd., and M/s SR Biochem are other domestic producers of the subject goods who have supported the application filed by the applicant.

2. The Authority, on the basis of a sufficient evidence submitted by the applicant, issued a public notice dated 4<sup>th</sup> September 2020, published in the Gazette of India, initiating the subject investigation in accordance with Section 9A of the Act, read with Rule 5 of the Rules, to determine the existence, degree and effect of alleged dumping of the subject goods originating in or exported from subject country, and to recommend the amount of Anti-dumping duty (ADD), which if levied, would be adequate to remove the alleged injury to the domestic industry.

**B. PROCEDURE**

3. The procedure described herein below has been followed by the Authority with regard to the subject investigation:

- a. The Authority notified the Embassy of the Subject Country in India about the receipt of the present anti-dumping application before proceeding to initiate the investigation in accordance with Sub-Rule (5) of Rule 5 supra.
- b. The Authority issued a public notice dated 4<sup>th</sup> September 2020, published in the Gazette of India Extraordinary, initiating the anti-dumping investigation concerning imports of the subject goods from subject country.
- c. The Embassy of subject country in India was informed about the initiation of the investigation in accordance with Rule 6(2) of the Rules. The Authority sent a copy of the initiation notification to the Government of the subject country, through its Embassy in India, known producers/exporters from the subject country, known importers/users and the domestic industry as well as other domestic producers as per the addresses made available by the applicant and requested them to make their views known in writing within the prescribed time limit.
- d. The Authority provided a copy of the non-confidential version of the application to the known



producers/exporters and to the Government of the subject country, through its Embassy in India in accordance with Rule 6(3) of the Rules supra. A copy of the non-confidential version of the application was also made available in the public file and provided to other interested parties, wherever requested.

- e. The Authority also forwarded copy of the notice to known producers/ exporters from the subject country, known importers/users in India, other Indian producers and the domestic industry as per the addresses made available by the applicant and requested them to make their views known in writing within 30 days of the initiation notification. The Authority sent Exporter's Questionnaire to the following known producers/exporters to elicit relevant information in accordance with Rule 6(4) of the Rules:
  - i. M/s Hangzhou Think Chemical Co., Ltd.
  - ii. M/s CSPC Weisheng Pharmaceutical (Shijiazhuang) Co., Ltd
  - iii. M/s Northeast Pharmaceutical Group Co., Ltd.
  - iv. M/s Barentz (Shanghai) Commercial & Trading Co Ltd
  - v. M/s Sinoright International Trade Co Ltd
  - vi. M/s DSM Nutritional Products Asia Pacific
- f. The Embassy of the subject country in India was also requested to advise the exporters/producers from China PR to respond to the questionnaire within the prescribed time limit. A copy of the letter and questionnaire sent to the producers/exporters was also sent to them along with the names and addresses of the known producers/exporters from the subject country.
- g. In response to the initiation of the subject investigation, the following exporters/producers from the subject country filed exporter's questionnaire response:
  - i. M/s CSPC Weisheng Pharmaceutical (Shijiazhuang) Co., Ltd
  - ii. M/s Shandong Luwei Pharmaceutical Co Ltd.
- h. The Authority sent Questionnaire to the following known importers/users of subject goods in India calling for necessary information in accordance with Rule 6(4) of the Rules:
  - i. M/s CIPLA Limited
  - ii. M/s Global Exim
  - iii. M/s ValueTree India Pvt Ltd
  - iv. M/s Dsm Nutritional Products India Pvt Ltd.
  - v. M/s Planet Science
  - vi. M/s Confiance Life Sciences Pvt. Ltd
  - vii. M/s Maxheal Pharmaceuticals Ltd
  - viii. M/s Pulse Pharmaceuticals
- i. In response to the initiation of the subject investigation, the following importer/ consumer filed questionnaire response:
  - i. M/s Sevantilal & Sons
  - ii. M/s Abbott Healthcare Private Limited
- j. The Authority sent notice of initiation to the following other domestic producers, intimating them of the initiation of investigation with a request to provide relevant information to the Authority in the form and manner prescribed:
  - i. M/s Amoli Organics Pvt. Ltd.
  - ii. M/s Reckon Organics Pvt Ltd
  - iii. M/s S. R. Bio Chem

- k. None of the other domestic producers have participated in the present investigation.
- l. In response to the initiation of the subject investigation following have filed the submission to the Authority
  - i. Bulk Drugs & Allied Dealer Association
  - ii. Sandeep Organics Private Limited
- m. The Authority made available non-confidential version of the evidence presented by various interested parties in the form of e-file through email for the interested parties.
- n. Request was made to the Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCIS) to provide the transaction-wise details of imports of subject goods for the past three years, and the period of investigation, which was received by the Authority. The Authority has, relied upon the DGCIS data for computation of the volume of imports and its analysis after due examination of the transactions.
- o. The Non-injurious Price (NIP) based on the optimum cost of production and cost to make and sell the subject goods in India based on the information furnished by the domestic industry on the basis of Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) and Annexure III to the Rules has been worked out so as to ascertain whether anti-dumping duty lower than the dumping margin would be sufficient to remove injury to the domestic industry.
- p. Due to the worldwide outbreak of COVID-19 and consequent restrictions imposed by different countries, including India, the physical inspection through on-spot verification of the information was not carried out by the Authority. Remote cross check/Desk Verification of the information provided by the applicant/producers/ exporters, to the extent deemed necessary, was carried out by the Authority. Only such verified information with necessary rectification, to the extent deemed necessary, has been relied upon for the purpose of this final findings.
- q. Disclosure statement (NCV) was served to all interested parties with confidential version to concerned interested parties on 19/8/2021 through email along with reasonable time given for filing the comments, if any. Comments were received from interested parties, and the same has been taken on record by the Authority.
- r. Other submissions made by the interested parties during the course of this investigation, to the extent supported with evidence and considered relevant to the present investigation, have been appropriately considered by the Authority, in this final finding.
- s. The Period of Investigation for the purpose of the present anti-dumping investigation is from April 2019 – March 2020 (12 months). The examination of trends in the context of injury analysis covered the periods April 2016-March 2017, April 2017-March 2018, April 2018-March 2019 and the POI.
- t. Due to the worldwide outbreak of COVID-19 and consequent restrictions imposed by different countries, including India, the Authority in accordance with Rule 6(6) of the AD Rules and Trade Notice No. 01/2020 dated 10th April 2020, conducted oral hearing through video conferencing on 2<sup>nd</sup> March 2021 to provide an opportunity to the interested parties to present relevant information orally before the then Designated Authority in office. All the parties who had attended the above-mentioned oral hearings were advised to file written submissions of the views expressed orally, followed by rejoinders, if any. The arguments made in such written submissions and rejoinders received from the interested parties have been considered, to the extent deemed necessary, for the purpose of this final findings.
- u. Information provided by the interested parties on confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claim. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims wherever warranted and such information has been considered as confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non-confidential version of the information filed on confidential basis.
- v. The Authority has considered the arguments raised and information provided by all the

interested parties including post disclosure comments, to the extent the same are supported with evidence and considered relevant to the present investigation.

- w. Wherever an interested party has refused access to, or has otherwise not provided necessary information during the course of the present investigation, or has significantly impeded the investigation, the Authority has considered such parties as non-cooperative and recorded the final findings on the basis of the facts available.
- x. ‘\*\*\*’ in this final findings represents information furnished by an interested party on confidential basis and so considered by the Authority under the Rules.
- y. The exchange rate for the POI has been taken by the Authority as US\$1 = Rs. 71.65.

#### **C. PRODUCT UNDER CONSIDERATION AND LIKE ARTICLE**

4. At the stage of initiation, the product under consideration was defined as:

*3. The product under consideration is "Vitamin C in all its form", also known as ascorbic acid, L-Xyloascorbic Acid, 3-oxo L-Gulofuranolactone (enol form), L-3-*

*Ketothreohexuronic Acid Lactone etc., as described under entry number '867 of Merck Index'.*

*4. Vitamin-C is primarily used by the pharmaceutical's companies for production of various medicines. The product has uses also in non- pharmaceutical industry. Vitamin C is an essential nutrient involved in the repair of tissue and the enzymatic production of certain neurotransmitters found in various foods. It is required for the functioning of several enzymes and is important for immune system function. It also functions as an antioxidant'*

*5. The product under consideration is classified under chapter 29 of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) under customs sub-heading no.29362700. The customs classification is only indicative and is not binding on the scope of the product under consideration.*

##### **C.1 Views of the domestic industry**

5. The following are the submissions made by domestic industry with regard to product under consideration and like article:

- a. The product under consideration for the present investigation is “Vitamin C”, originating in or exported from China PR. Vitamin C is also known by various synonyms such as ascorbic acid, L-Xyloascorbic Acid, 3-oxo L-Gulofuranolactone (enol form), L-3-Ketothreohexuronic Acid Lactone etc., as described under entry number ‘867 of Merck Index’.
- b. The product under consideration should be considered as “Vitamin C/Ascorbic Acid”. The derivatives of Vitamin C are not within the purview of the present investigation.
- c. Vitamin-C is primarily used by the pharmaceutical’s companies for production of various medicines. However, the product has uses in non- pharmaceutical industry also. Vitamin C is an essential nutrient involved in the repair of tissue and the enzymatic production of certain neurotransmitters found in various foods. It is required for the functioning of several enzymes and is important for immune system function. It also functions as an antioxidant.
- d. There is some evidence that regular use of Vitamin C may reduce the duration of the common cold. The body uses vitamin C in many different ways and needed by the body to form collagen. Vitamin C is required to make skin, tendons, ligaments and blood vessels and to repair and maintain cartilage, bones and teeth, to heal wounds and to form scar tissue. It is used to prevent and treat scurvy. It is normally produced and sold in terms of net weight expressed in terms of kgs or MT.
- e. Vitamin C is classified under Chapter 29 of the Customs Tariff Act in the name of “Vitamin C and its derivatives”. The dedicated code for Vitamin C is 29362700. However, the customs classification is only indicative and is not binding on the scope of the present investigations.
- f. The goods produced by the applicant are like article to the imported goods as they are comparable in terms of chemical & technical characteristics, manufacturing process &

technology, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods, and are technically and commercially substitutable.

- g. There is no known significant difference in the technology employed by the domestic industry and the producers in subject country.
- h. The product under consideration is only the bulk drug and not the formulation. The price ceiling imposed under the Drugs (Price Control) Order, 2013 ("DPCO") is for formulation and not on API or Bulk drugs.
- i. The producers are not required to upload the certificate of analysis of their products on their website. The product produced by the domestic industry complies to all applicable norms. Same standards are also applicable on imports. The domestic industry produces and sells like article to the imported product.
- j. Any import of Vitamin C in India has to comply as per Indian Pharmacopoeia (IP) and same quality is manufactured by the domestic producers.
- k. The process adopted by an applicant is same as the process employed by the Chinese producers.

### **C.2. Views of the other interested parties**

- 6. The following are the submissions made by interested parties with regard to product under consideration and like article:
  - a. Certificate of analysis of Product under Consideration is not on their official Website. Website of one of the Domestic Industry is blank. The interested parties cannot compare the imported and domestic product.
  - b. Product is mainly in four forms. viz. tablet, powder, coated & uncoated. Difference in usage, pricing etc. needs to be investigated. Tablet is costlier. China mainly exports in powder form into India.
  - c. Import is subject to No Objection (NOC) from ADC (Assistant Drug Controller of India). They control the quality of the imports along with specific markings.
  - d. The production process adopted by the applicant is different from the Chinese producers and is not cost-effective, leading to self-inflicted injury.
  - e. PUC has many grades such as BP, USP, FOOD, FEED Grade etc. Price & usage differs as per grade.

### **C.3 Examination by the Authority**

- 7. The product under consideration, as defined in the notice of initiation, is "Vitamin C in all its form", also known as ascorbic acid, L-Xyloascorbic Acid, 3-oxo L-Gulofuranolactone (enol form), L-3 Ketothreohexuronic Acid Lactone etc., as described under entry number '867 of Merck Index'. Vitamin-C is primarily used by the pharmaceutical's companies for production of various medicines. The scope of the product under consideration is only Vitamin-C in bulk drug form, and not the formulation.
- 8. Vitamin C is an essential nutrient involved in the repair of tissue and the enzymatic production of certain neurotransmitters found in various foods. It is required for the functioning of several enzymes and is important for immune system function. It also functions as an antioxidant.
- 9. With regard to the post disclosure comments filed by one of the party to explicitly mention whether derivatives of Vitamin-C are not part of PUC, the Authority clarifies that the derivatives of Vitamin C are not within the purview of the present investigation.
- 10. The product under consideration is classified under chapter 29 of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) under customs sub-heading no. 29362700. The Customs classification is indicative only and not binding on the scope of the investigation.
- 11. As regards absence of certificate of analysis on the website of the domestic producers, the Authority notes that there is no statutory requirement to upload certificate of analysis on the websites. Further, the

domestic producers are selling to a number of consumers in India and it should not be a bottleneck for them to obtain certificate of analysis of the domestic producer's product.

12. As regards existence of various grades and forms of the product, it is clarified that the scope of the product under consideration is only bulk drug and not the formulation. The forms of the product specified by the interested parties appears relevant for formulation of the product.
13. As regards difference in production process adopted by the applicant and Chinese producers, the Authority notes that the difference in the production process or difference in starting raw material does not make two products different, unless the properties of the product itself are different. The interested parties have however not established difference in the properties of the product.
14. The sale of the product in the Indian market either through domestic manufacturers or the imports has to comply as per Indian Pharmacopoeia (IP) and therefore the product sold by the parties should have comparable quality. As far as formulation is concerned, the price of the same is controlled by Govt. of India.
15. The applicant claimed that the Vitamin C produced by it and that imported from the subject country are produced using the same basic raw materials having broadly similar manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification. The contention of the applicant has not been disputed by the other interested parties. The product was subject to antidumping duty in the past and there was no established difference between the domestic and imported product. The Authority determined to hold that the subject goods produced by the domestic industry are like article to the product imported from subject country in terms of Rule 2(d) of the Rules.

#### **D. SCOPE OF DOMESTIC INDUSTRY AND STANDING**

##### **D.1 Views of the domestic industry**

16. Following are the submissions made by the domestic industry with regard to scope of the domestic industry and standing:
  - a. The Application has been filed by M/s. Bajaj Healthcare Limited.
  - b. There are three more producers of the product under consideration in the country namely,
    - i. M/s Amoli Organics Pvt Ltd,
    - ii. M/s Reckon Diagnostics Pvt. Ltd. and
    - iii. M/s SR Biochem.
  - c. All the three other producers of the product under consideration have supported the application and the present investigation.
  - d. The applicant is neither related to an importer in India nor to an exporter from the subject country and has not imported the product under consideration from the subject country.
  - e. The applicant holds a major proportion of total domestic production of the subject goods in India and thus, constitutes domestic industry.

##### **D.2. Views of the other interested parties**

17. Following are the submissions made by the other interested parties with regard to scope of the domestic industry and standing:
  - a. The applicant must provide injury data for the domestic producers supporting the Application, which it claims taken together, constitutes the domestic industry.

##### **D.3. Examination by the Authority**

18. Rule 2(b) of the Rules defines domestic industry as under:

*“domestic industry” means the domestic producers as a whole engaged in the manufacture of the like article and any activity connected therewith or those whose collective output of the said article constitutes a major proportion of the total domestic production of that*

*article except when such producers are related to the exporters or importers of the alleged dumped article or are themselves importers thereof; in such case the term 'domestic industry' may be construed as referring to the rest of the producers”.*

19. The application has been filed by M/s. Bajaj Healthcare Limited. The applicant is not related to any importer or exporter of subject goods in the subject country, nor have they imported subject goods from subject country. The applicant is the largest producer of the subject goods in the country.
20. The application filed by the applicant is supported by M/s Amoli Organics Pvt Ltd, M/s Reckon Diagnostics Pvt. Ltd., and M/s SR Biochem other domestic producers of the product under consideration.
21. The Authority sent communication to other domestic producers advising them to file relevant information in the form and manner prescribed with regard to injury determination. However, none of other domestic producers have filed complete injury information in the prescribed format.
22. The Authority notes that the Authority has prescribed a format for the supporters to enable these supporters lodge their claim with regard to possible injury suffered by them. Therefore, the Authority has not examined possible injury to these supporters in the present case since these supporters have not provided relevant information. However, in a situation where supporting domestic producer has not provided relevant information in prescribed format, but have nonetheless expressed support to the application, the Authority notes that such support is required to be accepted within the meaning of Rule 5.
23. The evidence on record shows that the applicant commands a major proportion (46%)/ (40%-50%) in the total domestic production in India. Further, the applicant, along with the supporter, account for 100% of the total production of the subject goods in India. Accordingly, the Authority holds that the applicant constitutes domestic industry within the meaning of Rule 2(b) of the Rules and considers that the application satisfied the criteria of standing in terms of Rule 5(3) of the Rules.

## **E. CONFIDENTIALITY**

### **E.1 Views of the domestic industry**

24. The following submissions have been made by the domestic industry with regard to confidentiality:
  - a. The response circulated by M/s Sinobright Pharmaceutical Industries Limited vide mail dated 1st March 2021 is too belated and should not be accepted by the Authority. The last date to submit the response was 27<sup>th</sup> November 2020.
  - b. The interested parties have filed grossly deficient response in non-confidential version even after being given an extension to file sufficient and complete information. The same is purely with the intent to prevent the domestic industry from defending its legitimate interests. The questionnaire responses are required to be rejected
  - c. The foreign producers have claimed excessive confidentiality with regard to shareholding structure, production process, value chain, production facilities, related parties, procurement of raw materials, list of products produced and/or sold, name of the holding company, shareholding details, channel of marketing in the home market and for exports to India are claimed as confidential,
  - d. No indexed version provided for the information claimed as confidential.
  - e. The exporters even failed to specify the raw material used for manufacturing the subject goods.
  - f. The applicant has been denied sufficient details to permit a reasonable understanding of the substance of the response submitted by the Authority. The applicant cannot even determine the extent to which information has been provided and whether any reliance can be placed on the same. As a result, the applicant is severely handicapped and unable to comment on the response filed by the exporter.

### **E.2 Views of the other interested parties**

25. The following submissions have been made by other interested parties with regard to confidentiality:

- a. In spite of ADD duties for past 22 years still domestic industry is seeking protection by claiming excessive confidentiality in disclosing the facts.

### **E.3 Examination by the Authority**

26. Various submissions made by the applicant as well as other interested parties during the course of the investigation with regard to confidentiality, to the extent considered relevant by the Authority, have been examined and addressed as follows.
27. The Authority made available non-confidential version of the information provided by various interested parties to all interested parties through the public file containing non-confidential version of evidences submitted by various interested parties for inspection as per Rule 6(7).
28. With regard to confidentiality of information, Rule 7 of the Rules provides as follows:

*“Confidential information: (1) Notwithstanding anything contained in sub-rules (2), (3) and (7) of rule 6, sub-rule(2) of rule 12, sub-rule(4) of rule 15 and sub-rule (4) of rule 17, the copies of applications received under sub-rule (1) of rule 5, or any other information provided to the designated authority on a confidential basis by any party in the course of investigation, shall, upon the designated authority being satisfied as to its confidentiality, be treated as such by it and no such information shall be disclosed to any other party without specific authorization of the party providing such information.*

*(2) The designated authority may require the parties providing information on confidential basis to furnish non-confidential summary thereof and if, in the opinion of a party providing such information, such information is not susceptible of summary, such party may submit to the designated authority a statement of reasons why summarization is not possible.*

*(3) Notwithstanding anything contained in sub-rule (2), if the designated authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorise its disclosure in a generalized or summary form, it may disregard such information.”*

29. As regards the contentions with regard to confidentiality of information, information provided by the interested parties on confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claim. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims, wherever warranted and such information has been considered confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non confidential version of the information filed on confidential basis. The Authority made available the non-confidential version of the evidence submitted by various interested parties in the form of public file. The information related to imports, performance parameters and injury parameters of domestic industry has been made available in the public file. Business sensitive information has been kept confidential as per practice.

## **F. MISCELLANEOUS SUBMISSIONS**

### **F.1 Views of the other interested parties**

30. The following submissions have been made by the other interested parties with respect to miscellaneous issues:
  - a. After enjoying uninterrupted 22 years long Anti-Dumping Duty at the rate USD 3.74/Kg the domestic manufacturers have again filed an application for fresh investigation.
  - b. The said protection subsisted with stated objective of providing protection from injury to concerned Industry as also that Industry shall endeavor to develop necessary skill technology and resources to make Country self-reliant for PUC. But domestic industry continues to remain 100% dependent on China as they continue to procure penultimate stage intermediate (2 KGA) from China.

- c. The domestic industry has made no progress at all towards self-reliance on 2KGA even after unreserved support of ADD duties. ADD has been providing them windfall profit, and there is no urge for backward integration. The domestic producers do not care for ultimate aim of Government which should have remained single focal point.
- d. Since 1998 the Authority has imposed of Anti-Dumping duty which has resulted in creation of monopoly in favour of applicant in the Indian Domestic market.
- e. India is not a key market for exports from China as only small portion out of total exports is exported to India. Export orientation of Chinese producers is directed towards the US and EU and not towards India. China has near monopoly on World “Vitamin C” production and the same does not come within the ambit of anti-dumping laws. It is completely misplaced that exporters from China wish to dump “Vitamin C” in India.
- f. The Authority should investigate why the Indian industry is still not able to compete with global players in spite of protection of duty for more than 22 years.
- g. Product under consideration is one of the basic & preliminary medicine against COVID as prescribed by Indian Council for Medical Research (ICMR) and is widely used in COVID. There should be no anti-dumping duty on the product in this pandemic. ADD will restrict the availability of product at fair rate and the petitioner does not need any protection.
- h. In case ADD is imposed, the domestic industry is likely to increase its price to the tune of ADD hence both imported as well as products produced in India will become costlier and the consumers will have to bear the higher price. In the past 5 years, due to the antidumping duty on “Vitamin C”, the sales price remained at level of more than USD 6/kg in India, and even reached to USD10/KG sometimes.
- i. Anti-dumping will increase the price of this medicine which will have an adverse effect on public at large, especially poor people (India has maximum poor people). It can lead to high mortality rate. It will spoil India’s name in the World.
- j. Conduct and commercial exploitation by domestic industry has adversely affected and has let down country’s interest. Stated purpose and the aims have been completely overlooked in pursuit of commercial exploitation.
- k. Implementation of antidumping duty only makes the selected Indian manufactures gain excessive profit, but harm the benefit of India pharmaceutical enterprises, food enterprises and beverage enterprises which uses “Vitamin C” to produce their own products, not to mention about the plight of the consumers.
- l. It would not be advisable to impose Anti-Dumping Duty on Vitamin C because even after protection for 22 years the domestic industry has seen only their motive and it has been a burden on Indian consumer to pay more for product which is available at much cheaper rate. This itself proves that there is no dumping.
- m. If Government feel that domestic industry has to be protected, then 13% of CIF value as extra input duty can be imposed or equivalent Anti-Dumping Duty should be imposed which roughly comes to USD 0.58/Kg. If duty of USD 3.74/Kg is reimposed then it will have no merit and would mean abuse of the provision.
- n. Contrary to the submission made by the applicant the product under consideration has substitutes (viz. citric acid, potassium bromate, azodicarbonamide).
- o. Since the product is an API, its availability & pricing is very important.
- p. The domestic industry has even suo moto cancelled its agreed supply contracts and has engaged in price rigging and cartelization.
- q. Both imports and domestic industry have been benefitting from the high demand conditions. PUC does not have any fixed demand as it depends on the market situation which is fluctuating.



- r. There are two sets of contrary/incorrect data provided by the applicant therefore, the interested parties are not able to provide any meaningful comments and have not been able to fully participate in the investigation.
- s. Domestic industry did not file for initiation of SSR review and instead filed for a fresh investigation deliberately as there was no likelihood of further injury.
- t. The Appellate Body in US-Corrosion Resistant Steel Sunset Review had noted that a likelihood determination is prospective determination, and that investigating authorities must undertake a forward-looking analysis to seek to resolve the issue of what would be likely to occur if the duty was terminated.
- u. The domestic industry has increased the prices from April 2020 to August 2020 by more than 60% which is without increase in cost of production thereby resorting to profits. That within a short period of 3 months only, the domestic industry was able to make 78% (in the quarter ended 30 September 2020) and 56% (in the quarter ended 30 June 2020) of the profits made during the 12 months ended on 31 March 2020.
- v. Due to the background of this case, post POI data should be analysed to understand the state of affairs of the domestic industry.
- w. After the sudden rise in demand, the Respondents have significantly increased its production so that there is no shortage during the pandemic, and this is despite the fact that DPCO has fixed the price cap of Rs. 23.02 per strip for the final product.
- x. The product under consideration is an essential drug. To enjoy the monopolistic privileges, the Domestic Industry has undermined the importance and necessity of the subject goods in the country.
- y. By imposing anti-dumping duties on an essential drug like Vitamin C, which also serves other benefits to the society, the claim of the industry would tantamount to a disservice to the country by inflating the prices of a product that is of vital importance, especially in the present times.
- z. The supporting producers along with the petitioner formed the cartel and hiked the prices in tandem. Thus, the domestic industry engaged in price rigging at the cost of health of general public in the middle of global pandemic.
- aa. It would not be in public interest to impose a duty on imports of PUC which is a key API for manufacture of Vitamin C drug which could save the lives of people of the country in Covid-19 pandemic.
- bb. The Authority must also consider the regulatory framework of Vitamin C finished product and its impact on the patient/ end consumer.
- cc. In the long run, the end consumers could be left with only the option of FSSAI category Vitamin C which are not subject to pricing restrictions and may not cater to patients' requirement of therapeutic dosage of 500mg.
- dd. From April 2020 to August 2020, the domestic industry has increased the prices of PUC by more than 60% without any commensurate increase in their cost of production thereby resorting to profiteering at the cost of suffering public in the COVID-19 pandemic situation given the fact that Vitamin C finished product was in extremely high demand as a vital immunity booster.
- ee. Vitamin-C tablet is generally taken to boost immunity especially during the ongoing Covid-19 pandemic. Thus, imposition of anti- dumping duty will have an adverse impact on ability to manufacture and maintain a consistent supply of the tablets and may ultimately impact public interest.
- ff. Re-imposition of anti- dumping duty on imports of PUC will result in monopoly of the domestic industry and will empower them continue the price increases to the detriment of manufacturers of the finished formulations of Vitamin C, as well as of the public and consumers at large, more so in such a critical period when the country is fighting the pandemic. It will make selected Indian "Vitamin C" manufactures gain excessive profit, but harm the benefit of India pharmaceutical

enterprises, food enterprises and beverage enterprises, not to mention about the plight of the consumers.

gg. An examination of true demand supply situation of this product in India may be done before proceeding further in this matter so that the general public is not deprived of Vitamin C tablets in India.

hh. In case ADD is imposed, the domestic industry is likely to increase its price to the tune of ADD hence both imported as well as products produced in India will become costlier and the consumers will have to bear the cost of higher price.

### **F.1 Views of the domestic industry**

31. The following submissions have been made by the applicant with respect to miscellaneous submissions:

- a. The exporters of the subject countries got extension for filing responses twice, even then the exporter took 84 days to file questionnaire response.
- b. The POI ended with the beginning of lockdown, therefore the petition did not have any reference to surge in demand during lockdown triggered by COVID-19.
- c. Public interest factors should not bother exporters, as India's interest is none of their concerns.
- d. The Authority does not have practice of analyzing the post POI Injury data in a fresh investigation.
- e. M/s. Abbott India Ltd never fulfilled their contractual obligations and were habitually dis-honoring their contractual obligations at their convenience. Sale purchase is based on the contractual negotiations which is followed by the applicant for the complete agreed quantity to be sold for the year.
- f. The imposition of ADD will not result in any significant adverse impact on the end product and the imposition will be in the larger public interest. ADD is a redressal of unfair price discrimination by the producers in other countries, which is injurious to the industry in India.
- g. The price ceiling imposed under the DPCO is for formulation and not on API or Bulk drugs.
- h. The domestic industry will not unduly increase their prices due to market forces and fair competition existing in the market. In fact, domestic industry has stood upfront at this time of Covid crises and supplied product for use by the citizen of the Country.
- i. The responding exporters have raised concern about different data at different places for first time at the time of oral hearing. The applicant cleared these discrepancies vide mail dated 9th March 2021.
- j. The present investigation is a fresh investigation; hence the Authority does not have the practice of analyzing the post POI injury data.
- k. It is producers/exporters' own argument that the ADD was in place for such a long period. While the present investigation is a fresh investigation, the product was attracting ADD for quite some time. No adverse effect of the ADD could be established by any party.
- l. Even when duty has been in place, there was neither a shortage nor unbearable price of the product, nor significant adverse impact on the consumers. Evidently, the interested parties are resorting to misstatements and unsubstantiated claims.
- m. The domestic producers will not unduly increase their prices due to market forces and high competition and have stood upfront at this time of crises to have an uninterrupted supply of medicines to the people of India. Further, this will lead to continued availability of multiple domestic sources for the users, at reasonable prices.
- n. Even after imposition of duties, free, fair and reasonable competition will prevail in the market, thereby ensuring that the imposition will be in the larger public interest.
- o. The imposition of duty will protect the domestic industry against dumping from the subject country, provide a level playing field and address the decline of the domestic industry's performance.

- p. Anti-dumping duty is not a protection to the industry, but rather a means of correction of prices to fair levels. It would not restrict imports from the subject country in any way and would not affect the availability of the product to the consumers.
- q. The exporters/producers should confine themselves to whether there is dumping. Such public interest factors should not bother foreign producers. The domestic industry is responsible and responsive.
- r. The imports from China have increased in the most recent period and not when Covid-19 was at its peak. On the contrary, when Covid-19 was at its peak, the import volumes were low and the price was high.
- s. When the import price has declined, the import volumes have increased. It clearly shows that the Chinese producers were least concerned with the India's demand during Covid-19 period.
- t. Once their own internal requirements have been met, and Covid-19 was on way out, the Chinese producers woke up to the Covid-19 situation in India, reduced prices and dumped huge volumes. This also shows that the Chinese producers' actions are different from statements.

### **F.3 Examination by the Authority**

- 32. The Authority has examined the submissions made by various interested parties and considered the same, having regard to the legal provisions and evidence provided by the interested parties.
- 33. With regard to the contention that instead of filling review petition, a fresh application has been filed, the Authority notes that an applicant did file application for a sun set review (SSR), however, the same was not accepted by the Authority on technical ground as the same was way outside the time limit specified to file SSR application.
- 34. Since the present investigation is a fresh investigation, the Authority does not consider the post POI data. Further, there are review provisions under the Rules to address the developments in subsequent period.
- 35. With regard to domestic producers' dependency on China for 2KGA, the Authority notes that the production from 2-Ketogluconic Acid to Vitamin-C constitutes production and involves significant value addition. Further, volatility of the raw material prices or exchange rates is expected to impact the price of both the raw materials and finished product. It is not established how these changes could selectively impact profitability of the product alone.
- 36. Regarding inability of domestic producers to produce 2 KGA, the Authority considers that the same is beyond the scope of the present investigations.
- 37. Regarding monopoly of domestic industry, the Authority notes that there are four manufacturers of Vitamin C in India thus showing significant domestic competition. Further, there are review provisions under the Rules to address the developments in subsequent period.
- 38. The Authority has noted that India and China are the only manufacturers of vitamin C bulk drug. Other countries in the world, purchase Vitamin C bulk drug from India and China and sell the formulation.
- 39. With regard to the contention that ADD will restrict the availability of product at fair rate, the Authority notes that none of the interested parties have shown how anti-dumping duty in the past adversely impacted the price of the end product or public at large. Further, Vitamin C falls under DPCO and therefore prices of the end product are regulated.
- 40. With regard to the contrary set of injury data provided by the applicant, it is noted that the same was rectified by the domestic industry. It is also noted that the variations are not material. In any case, the Authority has adopted information which has been remote cross checked.
- 41. As regards arguments of public interest, it is noted that the purpose of anti-dumping duty is only to address unfair practice of dumping.

**G. MARKET ECONOMY TREATMENT (MET), NORMAL VALUE, EXPORT PRICE & DETERMINATION OF DUMPING MARGIN**

42. Under Section 9A(l)(c) of the Act, normal value in relation to an article means:

*(i) the comparable price, in the ordinary course of trade, for the like article when meant for consumption in the exporting country or territory as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or*

*(ii) when there are no sales of the like article in the ordinary course of trade in the domestic market of the exporting country or territory, or when because of the particular market situation or low volume of the sales in the domestic market of the exporting country or territory, such sales do not permit a proper comparison, the normal value shall be either-*

*(a) comparable representative price of the like article when exported from the exporting country or territory or an appropriate third country as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or the cost of production of the said article in the country of origin along with reasonable addition for administrative, selling and general costs, and for profits, as determined in accordance with the rules made under sub-section (6):*

*(b) Provided that in the case of import of the article from a country other than the country of origin and where the article has been merely transshipped through the country of export or such article is not produced in the country of export or there is no comparable price in the country of export, the normal value shall be determined with reference to its price in the country of origin.*

**G.1 Views of the domestic industry**

43. The following submissions have been made by the applicant with respect to determination of normal value, export price and dumping margin:

- a. China should be considered as a non-market economy, in line with the position taken by the Authority in previous cases, and by investigating authorities in other countries.
- b. The cost and price of the Chinese producers cannot be relied upon for determination of normal value, and accordingly, the normal value should be determined in accordance with the provisions of para 7 of Annexure I of the Rules.
- c. The applicant has determined the normal value of subject goods based on international prices of the raw materials as available in the public domain and considering the conversion cost of the domestic industry duly adjusted with selling, general and administrative expenses and a reasonable amount of profit.
- d. Export price is based on transaction wise import data provided by DGCI&S, Kolkata. The export prices being CIF value while the normal values being at ex-factory level, the export prices have been adjusted for, ocean freight, marine insurance, commission, inland freight expenses, port expenses, bank charges and VAT.
- e. There is no basis for the claim made unless the data provided by the responding exporters for export price is complete in all respect. Further, the Authority should first decide whether such belated response should be accepted.
- f. The dumping margin of the imports from the subject country is not only above de minimis levels, but also significant.

**G.2 Views of the other interested parties**

44. The following submissions have been made by the other interested parties with respect to determination of normal value, export price and dumping margin:

- a. The export price, landed value and dumping margin should be determined on the basis of the data submitted in the exporter's questionnaire response.
- b. CSPC, one of the major producer/exporters, undertakes to revise selling price for the purpose of export to India to the level/rate which according to the Authority does not result in dumping of "Vitamin C" and addresses injury to the domestic industry. In other words, CSPC undertakes to fix the selling price of "Vitamin C".
- c. The determination of normal value for China PR is completely erroneous and baseless as it based on information provided by the applicant, who is monopolizing the Indian domestic industry and is the major beneficiary of the duty.
- d. The sales price from China is higher than the cost. From 2018 to 2020, each Chinese factory which is in normal operation earns money from this product, which can be proved through the financial reports. Also, the average export price from China to other countries are same as the average price of "Vitamin C" exported to India. Only India imposes the antidumping taxes, which is against the norms of WTO.
- e. The material available on record does not establish that the "Vitamin C" is being exported is at a price lower than its normal value.
- f. The premise for treating China PR as Non-Market Economy is erroneous.
- g. 2KGA, the main raw material, used in production of the subject goods should not form the basis of normal value computation. 2KGA constitutes nearly 50% of the cost of production of the subject goods, the use of international prices of 2KGA would skew the normal value upwards. The Authority must adjust the above input procurement costs and attendant costs relating to importation of 2KGA while constructing the normal value for China.
- h. There is no basis/evidence to make a prima facie view that PUC from China PR is being dumped in Indian Market. The basis of arriving at the "margin of dumping" that is the difference between the normal price and the export price is completely irrational and cannot be acted upon.
- i. Normal value constructed based on cost of production in India is impermissible.
- j. The Chinese manufacturer gets 13% tax back from Chinese Government when they export Vitamin C. So, the contention that the export price is not at a normal price is only to the extent of 13%.
- k. The Authority may determine individual dumping and injury margin for the producer/exporter in this submission who has filed the EQR in this matter.

### **G.3 Examination by the Authority**

#### **G.3.1 Determination of normal value and export price**

##### **Market economy status for Chinese Producers**

45. Article 15 of China's Accession Protocol in WTO provides as follows: "Article VI of the GATT 1994, the Agreement on Implementation of Article VI of the General Agreement on Tariffs and Trade 1994 ("Anti-Dumping Agreement") and the SCM Agreement shall apply in proceedings involving imports of Chinese origin into a WTO Member consistent with the following:

*"(a) In determining price comparability under Article VI of the GATT 1994 and the Anti-Dumping Agreement, the importing WTO Member shall use either Chinese prices or costs for the industry under investigation or a methodology that is not based on a strict comparison with domestic prices or costs in China based on the following rules:*

*(i) If the producers under investigation can clearly show that market economy conditions prevail in the industry producing the like product with regard to the manufacture, production and sale of that product, the importing WTO Member shall use Chinese prices or costs for the industry under investigation in determining price comparability;*

*(ii) The importing WTO Member may use a methodology that is not based on a strict comparison with domestic prices or costs in China if the producers under investigation cannot clearly show that market economy conditions prevail in the industry producing the*

*like product with regard to manufacture, production and sale of that product.*

*(b) In proceedings under Parts II, III and V of the SCM Agreement, when addressing subsidies described in Articles 14(a), 14(b), 14(c) and 14(d), relevant provisions of the SCM Agreement shall apply; however, if there are special difficulties in that application, the importing WTO Member may then methodologies for identifying and measuring the subsidy benefit which take into account the possibility that prevailing terms and conditions in China may not always be available as appropriate benchmarks. In applying such methodologies, where practicable, the importing WTO Member should adjust such prevailing terms and conditions before considering the use of terms and conditions prevailing outside China.*

*(c) The importing WTO Member shall notify methodologies used in accordance with subparagraph (a) to the Committee on Anti-Dumping Practices and shall notify methodologies used in accordance with subparagraph (b) to the Committee on Subsidies and Countervailing Measures.*

*(d) Once China has established, under the national law of the importing WTO Member, that it is a market economy, the provisions of subparagraph (a) shall be terminated provided that the importing Member's national law contains market economy criteria as of the date of accession. In any event; the provisions of subparagraph (a)(ii) shall expire 15 years after the date of accession. In addition, should China establish, pursuant to the national law of the importing WTO Member, that market economy conditions prevail in a particular industry or sector, the non-market economy provisions of subparagraph (a) shall no longer apply to that industry or sector."*

46. It is noted that while, the provision contained in Article 15 (a) (ii) have expired on 11.12.2016, the provision under Article 2.2.1.1 of WTO read with obligation under 15 (a) (i) of the Accession protocol require criterion stipulated in para 8 of the Annexure I of the Rules to be satisfied through the information/data to be provided in the supplementary questionnaire on claiming the market economy status. It is noted that since none of the responding producers and the exporters from China PR have submitted relevant questionnaire response, the normal value computation is required to be determined as per provisions of para 7 of Annexure I of the Rules. Accordingly, the normal value and export price for the producers/ exporters from the subject country have been determined as below.

### **G.3.2 Determination of Normal Value for all producers in China PR**

47. The following Chinese producers/exporters filed Market Economy Treatment (MET) questionnaire response and claimed market economy status:

a. M/s CSPC Weisheng Pharmaceutical (Shijiazhuang) Co., Ltd.

48. In the absence of sufficient information on record, regarding the other methods as enshrined in Para 7 of Annexure I of the Rules, the Authority has determined the normal value by considering the method on "any other reasonable basis, *including the price actually paid or payable in India for the like product, duly adjusted, if necessary, to include a reasonable profit margin*".

49. There are imports of subject goods from Singapore as well, however, as per information on record there is no production facility for manufacturing the subject good in Singapore. The Authority has, therefore, constructed the normal value for China PR on the basis of international prices of the raw materials as available in the public domain and considering the conversion cost of the domestic industry duly adjusted with selling, general and administrative expenses and addition of reasonable profits. Accordingly, the constructed normal value so determined for Chinese producers/ exporters is mentioned in the dumping margin table below.

### **G.3.3 Determination of Export Price**

a. M/s Shandong Luwei Pharmaceutical Co Ltd.

50. M/s Shandong Luwei Pharmaceutical Co Ltd. is a producer of the subject goods in China PR and has exported the product to India. It is noted that during the POI, M/s Shandong Luwei Pharmaceutical Co Ltd. has claimed to have exported \*\*\*MT of subject goods directly to unrelated customers in India. In the disclosure statement, the CIF export price had been determined on the basis of the questionnaire response filed and had been adjusted towards inland freight, ocean freight, insurance, port & other related expenses and bank charges, details of which were examined through remote cross check/desk

verification to the extent feasible. Accordingly, the net export price for the PUC at ex-factory level for M/s Shandong Luwei Pharmaceutical Co Ltd. had been proposed to be determined accordingly.

51. Post issuance of Disclosure statement to the interested parties, other Chinese producer i.e, M/s CSPC Weisheng Pharmaceutical (Shijiazhuang) Co., Ltd by referring export details as per China Customs, alleged that M/s Shandong Luwei Pharmaceutical Co Ltd. has not reported the complete/factual data on its exports to India hence, resulting in doubtfully lower margins. Further, the domestic industry has also filed similar comments by submitting bill of entry wise details of exports made by M/s Sinoright International Trade Co., Ltd. alleging that Shandong Luwei Pharmaceutical has also sold the subject goods to India during the POI through an unrelated company/trader in China i.e., M/s Sinoright International Trade Co., Ltd. Further, the domestic industry provided a document stating that Shandong Luwei Pharmaceutical has appointed Sinoright International Trade as its agent and the document clearly states that *"Shandong Luwei Pharmaceutical Co., Ltd. hereby authorize M/s Sinoright international Trade Co Ltd as the Exclusive Agent in India for the commercial activities, marketing and Sales for Ascorbic Acid"*. Considering the vital facts involved, the Authority gave M/s Shandong Luwei Pharmaceutical Co Ltd. an opportunity to offer its comment on the above, to which the company responded that the agreement concerning Shandong Luwei Pharmaceutical appointing Sinoright International Trade as its agent was later revoked by the company. Further, the Authority called for bill of entry details including the commercial invoices, packing list, certificate of origin etc., and Form-9 & 10 from the Office of Jawaharlal Nehru Custom House (Department of Revenue, Ministry of Finance) and the Office of CDSCO (Central Drugs Standard Control Organization (Directorate General of Health Services, Ministry of Health and Family Welfare). On examining the same, it is concluded that Shandong Luwei Pharmaceutical Co., Ltd has not reported all the exports made to India and has not come clean on all transactions made to India. Therefore, the Authority has rejected the response filed by the company and has not determined individual margins for the company.

**b. M/s CSPC Weisheng Pharmaceutical (Shijiazhuang) Co., Ltd. & M/s Sinobright Pharmaceutical Industries Limited**

52. M/s CSPC Weisheng Pharmaceutical (Shijiazhuang) Co., Ltd. is a producer of the subject goods in China PR, and has exported the product to India directly, and also through M/s Sinobright Pharmaceutical Industries Limited (unrelated exporter). Following the receipt of response, a deficiency letter was sent to the producer asking them to address the deficiencies. The producer has addressed these deficiencies. It is noted that during the POI, M/s CSPC Weisheng Pharmaceutical (Shijiazhuang) Co., Ltd. has exported \*\*\* MT of subject goods to India directly and another \*\*\* MT through the unrelated exporter. The CIF export price has been determined on the basis of the questionnaire response filed. The CIF export price has been adjusted towards ocean freight, inland transportation, port and other related expenses, bank charges, details of which were examined through remote cross check/desk verification to the extent feasible. Accordingly, net export price for the PUC at ex-factory level for M/s M/s CSPC Weisheng Pharmaceutical (Shijiazhuang) Co., Ltd. has been determined, and is shown in the dumping margin table.

**Export Price for all other producers/exporters from China PR**

53. The export price for other non-cooperating exporters from China PR has been determined as per facts available, taking into account the data of the co-operating exporters from China and DGCI&S import data.

**i. Dumping Margin**

54. On the basis of normal value and export price, as determined above, the dumping margin for producers/exporters from China PR has been determined and the same is provided in the table below:

Producer	Normal Value (US\$/Kg)	Export Price (US\$/Kg)	Dumping Margin (US\$/Kg)	Dumping Margin %	Dumping Margin Range
M/s CSPC Weisheng Pharmaceutical (Shijiazhuang) Co., Ltd.	***	***	***	***	110-120
Others	***	***	***	***	120-130

**H. INJURY AND CAUSAL LINK****H.1 Views of the domestic industry**

55. The submissions made by domestic industry with regard to injury and causal link are summarized as follows:

- a. Imports from subject country had increased over the injury period, with a slight decline in the imports during the POI.
- b. The imports in relation to production had increased over the injury period, with a slight decline in the POI and imports in relation to consumption has increased till 2017-18 and declined thereafter till POI.
- c. The demand for the subject goods had continuously increased throughout the injury period, with a slight decline in the imports during the POI.
- d. Market share of imports from subject country has declined whereas market share of other countries has increased over the injury period.
- e. The landed price of imports is significantly below the selling price of the domestic industry. The imports are undercutting the prices of the domestic industry.
- f. The imports are significantly depressing the prices of the product in the market.
- g. The production of the domestic industry increased till 2018-19 with addition of capacities in 2017-18, but the production declined in the POI.
- h. The domestic sales increased till 2018-19, however, the same declined in the POI.
- i. The capacity utilization increased till 2018-19 however, the same declined in the POI.
- j. The market share of the domestic industry had decreased over the injury period; however, the market share of subject imports from subject country has increased in 2018-19 which slightly declined in the POI, and the imports from other countries have increased over the injury period.
- k. The profitability of the domestic industry increased till 2018-19, followed by a sharp decline in the POI. Return on investment and cash profits have followed the same trend as that of profitability. This profitability has now declined due to the steep decline in the import prices.
- l. Inventories with the domestic industry were declining until 2017-18 but have increased thereafter.
- m. Productivity per day of the domestic industry has increased throughout the injury period.
- n. Employment and wages have shown an overall improvement in the proposed injury period.
- o. Domestic industry has registered an overall growth both in terms of volume and price parameters, with a decline in the POI. Various parameters, i.e., sales volume, sales value, prices, production volume, capacity utilization, profits, cash profits, ROI showed positive growth until the 2018-19, and decline in the POI. The growth in profits, cash profits and ROI was substantially negative in the POI.
- p. The performance of the domestic industry deteriorated in the present POI even when anti-dumping duty is in place.
- q. Even if NIP is not higher than NSR, the same does not mean absence of injury to the DI.

**H.2 Views of the other interested parties**

56. The submissions made by other interested parties with regard to injury and causal link are summarized as follows:



- a. The POI considered was already having ADD in existence and therefore there was no occasion of injury being caused. The entire exercise appears to be mechanical in nature and appears to have been initiated with the object to protect domestic industry *per se* and rather extend protection to the applicant to create monopoly in their favour. Thus, there is no basis for initiation of present investigation.
- b. The entire initiation is based on the premise of likelihood of injury. The actual and real data, which if produced to the Authority, the same would give a completely contrary picture.
- c. The evidence provided regarding huge surplus production capacities of Chinese producers is without specifying whether the supply capacity is for exports or for domestic consumption or aimed at India. In the absence of positive evidence, the claim of the applicant is not liable to be accepted.
- d. No information regarding export price of the applicant has been provided. Exports by all Domestic Industries need to be investigated.
- e. Imports from other countries need to be investigated.
- f. Product is in very high demand. There is absolutely no need to justify this.
- g. Annual reports, Audit Reports & ITR of all Domestic Industries need to be investigated.
- h. Minutes of all Domestic Industries need to be investigated.
- i. Profitability to BSE & NSE by all the Domestic Industries need to be investigated. The applicant is making gross profits, as exhibited by data as well, and further is not facing any price suppression. Any fall in ROI and net profits is attributable to the increase in extraordinary expenses rather than allegedly dumped import.
- j. 2KGA constitutes 50 percent of the cost of production of Vitamin C. This is one of the reasons why the landed value of the imports from China is showing a decline.
- k. There exists significant demand supply gap.
- l. Chinese manufacturers are more competitive, a fact also admitted by the domestic manufacturers. If the Chinese exporters wanted to capture the Indian market, they could have substantially increased the prices of the raw material 2KGA which would have resulted in bigger injury to the Indian bulk drug manufacturers. In such circumstances, since there is no domestic manufacturer for 2KGA, the option of initiating an AD investigation would also not be available.
- m. There is no evidence available with the Authority and the domestic industry that there is any dumping, that the dumping is causing injury and therefore there was no occasion to initiate investigation.
- n. According to the production technics in India, the cost of producing “Vitamin C” is two times higher than the cost of producing 2 KGA. Due to the volatility in the prices of the raw material (2KGA), the domestic manufacturers have suffered losses.
- o. Chinese exporters are more cost competitive than Indian domestic manufacturers.
- p. The data provided neither establishes that it has suffered material injury nor that there is a case of recurrence of material injury upon revocation of the duty.
- q. There is no absolute increase in the volume of imports from China PR.
- r. Capacity and production have increased. No decline in capacity utilization. The domestic sales volume and value have also increased. Market share has also increased. The domestic industry is showing a positive growth.
- s. There is no injury as there was no decline in market share, Profits, Return on Capital Employed (ROCE) and cash profit.
- t. There is no causal link between the imports and the claim of material injury. The injury data has been provided only for the applicant and cannot be relied upon. The applicant should have provided injury data for the other domestic producers.

- u. New players would not enter a market that is suffering injury or is not considered profitable. The extent of injury caused by the significant increase in expenses of the applicant must be segregated from the any injurious effect caused by imports.
- v. There is no price undercutting. No price suppression or depression has been caused by imports as there has been a decrease in the selling price as well as the cost of production due to decrease in the price of 2KGA. Therefore, the imports have not depressed prices to a significant degree or prevented price increase, which otherwise would have occurred.
- w. Selling price of “Vitamin C” has been regulated by the National Pharmaceutical Pricing Authority (NPPA) and any upward trend in prices has been subject to a ceiling. The selling price of the applicant has been above its cost of production and the applicant should not be suffering any losses.
- x. Other domestic producers have increased their selling prices in recent period.
- y. Certain expenses such as depreciation, wages and interest were responsible for any losses rather than imports. The decline in the profits and return on investment is linked to the increase in the aforesaid expenses of the applicant.
- z. The applicant appears to be incurring a gross profit but due to increase in investments, there has been a decline in its cash profits.
- aa. International prices of the major raw material, i.e., Methanol, declined sharply by 30% during the POI. Therefore, the import prices and selling prices of DI for PUC have declined.
- bb. There has been an enormous decline in the alleged imports, both in absolute and relative terms, during the POI as compared to the preceding year.
- cc. There has been fluctuations in the imported volume and domestic sales which can be attributed to the decline in market share.
- dd. Authority should confirm that the NIP is higher than NSR. Since the range of injury margin and price undercutting is identical, the two essential components for this investigation may be the same or NSR may be higher has the NIP. Authority should terminate the investigation if NIP is higher than NSR as per its consistent practice.

### **H.3 Examination by the Authority**

57. Rule 11 of Antidumping Rules read with Annexure II provides that an injury determination shall involve examination of factors that may indicate injury to the domestic industry, “... *taking into account all relevant facts, including the volume of dumped imports, their effect on prices in the domestic market for like articles and the consequent effect of such imports on domestic producers of such articles...*”. In considering the effect of the dumped imports on prices, it is considered necessary to examine whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like article in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree. For the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry in India, indices having a bearing on the state of the industry such as production, capacity utilization, sales volume, inventory, profitability, net sales realization, the magnitude and margin of dumping, etc. have been considered in accordance with Annexure II of the Rules.
58. The Authority has taken note of various submissions made by the Domestic Industry and other interested parties on injury and causal link and has analyzed the same considering the facts available on record and applicable laws. The injury analysis undertaken ipso facto addresses submissions made by the domestic industry and other interested parties.
59. As regards to the performance of the domestic producers in their annual report, audit reports, ITR and profitability to BSE & NSE, it is noted that the applicant is a multi-product company having a number of products. Profits reported in the aforementioned documents are not reflective of the performance of the domestic industry for the product under consideration. In any case, the Authority has made present determination based on the verified information.
60. With regard to the submission made by the opposing interested parties that net selling price (NSR) is

higher than the Non injurious price (NIP), therefore there is no injury to the domestic industry, the Authority notes that there is no legal provision that the Authority should compare the non-injurious price with net sales realization in order to determine the price effect.

61. The Authority notes that the product under consideration was attracting antidumping duty @ US\$ 3.74/Kg imposed vide customs notification no. 38/2015-Customs (ADD) dated 6th August, 2015 which was in force till 5<sup>th</sup> August 2020. Thus, antidumping duty was in force almost during entirety of the injury period. The Authority considers that the fact of existing antidumping duty during the relevant period is required to be considered for the purpose of injury determination.

### **H.3.1 Volume effect of the dumped imports**

#### **a. Assessment of demand/apparent consumption**

62. For the purpose of the present investigation, the Authority has taken into consideration the demand or apparent consumption of the product in India as the sum of domestic sales of the Indian Producers and imports from all sources.

Particulars	UoM	2016-17	2017-18	2018-19	POI
Domestic Industry Sales	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	112	113	100
Sales of Other Producers	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	107	102	105
Total imports from the subject country	MT	783	1288	1171	868
Trend	Indexed	100	165	150	111
Imports from other countries	MT	65	84	253	217
Trend	Indexed	100	130	390	335
Total Demand/Consumption	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	123	124	109

63. It is seen that whereas the demand of the product under consideration increased till 2018-19, it declined in the period of investigation. However, as compared to the base year, the demand for the subject goods increased in the period of investigation.

#### **b. Import volumes from subject country**

64. With regard to the volume of the dumped imports, the Authority is required to consider whether there has been a significant increase in dumped imports from subject country, either in absolute terms or relative to production or consumption in India. For the purpose of injury analysis, the Authority has relied on the transaction-wise import data procured from DGCI&S. The volume of imports of the subject goods from the subject country has been analyzed as under:

Particulars	UoM	2016-17	2017-18	2018-19	POI
Total imports from the subject country	MT	783	1288	1171	868
Trend	Indexed	100	165	150	111
Imports from other countries	MT	65	84	253	217
Trend	Indexed	100	130	390	335
<b>Subject imports from China in relation to</b>					
Demand	%	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	132	120	100
Indian Production	%	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	150	133	100

65. It is noted that:

- a. The volume of dumped imports increased till 2017-18 and declined thereafter till the period of investigation. As compared to the base year, the imports, however, increased in the period of investigation.
- b. The imports in relation to domestic production and consumption have shown the similar trends. Whereas the imports increased till 2017-18 in relation to production and consumption in India, it declined thereafter till the period of investigation.

### **Price effect of the dumped imports**

66. In terms of Annexure II (ii) of the Rules, with regard to the effect of the dumped imports on prices, the Authority is required to consider whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like product in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree.

#### **a. Price undercutting**

67. For the purpose of price undercutting analysis, the net selling price of the domestic industry has been compared with the landed value of imports from the subject country. While computing the net selling price of the domestic industry, all taxes, rebates, discounts and commissions have been deducted and sales realization at ex-works level has been considered for comparison with the landed value of the dumped imports. Accordingly, the undercutting effects of the dumped imports from the subject country work out as follows:

Particulars	Units	China PR			
		2016-17	2017-18	2018-19	POI
Landed price of imports	Rs/Kg	318	586	433	256
Net Selling Price	Rs/Kg	***	***	***	***
Price Undercutting	Rs/Kg	***	***	***	***
	%	***	***	***	***
	Range	70-80%	40-50%	65-75%	100-110%

68. It is seen that the landed prices of the subject goods were materially below the selling price of the domestic industry. Further selling price increased in 2017-18, with increase in the landed price of imports. However, the selling price declined thereafter with the decline in the landed price of imports. Price undercutting is positive and significant throughout the injury period.

#### **b. Price suppression and depression**

69. In order to determine whether the dumped imports are depressing the domestic prices and whether the effect of such imports is to suppress prices to a significant degree or prevent price increases which otherwise would have occurred in normal course, the changes in the costs and prices over the injury period, are compared as below:

Particulars	Unit	2016-17	2017-18	2018-19	POI
Cost of Sales	Rs/Kg	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	154	125	94
Selling Price	Rs/Kg	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	151	132	94
Landed Price-China	Rs/Kg	318	586	433	256
Trend	Indexed	100	184	136	81

70. It is seen that the landed price of imports from subject country was below the cost of sales as well as selling price of the domestic industry throughout the injury period. It is also noted that whereas the domestic industry was able to increase its price more than the cost increase in 2017-18 and reduced the price less than the cost decline in 2018-19, during the period of investigation, the domestic industry was forced to reduce the price more than the cost decline.
71. It is also noted that the landed price of imports is significantly below the cost of sales. Further, the difference between the landed price of imports and cost of sales increased over the injury period and was at its highest in the POI. Thus, the domestic industry has suffered price suppression during the injury period.
72. It is thus noted that the imports are depressing the prices of the domestic industry.

### **H.3.2 Economic parameters of the domestic industry**

73. Annexure II to the Rules requires that the determination of injury shall involve an objective examination of the consequent impact of dumped imports on domestic producers of such products. With regard to consequent impact of dumped imports on domestic producers of such products, the Rules further provide that the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry should include an objective and unbiased evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry, including actual and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilization of capacity; factors affecting domestic prices, the magnitude of the margin of dumping; actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital investments. The various injury parameters relating to the domestic industry are discussed herein below.

#### **a. Production, capacity, sales and capacity utilization**

74. Capacity, production, sales and capacity utilization of the domestic industry over the injury period is as follows:

Particulars	UOM	2016-17	2017-18	2018-19	POI
Capacity	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	109	109	109
Total Production	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	109	113	113
Capacity Utilization	%	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	100	103	103
Domestic Sales	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	112	113	100
Export Sales	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	100	36	27
Total Sales	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	112	112	99

75. It is seen that:

- Domestic industry increased its capacities in the year 2017-18.
- The production and capacity utilization of the domestic industry increased.
- The domestic sales increased till 2018-19 and thereafter declined in the POI.

#### **b. Market Share in Demand**

76. Market share of the domestic industry and of imports was as shown in table below:

Particulars	UoM	2016-17	2017-18	2018-19	POI
Domestic Industry Sales	%	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	91	91	91
Sales of Other Producers	%	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	87	82	95
Imports from the subject country	%	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	132	120	100
Other countries	%	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	100	300	300
<b>Total</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

77. It is seen that while the market share of subject imports has increased in 2017-18 and declined in the period of investigation. However, the product was subjected to antidumping duty throughout the injury period, still the market share of the of the subject imports is quite significant. The market share of domestic sales declined in period of investigation as compared to the base year.

#### c. Inventories

78. Inventory position with the domestic industry over the injury period is given in the table below:

Parameters	Unit	2016-17	2017-18	2018-19	POI
Opening Stock	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	35	4	22
Closing Stock	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	13	63	975
Average Inventory	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	27	20	273

79. It is seen that the inventories with the domestic industry declined till 2018-19 and increased in POI.

#### d. Profitability, return on investment and cash profits

80. Profitability, return on investment and cash profits of the domestic industry over the injury period is given in the table below:

Parameters	Unit	2016-17	2017-18	2018-19	POI
Selling price	Rs/Kg	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	151	132	94
Cost	Rs/Kg	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	154	125	94
Profit/ loss	Rs/Kg	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	123	189	90
Profit/ loss	Rs Lacs	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	137	213	91
Profit/ loss before Interest and Tax	Rs Lacs	***	***	***	***

Trend	Indexed	100	126	178	77
Cash Profit	Rs. Lacs	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	122	179	92
ROCE	%	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	71	127	42

81. It is seen that

- The profitability of the domestic industry increased till 2018-19 and declined during period of investigation. The profitability shows decline during period of investigation as compared to base year.
- Return on investment and cash profits have followed the same trend as that of profitability.
- The domestic industry has submitted that the manufacturing facilities of the domestic industry are largely depreciated and therefore the ROI is not reflective and representative.

**e. Employment, productivity and wages**

82. Performance of the domestic industry with regard to employment, productivity and wages over the injury period was as follows.

Employment, Productivity and Wages					
Particulars	UoM	2016-17	2017-18	2018-19	POI
Employee	Nos.	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	106	121	126
Productivity per employee	MT/Nos	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	107	93	86
Wages	₹ Lacs	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	108	146	124

83. It is seen that

- The number of employees has shown improvement over the injury period.
- Productivity have declined over the injury period.
- Wages paid have increased till 2018-19 and then declined in the POI.

**d. Growth**

84. Growth of the domestic industry with regard to production, domestic sales, cost of sales, selling price, profits and cash profits have shown decline over the injury period. However, return on investment showed negative growth, especially during the period of investigation.

Parameters	Unit	2016-17	2017-18	2018-19	POI
Production (MT)	%		9%	3%	0%
Domestic Sales Volume (MT)	%		12%	1%	-11%
Cost of Sales (Rs/Kg)	%		54%	-19%	-25%
Selling Price (Rs/Kg)	%		51%	-12%	-29%
Profit/ Loss (Rs/Kg)	%		22%	55%	-52%
Cash Profit	%		22%	47%	-49%
ROI	%		-29%	79%	-67%

e. **Ability to raise capital investments**

85. The Authority notes that domestic industry is having reasonably good capacity utilization. However, performance of the domestic industry has declined in the POI.

f. **Magnitude of dumping**

86. It is noted that the subject goods are being dumped into India and the dumping margin is positive and significant.

g. **Factors affecting domestic prices**

87. The examination of the import prices from the subject country, change in the cost structure, competition in the domestic market, factors other than dumped imports that might be affecting the prices of the domestic industry in the domestic market shows that the landed value of imported material from subject country is the benchmark for the selling price of the domestic industry. In fact, the domestic industry is matching the price of imports, and has not increased its prices in proportion to the increase in costs. This shows that the landed prices of subject goods from subject countries are affecting the prices of the domestic industry.

h. **Analysis on injury**

88. The Authority has taken note of various submissions made by the Domestic Industry and other Interested parties on injury and causal link, and has analyzed the same considering the facts available on record and applicable laws. The injury analysis made in the preceding paras ipso facto addresses submissions made by the domestic industry and other interested parties.

89. The examination of the imports of the subject product and performance of domestic industry shows the volume of imports has increased in absolute terms as well as in relation to production and demand in India over the injury period during injury period, even though it has shown a decline in the POI as compared to preceding year. The imports are undercutting the prices of the domestic industry, and margin of price undercutting is significant. It is also noted that imports of subject goods from subject country have resulted in price depression in the market, and domestic industry has also suffered price suppression on account of dumped imports of subject goods from subject country.

90. While the capacity of the domestic industry has increased over the period, the sales of the domestic industry has declined in the POI when compared with the preceding year. The market share of subject imports has increased, while the share of domestic industry has declined from the base year. The domestic industry has suffered a decline in its profits, and cash profit in the period of investigation. The return on capital employed of the domestic industry has declined significantly in the POI.

**Injury Margin/Price Underselling**

91. The Authority has determined Non-Injurious Price (NIP) for the domestic industry on the basis of principles laid down in the Rules read with Annexure III, as amended. The non-injurious price of the product under consideration has been determined by adopting the information/data relating to the cost of production provided by the domestic industry and duly certified by the practicing cost accountant for the period of investigation. The non-injurious price has been considered for comparing the landed price from the subject country for calculating injury margin. For determining the non-injurious price, the best utilization of the raw materials by the domestic industry over the injury period has been considered. The same treatment has been carried out with the utilities. The best utilization of production capacity over the injury period has been considered. It is ensured that no extraordinary or non-recurring expenses were charged to the cost of production. A reasonable return (pre-tax @ 22%) on average capital employed (i.e. average net fixed assets plus average working capital) for the product under consideration was allowed as pre-tax profit to arrive at the non-injurious price as prescribed in Annexure III of the Rules and being followed as per consistent practice of the Authority.

92. For all the non-cooperative producers/exporters from the subject countries, the Authority has determined the landed price based on facts available.

93. Based on the landed price and non-injurious price determined as above, the injury margin for producers/exporters has been determined by the Authority and the same is provided in the table below:



Producer	Non-Injurious Price (US\$/MT)	Landed Value (US\$/MT)	Injury Margin US\$/MT	Injury Margin (%)	Injury Margin % (Range)
M/s CSPC Weisheng Pharmaceutical (Shijiazhuang) Co., Ltd.	***	***	***	***	90-100
Others	***	***	***	***	120-130

## **I. CAUSAL LINK AND NON-ATTRIBUTION ANALYSIS**

94. As per the Rules, the Authority, inter alia, is required to examine any known factors other than the dumped imports which at the same time are injuring the domestic industry, so that the injury caused by these other factors may not be attributed to the dumped imports. Factors which may be relevant in this respect include, inter alia, the volume and prices of imports not sold at dumped prices, contraction in demand or changes in the patterns of consumption, trade restrictive practices of and competition between the foreign and domestic producers, developments in technology and the export performance and the productivity of the domestic industry. The Authority examined whether known factors other than dumped imports could have contributed to the injury to the domestic industry.

95. The Authority notes that the Rules recognize that dumping need not be the sole cause of injury to the domestic industry. There may be other factors which might have at the same time caused injury to the domestic industry. However, in a situation where other factors have caused injury to the domestic industry, the Authority is required to ascertain whether injury caused due to other factors is so significant that the same outweighs the injury suffered by the domestic industry due to dumped imports.

### **a. Imports from other sources**

96. Imports from other countries are either at de-minimus levels or the import prices are higher. It is, therefore, seen that the imports from other countries have not caused injury to the domestic industry.

### **b. Contraction in demand**

97. The demand of the product under consideration has increased over the injury period with a decline in the POI. Even when the demand declined in the POI, the same was higher than base year. Further, as the demand for the product declined, there was a steep decline in the import price, far beyond the decline in the costs. Resultantly, the domestic industry was forced to reduce the prices.

### **c. Changes in the pattern of consumption**

98. There is no evidence of any change in the pattern of consumption with regard to the product under consideration. Therefore, changes in the pattern of consumption cannot be considered to have caused injury to the Domestic Industry.

### **d. Trade restrictive practices of and competition between the foreign and domestic producers**

99. There is no trade restrictive practice, which could have contributed to the injury to the domestic industry.

### **e. Developments in technology**

100. None of the interested parties have furnished any evidence to demonstrate significant changes in the technology that could have caused injury to the domestic industry.

### **f. Export performance**

101. The injury information examined hereinabove relates only to the performance of the domestic industry in terms of its domestic market. Thus, the injury suffered cannot be attributed to the export performance of the domestic industry.

### **g. Performance of other products being produced and sold by the domestic industry**

102. The Authority has only considered data relating only to the performance of the subject goods.

Therefore, performance of other products produced and sold are not a possible cause of the injury to the domestic industry.

## **J. EXAMINATION OF INJURY AND CAUSAL LINK**

103. It is thus noted that other known factors listed under the Rules do not show that the domestic industry could have suffered injury due to these other factors. The Authority has also examined whether the dumping of the product has caused injury to the domestic industry. The following parameters show that material injury to the domestic industry has been caused by dumped imports:

- a. Imports of the subject goods from subject country have increased in absolute terms as well as in relation to production and consumption.
- b. The market share of subject imports has remained constant and significant during injury period, while the share of domestic industry has declined over the same period.
- c. The dumped imports are undercutting the prices of the domestic industry. Further, the price undercutting has led to suppressing and depressing effects on the prices of the product in the market.
- d. The suppressing and effecting effects caused by the dumped imports has adversely impacted the profits, cash profits and return on capital employed of the domestic industry.

## **K. POST DISCLOSURE COMMENTS AND EXAMINATION BY AUTHORITY**

### **K.1 Views of the domestic industry**

104. The following are the post-disclosure submissions made by the domestic industry:

- a. While the dumping margin for all parties are so comparable, the injury margin is so incomparable.
- b. Considering the low volume of individual import transactions, and the fact that shipments are by air, it is obvious that the complete transactions are not disclosed by the exporters to the Authority. These transactions are not normal business transactions. The Authority is requested to seek relevant documents from JNPT port. Since the product is a drug, any producer is required to obtain a licence from the Drug Controller and is required to file document showing name of the producer even for the goods purchased from trader.
- c. M/s Shandong Luwei Pharmaceutical has been exporting at such a low price all alone seems that it has reported only three air transactions during POI and at such high price. There is a huge difference in the freight charges via sea route and via air freight.
- d. We request the Authority re-consider injury margin after removing air freight and considering only sea freight payable.
- e. M/s Shandong Luwei Pharmaceutical has not reported sales made through M/s Sinoright International Trade Co. There is no response accompanied with producer's response. Only producer has filed response. This further shows suppression of facts.
- f. M/s Shandong Luwei Pharmaceutical has significantly suppressed the facts and filed false information before the Authority.
- g. There is no viable substitute for the product under consideration. The shelf life of the product sold by domestic industry is 4 years whereas the foreign producers provide 3 years of shelf life. Packing of product under consideration manufactured by domestic industry is similar to that of exporters.
- h. The imposition of anti-dumping measure would be in the interests of the domestic manufacturers, arresting decline in the performance of the industry and will redress the injury suffered. The industry provides employment to more than 5,000 individuals directly, and to more than 50,000 individuals indirectly, the livelihood of such individuals would be impacted. Imposition of duty would encourage production of intermediate in India as well.
- i. The imposition of duty will not result in any significant adverse impact on the eventual end product, and it will be in the larger public interest. There is no evidence of adverse impact on users, despite the duties having been in force since 2010. The price of Vitamin C formulation

used in medicines will not increase since its price is controlled and regulated by the Government of India. Vitamin C falls under DPCO.

- j. Chinese producers were least concerned with the India's demand during peak COVID-19 period.
- k. The Indian industries already have sufficient capacities to cater 100% demand in India.
- l. The duty should be imposed as fixed amount, expressed in terms of US\$.

## **K.2 Views of the other interested parties**

105. The following post-disclosure submissions have been made by the other interested parties:

- a. No Duties should be recommended as Net Sales Realization is more than Non-Injurious Price of the applicant industry as mentioned in Para 57 of the disclosure statement.
- b. The Authority need to reduce the post FOB expenses like ocean freight, insurance, port charges, and any applicable duties like BCD, cess etc. from the cost/price of the applicant industry, as producers in China would not be incurring these expenses as they do not import raw material.
- c. The "Lesser Duty Rule" is mandatorily required to be followed by the Authority in all cases.
- d. Injury Assessment of the Authority is not only incorrect but also contrary to the requirement of the Rules as the Authority does not have sufficient data to reach to the conclusion that domestic producers of the subject goods have suffered injury.
- e. Since the other producers have not filed the data as per the Trade Notice No. 13/2018, their data could not be even used as supporters, as was done in the case of 6PPD [F. No. 6/34/2019- DGTR dated 9.1.2020]. None of the Indian producers has applied for the sunset review investigation, proves that there was neither any injury nor their likelihood of injury to the domestic producers.
- f. Owing to COVID-19, the demand for these products has increased by six to eight times. For instance, the demand of these products for Abbott has increased by more than 400%. The Domestic Industries cannot cater to the demand of the subject goods in India. Since China and Singapore are the main exporters of Vitamin C into India, any anti-dumping duty on imports of Vitamin- C would adversely affect the users of the subject goods.
- g. Bajaj Healthcare Limited has also approached the other suppliers effectively forming a cartel so that they can maintain the increased prices of Ascorbic Acid and Sodium Ascorbate.
- h. The sudden increase in demand, coupled with shortage of supply has led to an acute shortage of Vitamin C which is being sold at prices 5 to 8 times higher than the usual price.
- i. It would be extremely unfair to the public at large if any extra protection is extended which they have been enjoying for more than 22 years.
- j. The instant investigations are clearly based on incorrect premises, wrong information and are in breach of the settled legal provisions. Thus, we request the Authority to kindly terminate the investigation forthwith.
- k. The Authority, as per its consistent practice, may not accept any fresh evidence at this stage of the investigations. However, in the unlikely event of the Authority showing any unprecedented indulgence, all such documents/information may kindly be provided to us for our comments. Grant a fresh hearing after providing the information which cannot be kept as confidential or for which a meaningful summary is necessarily required to be provided in terms of Rule 8 of the Anti-dumping Rules.
- l. It should be expressly stated in the definition of PUC and below the duty table in the Final Findings that derivatives of Vitamin-C are not within the product scope.
- m. Since the duties on this product have been in force for last 22 years from China PR, the Authority must undertake a post POI analysis in this case to ascertain whether the situation demands any further imposition of anti-dumping measures on this product.

- n. Higher procurement cost of PUC severely constrains the continuing of operations of producing and selling the final drug formulations which are price capped by NPPA under the DPCO as the PUC is one of the basic raw materials for such final drug formulation.
- o. There has been a trend of user industry players to manufacture Food Supplement form of Vitamin C which are not subject to price restrictions like drug form. This has severely impacted and continues to impact the availability of Vitamin C at fair price to the public at large.
- p. Having provided all the required information in user questionnaire response, it is incorrect for the Authority to state that none of the interested parties provided information to show the impact of anti-dumping duties.
- q. Considering the nature of PUC involved and prevailing regulatory mechanism for price fixation, imposition of anti-dumping duty will have severe impact on the user industry and the availability of Vitamin C to public at large at fair prices.
- r. The subject imports have reduced drastically by 303 MT in the POI as compared to the immediate previous year 2018-19. There is a miniscule increase of 85 MT in the import volume when compared with the base year. However, such a negligible increase cannot be considered as 'significant' increase for the purpose of Annexure-II of AD rules.
- s. The data pertaining to CIF prices as furnished by the domestic industry has undergone a change multiple times and the Authority is requested to thoroughly verify the CIF prices of the imports.
- t. M/s CSPC Weisheng Pharmaceutical (Shijiazhuang) Co., Ltd has represented that there is an apparent inconsistency in the dumping margin and injury margin determined for CSPC and Shandong Luwei Pharmaceutical Co., Ltd. While the export price (FOB) of CSPC has been US\$3.10/Kg during the POI, the export price (FOB) of the other cooperating exporter is seen as US\$2.64/Kg in the same period. In view of the same, the Authority may cross check the injury margin determined for CSPC to avoid any calculation errors.
- u. Both landed price of imports and selling price of the DI have been fluctuating during the entire injury period and such significant price changes have been on account of wild movements in demand for the product at times.
- v. There is a sharp fall in import during the POI. The DI, however, registered highest profits in the previous 2 years when the import was highest, and the profits declined in the POI when the imports sharply declined during the POI. Thus, landed price alone was not the cause of fall in profits as alleged.

### **K.3 Examination by the Authority**

106. The Authority notes that most of the submissions by the domestic industry and other interested parties are repetitive in nature. These submissions have already been examined at appropriate places in this finding. Further, the Authority has examined additional relevant submissions of the interested parties as under
107. Post issuance of Disclosure statement to the interested parties, other Chinese producer i.e, M/s CSPC by referring export details as per China Customs, alleged that M/s Shandong Luwei Pharmaceutical Co Ltd. has not reported the complete/factual data on its exports to India hence, resulting in doubtfully lower margins. Further, the domestic industry has also filed similar comments by submitting bill of entry wise details of exports made by M/s Sinoright International Trade Co., Ltd. alleging that Shandong Luwei Pharmaceutical has also sold the subject goods to India during the POI through an unrelated company/trader in China i.e., M/s Sinoright International Trade Co., Ltd. Further, the domestic industry provided a document stating that Shandong Luwei Pharmaceutical has appointed Sinoright International Trade as its agent and the document clearly states that "*Shandong Luwei Pharmaceutical Co., Ltd, hereby authorize M/s Sinoright international Trade Co Ltd as the Exclusive Agent in India for the commercial activities, marketing and Sales for Ascorbic Acid*". Considering the vital facts involved, the Authority gave M/s Shandong Luwei Pharmaceutical Co Ltd. an opportunity to offer its comment on the above, to which the company responded that the agreement concerning Shandong Luwei Pharmaceutical appointing Sinoright International Trade as its agent was later revoked by the company. Further, the Authority called for bill of entry details including the

commercial invoices, packing list, certificate of origin etc., and Form-9 & 10 from the Office of JNCH and the Office of CDSCO. Since, PUC being bulk drug, Form-9 (Form of undertaking to accompany an application for an import License) is required to be submitted to get the Form-10 (Import License) issued. On the basis of the Form-9 submitted by the authorized agent of Shandong Luwei Pharmaceutical Co., Ltd, the Form-10 was issued by the CDSCO that permitted the imports of the PUC. On examining the same, it is concluded that Shandong Luwei Pharmaceutical Co., Ltd has not reported all the exports made to India and has not come clean on all transactions made to India. Therefore, the Authority has rejected the response filed by the company and has not determined individual margins for the company.

108. The Authority holds that no interested party has established that there are technically and commercially viable substitute for the product under consideration.
109. The interested parties have disputed existence of injury to domestic industry. The interested parties have pointed out at improvement in performance of the domestic industry in respect of few injury parameters. It is noted that the mere fact that the performance of the Domestic Industry has improved in respect of some parameters does not mean that the domestic industry has not suffered material injury. It is well established legal position that it is not necessary that performance of domestic industry should show deterioration in respect of each injury parameter, and improvement in some parameters does not imply absence of injury. So long as the performance of domestic industry shows deterioration in respect of some parameters and such deterioration outweighs positive developments in other parameters, it should be concluded that the domestic industry has suffered injury. In this regard, it is noted that the product was attracting antidumping duty over the injury period, the profits, ROI and cash profits of the domestic industry shows significant deterioration. It is also noted that landed price of imports is materially below the cost of production, selling price and non-injurious price of the domestic industry. Further, the landed price of the imports after adding antidumping duty was quite comparable to the selling price of the domestic industry. While imports declined in the POI as compared to the preceding year, the same were higher as compared to the base year, and increased significantly after cessation of the antidumping duty. Various parameters collectively and cumulatively show that the domestic industry has suffered injury.
110. As regards the contention that the other producers of the subject goods have not participated and are not suffering any injury or doing better, the Authority notes that these interested parties have provided no information showing that these other domestic producers are not suffering injury or their performance improved. The Authority cannot rely upon a mere conjecture with regard to performance of the other domestic producers. Further, the applicant constitutes domestic industry within the meaning of the Rules and cannot be deprived of an investigation merely because other domestic producers have not provided their injury data.
111. With regard to the submission made by the opposing interested parties that net selling price (NSR) is higher than the Non injurious price (NIP), therefore there is no injury to the domestic industry, the Authority reiterates that NIP in the present investigation has been determined in terms of Annexure III of the Anti-dumping Rules for the purpose of determination of injury margin. Further, the Authority notes that there is no legal provision that the Authority should compare the non-injurious price with net sales realization in order to determine the price effect. It is also noted that the landed price of imports has been consistently and materially below cost of sales, selling price and non-injurious price of the domestic industry.
112. With regard to issue of demand supply gap during the time of pandemic, the Authority notes that (a) the domestic producers have expanded their existing capacities, (b) as per information on record the domestic producers not only have the capacity much more than the existing demand in the country, but also will be able to cater to any foreseeable increase in demand, (c) the domestic industry has submitted that it has catered to increased demand during the Covid, (d) the other interested parties have not established with data the increase in demand due to Covid claimed by them. The domestic industry has submitted that the increase in demand was much lower.
113. As regards the argument of the interested parties that imposition of anti-dumping duty will have adverse effect on the food supplements, the Authority notes that the objective of imposition of anti-dumping measures is to create a level playing field for the domestic industry vis-à-vis the unfair trade practice of dumping. Further, the domestic industry provided calculations showing that cost on

account of the product in food supplements is quite low. Further, the product was attracting antidumping duty not only over the current injury period, but also over past few years, and there is no evidence provided by any interested party with regard to possible adverse effect of the antidumping duty in force. The interested parties have not shown that the cost of these products had declined materially after the previous antidumping duty on the product ceased.

114. The Authority notes, in general, that the imposition of anti-dumping duty may have a cost push effect on the prices of end products. Nevertheless, fair competition in the Indian market will not be reduced by the anti-dumping duties, particularly if the levy of the anti-dumping duty is restricted to an amount necessary to redress the injury caused to the domestic industry. On the contrary, imposition of the antidumping duties would remove the unfair advantages gained by the dumping practices, would prevent the decline of the domestic industry and help maintain availability of wider choice to the users/consumers of the subject goods. Therefore, the arguments that imposition of anti-dumping duty would have adverse effect on the end-users/consumer are without any basis.
115. With regard to the contention of interested parties of data pertaining to CIF prices as furnished by the domestic industry has undergone changes, the Authority has verified the information submitted and adopted the same.

## **L. INDIAN INDUSTRY'S INTEREST AND OTHER ISSUES**

### **L.1.Submissions by other interested parties**

116. The submissions made by other interested parties with regard to Indian industry's interest are summarized as follows:

- a. The product under consideration is an essential drug. To enjoy the monopolistic privileges, the Domestic Industry has undermined the importance and necessity of the subject goods in the country.
- b. By imposing anti-dumping duties on an essential drug like Vitamin C, which also serves other benefits to the society, the claim of the industry would tantamount to a disservice to the country by inflating the prices of a product that is of vital importance, especially in the present times.
- c. The supporting producers along with the petitioner formed the cartel and hiked the prices in tandem. Thus, the domestic industry is engaged in price rigging at the cost of health of general public in the middle of global pandemic.
- d. It would not be in public interest to impose a duty on imports of PUC which is a key API for manufacture of Vitamin C drug which could save the lives of people of the country in Covid-19 pandemic.
- e. The Authority must also consider the regulatory framework of Vitamin C finished product and its impact on the patient/ end consumer.
- f. In the long run, the end consumers could be left with only the option of FSSAI category Vitamin C which are not subject to pricing restrictions and may not cater to patients' requirement of therapeutic dosage of 500mg.
- g. From April 2020 to August 2020, the domestic industry has increased the prices of PUC by more than 60% without any commensurate increase in their cost of production thereby resorting to profiteering at the cost of suffering public in the COVID-19 pandemic situation given the fact that Vitamin C finished product was in extremely high demand as a vital immunity booster.
- h. The Vitamin-C tablet is generally taken to boost immunity especially during the ongoing Covid-19 pandemic. Thus, imposition of anti- dumping duty will have an adverse impact on ability to manufacture and maintain a consistent supply of tablets and may ultimately impact public interest.
- i. Re-imposition of anti- dumping duty on imports of PUC will result in monopoly of the domestic industry and will empower them continue the price increases to the detriment of manufacturers of the finished formulations of Vitamin C, as well as of the public and consumers at large, more so in such a critical period when the country is fighting the pandemic. It will make selected Indian "Vitamin C" manufactures gain excessive profit, but harm the benefit of India pharmaceutical

enterprises, food enterprises and beverage enterprises, not to mention about the plight of the consumers.

- j. An examination of true demand supply situation of this product in India may be done before proceeding further in this matter so that the general public is not deprived of Vitamin C tablets in India.
- k. Anti-dumping will increase the price of this medicine can lead to high mortality rate. It will spoil India's name in front of the World.
- l. In case ADD is imposed, the domestic industry is likely to increase its price to the tune of ADD hence both imported as well as products produced in India will become costlier and the consumers will have to bear the cost of higher price.

## **L.2 Submissions made by Domestic Industry**

117. The submissions made by domestic industry with regard to Indian industry's interest are summarized as follows:

- a. It is producers/exporters own argument that the ADD was in place for such a long period. While the present investigation is a fresh investigation, the product was attracting ADD for quite some time. No adverse effect of the ADD could be established by any party.
- b. Even when duty has been in place, there was neither a shortage nor unbearable price of the product, nor significant adverse impact on the consumers. Evidently, the interested parties are resorting to misstatements and unsubstantiated claims.
- c. The domestic producers will not unduly increase their prices due to market forces and high competition and have stood upfront at this time of crises to have an uninterrupted supply of medicines to the peoples of India. Further, this will lead to continued availability of multiple domestic sources for the users, at reasonable prices.
- d. Even after imposition of duties, free, fair and reasonable competition will prevail in the market, thereby ensuring that the imposition will be in the larger public interest.
- e. The imposition of duty will protect the domestic industry against dumping from the subject country, provide a level playing field and address the decline of the domestic industry's performance.
- f. Anti-dumping duty is not a protection to the industry, but rather a means of correction of prices to fair levels. It would not restrict imports from the subject country in any way and would not affect the availability of the product to the consumers.
- g. The exporters/producers should confine themselves to whether there is dumping. Such public interest factors should not bother foreign producers. The domestic industry is responsible and responsive.
- h. The imports from China have increased in the most recent period and not when Covid-19 was at its peak. On the contrary, when Covid-19 was at its peak, the import volumes were low and the price was high.
- i. When the import price has declined, the import volumes have increased. It clearly shows that the Chinese producers were least concerned with the India's demand during Covid-19 period.
- j. Once their own internal requirements have been met, and Covid-19 was on way out, the Chinese producers woke up to the Covid-19 situation in India, reduced prices and dumped huge volumes. This also shows that the Chinese producers actions are different from statements.

## **L.3 Examination by the Authority**

118. The Authority considered whether imposition of ADD shall have adverse public interest. For the same, the Authority examined submissions made by various parties and whether the imposition of the anti-dumping duty on imports of the product would be against the larger public interest. This determination is based on consideration of information on record and interests of various parties, including domestic industry, importers and consumers of the product.

119. The Authority invited views from all interested parties at the stage of initiation. The Authority has prescribed a questionnaire for the consumers to provide relevant information, including possible effect of ADD on their operations. Only one consumer M/s Abbott Healthcare Private Limited provided relevant information. Further, the domestic industry submitted that while it is a producer of the PUC, it is also a consumer of the same and selling Vitamin-C formulation in the market, in the form of Vitamin-C tablets. The domestic industry has provided its own profitability for the Vitamin-C formulation, in the form of relevant extracts from the cost audit report of both PUC and formulation.
120. None of the interested parties have brought any evidence on record demonstrating that there was significant adverse effect of this ADD on the consumers, after imposition of ADD on Vitamin -C.
121. Further, there is no evidence that imposition of ADD over the long period had led to either shortage of the product, or significant increase in the prices of the product or downstream product.
122. The Authority notes that the price of Vitamin-C formulation is regulated by the Govt. and therefore the product cannot be sold at any price by any formulator. Since the price is regulated, the Authority considers that imposition of ADD cannot lead to significant increase in the price of eventual end product (Vitamin-C tablets) for the public at large.
123. The Authority notes that the PUC is being produced in the Country by four companies. As per the information on record, the combined Indian capacity is 3,600 MT in POI. As against this, the demand for the product was 3,477 MT in the POI and about 5,200 MT at the peak of Covid-19 pandemic. The domestic producers have also increased their capacities (5280 MT) looking at the increase in demand during the pandemic. Thus, there are enough capacities for the PUC in the Country.
124. The Authority examined whether the imposition of the duty on imports of the product under investigation would be against the larger public interest. This determination is based on consideration of information on record and interests of various parties, including domestic industry, importers and consumers of the product.
125. The Authority issued gazette notification inviting views from all interested parties, including importers, consumers and other interested parties. Authority also prescribed a questionnaire for the consumers to provide relevant information with regard to present investigations, including possible effect of ADD on their operations. The Authority sought information on, inter-alia, interchangeability of the product supplied by various suppliers from different countries, ability of the domestic industry to switch sources, effect of ADD on the consumers, factors that are likely to accelerate or delay the adjustment to the new situation caused by imposition of ADD, impact of imposing the present duty. The Authority notes that only one consumer filed questionnaire response. While the consumer reported that it was suffering financial losses in the vitamin C formulations, the domestic industry submitted detailed calculations showing its own information relating to production and sale of downstream product. While Abott claimed that it was suffering financial losses in the downstream product, the domestic industry submitted that it was significantly profitable. The domestic industry has also provided details of orders placed on it by a number of consumers and State Govt. authorities for procurement of significant volumes of Vitamin-C formulation. These orders were at a price materially below the price at which the domestic industry is selling Vitamin-C formulation in the market.
126. The consumers attended the oral hearing and made submissions, which have been taken into account. The authority notes that these interested parties have not shown with quantified information that imposition of ADD shall have significant adverse effect either on these consumers or at public at large.
127. The Authority recognizes that the imposition of anti-dumping duties might affect the price levels of the product in India. However, fair competition in the Indian market will not be reduced by the imposition of anti-dumping measures. On the contrary, imposition of anti-dumping measures would remove the unfair advantages gained by dumping practices, prevent the decline of the domestic industry and help maintain availability of wider choice to the consumers of the subject goods. The purpose of anti-dumping duties, in general, is to eliminate injury caused to the domestic industry by the unfair trade practices of dumping so as to re-establish a situation of open and fair competition in the Indian market, which is in the general interest of the country. Imposition of anti-dumping duties, therefore, would not affect the availability of the product to the consumers. The Authority notes that



the imposition of the anti-dumping measures would not restrict imports from the subject country in any way, and therefore, would not affect the availability of the product to the consumers.

128. The Authority has examined the questionnaire filed by the user of PUC. The Authority finds that the cost of PUC forms a minor portion of the total production costs of the final drug formulation. Hence, imposition of anti-dumping duty on PUC may not lead to a significant increase in the overall cost of production of the final drug. In any case, if the user industry is aggrieved with the final prices caps fixed by the drug regulator, they may approach the appropriate drug regulatory authority for necessary action.

#### **M. CONCLUSION**

129. After examining the submissions made by the interested parties and issues raised therein, and considering the facts available on record, the Authority concludes that:

- a. Considering the normal value and export price for subject goods, the dumping margins for the subject goods from the subject country have been determined, and the margins are significant.
- b. The domestic industry has suffered material injury. The examination of the imports of the subject product and the performance of the domestic industry shows that the volume of dumped imports from subject country increased till 2017-18 and declined till the POI. It, however, remains significant in absolute and in relative terms to production and consumption. Imports are entering the market at price below the level of selling price, non-injurious price and even cost of sales. The production and capacity utilization increased; however, the domestic sales have declined. It is noted that the inventory level has increased in the POI. The performance of the Domestic Industry has significantly deteriorated in respect of profits, cash profits and return on capital employed in the period of investigation.
- c. The material injury suffered by the domestic industry has been caused by the dumped imports.
- d. None of the users have provided relevant information. The interested parties have not established impact of ADD on the user industry with verifiable information. Non-imposition of anti-dumping duty will adversely impact the indigenous production of the product concerned and the fact that the impact of antidumping duty is miniscule to the consumers of the product under consideration, the Authority is of the view that the imposition of anti-dumping duty will be in public interest.
- e. In view of the argument of interested parties regard to long duration of duties, the Authority examined the volume and price of imports over the long period. It is seen that the imports from China have continued in significant volumes over the entire duration of duty, which establishes that the existence of ADD has not resulted in absence of imports from China in the market, or absence of competition to the domestic industry from Chinese imports. The past investigations conducted by the Authority further shows that the Authority has in successive investigations found that that domestic industry has suffered continued injury. The landed price of imports has been consistently and materially below cost of sales, selling price and non-injurious price of the domestic industry. Despite long duration of anti-dumping duties, barring one consumer, no other consumer has participated in the present investigations. The non-cooperation from the users shows that there is negligible impact on them. While the Authority normally does not examine the post POI situation, however, in view of argument of interested parties over long duration of duty and the fact that the current injury period was a period of duty, the Authority examined the volume and price of imports after cessation of anti-dumping duties. It is seen that whereas import prices have almost remained in the similar region, the volume of import has significantly increased indicating that if the duties are not imposed the imports would continue to rise and likely to materially injure the domestic industry.

#### **N. RECOMMENDATIONS**

130. The Authority notes that the investigation was initiated and notified to all interested parties and adequate opportunity was given to the Domestic Industry, exporters, importers and other interested parties to provide information on the aspects of dumping, injury and the causal link. Having initiated and conducted the investigation into dumping, injury and causal link in terms of the provisions laid down under the Rules, the Authority is of the view that imposition of Anti-Dumping is required to

offset dumping and injury. Therefore, Authority recommends imposition of anti-dumping duty on imports of subject goods from the subject country.

131. In terms of provision contained in Rule 4(d) & Rule 17(1) (b) of the Rules, the Authority recommends impositions of anti-dumping duty equal to lesser of margin of dumping and the margin of injury so as to remove the injury to the domestic industry. Accordingly, definitive anti-dumping duty equal to amount mentioned in column 7 of the duty table below is recommend to be imposed for five (5) years from the date of the Notification to be issued by the Central Government, on all imports of goods described at Column 3 of the duty table, originating in or exported from China PR.

Serial number	Tariff Heading	Description of Goods	Country of Origin/ or export	Country of Export	Producer	Duty Amount	Currency	Unit
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	29362700	Vitamin-C*	China PR	Any country including China PR	M/s CSPC Weisheng Pharmaceutical (Shijiazhuang) Co., Ltd	3.20	US\$	Kg
2	29362700	-do-	China PR	China PR	Any producer other than serial number 1	3.55	US\$	Kg
3	29362700	-do-	Any country other than China PR	China PR	Any	3.55	US\$	Kg

**\*Note:** The anti-dumping duty is applicable to Vitamin-C in all its form, also known as ascorbic acid, L-Xyloascorbic Acid, 3-oxo L-Gulofuranolactone (enol form), L-3 Ketothreohehexuronic Acid Lactone etc.,as described under entry number “867 of Merck Index. The anti-dumping duty is not applicable to derivatives of Vitamin C.

#### **O. FURTHER PROCEDURE**

132. An appeal against these findings after its acceptance by the Central Government shall lie before the Customs, Exercise and Service tax Appellate Tribunal in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 as amended in 1995 and Customs Tariff Rules, 1995.

ANANT SWARUP, Designated Authority